पेज-06

आज की जनधारा

सीधी और सच बात, साहस के साथ

डाक पंजीयन 29/2010-2012

वेब संस्करण
www.aajkijandhara.com
www.jandhara.in
Jandhara24x7
@AJandhara/Jandhara24/7
AajkiJandhara & Jandhara24x7
6232949114, 8959444440

RNI No.- 52143/91

वर्ष : 35, अंक : 161, रायपुर, मंगलवार 16 जून 2026

रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, मध्यप्रदेश से प्रकाशित epaper www.aajkijandhara.com | email:aajkijandhara@gmail.com | ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-1, वि.सं. 2083 | पृष्ठ : 12 | मो. : 9425203900, 9425243430 ❁❁❁ मूल्य: 2.00 रु.

अबूझमाड़ से नक्सली गए, अब जंगल भी जा रहे

हेमंत संचेति

नारायणपुर। बस्तर में लगभग पांच दशक तक नक्सलियों के प्रभाव में रहने वाला अबूझमाड़ अब विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ एक नया संकट भी तेजी से आकार ले रहा है। नक्सलियों के खौफ में जहां कभी सरकारी अमला पहुंच नहीं पाता था, वहीं अब उस प्रशासनिक शून्यता और अधूरे सरकारी रिकॉर्ड का फायदा उठाकर जंगलों पर कब्जे और अंधाधुंध वन कटाई का सिलसिला शुरू हो गया है।

अबूझमाड़ का बड़ा हिस्सा आज भी राजस्व और वन विभाग के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। वर्षों तक नक्सली प्रभाव के कारण न तो सीमांकन हो पाया और न ही जमीनों का व्यवस्थित सर्वे। अब जब सड़कें बन रही हैं और क्षेत्र बाहरी दुनिया से जुड़ रहा है, तब इसी अव्यवस्था का फायदा उठाकर कई स्थानों पर वन भूमि को साफ कर खेती और कब्जे की कोशिशें तेज हो गई हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार इरकभट्टी-कच्चापाल, तोके-कोड़ेनार-जटवर-बाड़ापेंदा, बालेबेड़ा-परियादि-काकुर, मसपुर-गारपा-होरादी-काँडुलपार-पांगुड़, कोड़कोरसा-आदनार, कुतुल-कोड़नार-धुरबेड़ा-आदिमपार-माटवाड़ा-धोबे तथा ओरछा-लंका मार्ग के आसपास बड़े पैमाने

रिकॉर्ड की खामियों का फायदा, हजारों एकड़ वन क्षेत्र पर खतरा

पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर जमीन को खेती योग्य बनाया जा रहा है।

सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब वन भूमि पर खुलेआम कब्जे और कटाई की शिकायतें सामने आ रही हैं, तब जिम्मेदार विभाग आखिर कर क्या रहे हैं? वन विभाग का तर्क है कि अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा अंसर्वेड क्षेत्र है और स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कार्रवाई में दिक्कत आती है। सवाल यह है कि यदि रिकॉर्ड अधूरे हैं तो उन्हें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? और जब तक रिकॉर्ड पूरे नहीं होते, तब तक जंगलों को कटने के लिए छोड़ दिया जाए?

विडंबना यह है कि यह पूरा इलाका प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप के प्रभाव वाले क्षेत्र में आता है। वन संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस विभाग पर है, उसी विभाग की मौजूदगी में जंगलों के तेजी से सिमटने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। विपक्ष इसे वन विभाग की उदासीनता और सरकार की विफलता बता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नक्सलवाद के दौर में जंगल सुरक्षित थे क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप सीमित था। अब सड़क पहुंचने के बाद वन भूमि पर दबाव बढ़ गया है। यदि समय रहते सीमांकन, सर्वे और निगरानी की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में अबूझमाड़ का विशाल वन क्षेत्र कब्जों और कटाई की भेंट चढ़ सकता है।

वन विभाग ने 'वन मित्र' समूहों के गठन और जनजागरूकता अभियान की बात कही है, लेकिन जमीन पर कटते पेड़ और बढ़ते कब्जे इन दावों की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जागरूकता अभियान उन लोगों को रोक पाएंगे जो वन भूमि को साफ कर स्थायी कब्जे की तैयारी में जुटे हैं?

नक्सलवाद से मुक्त होने के बाद अबूझमाड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब विकास नहीं, बल्कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की है। यदि प्रशासन ने जल्द स्पष्ट सीमांकन, कड़ी निगरानी और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो नक्सलमुक्त हुआ अबूझमाड़ आने वाले समय में वनविहीन अबूझमाड़ के रूप में पहचाना जा सकता है।

बिजली हुई महंगी, बढ़ेगा मासिक खर्च

30-50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, कमर्शियल यूजर्स-किसानों को भी झटका

● **1 जुलाई से लागू होगी नई दरें**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी।

वहीं कमर्शियल बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। आयोग ने बताया कि बिजली वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तावित 24 प्रतिशत वृद्धि को खारिज किया गया है। औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को

मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 6.42 रुपए प्रति केवीएएच तय किया गया है।

नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। आयोग के अनुसार, बिजली कंपनी को 1 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान बिजली दरों के हिसाब से उसे प्रति यूनिट सिर्फ 6.71 रुपए की आय हो रही है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने की प्रेस कान्फ्रेंस: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इस बात की घोषणा की। आयोग के सदस्य विनोद गनोदवाले और अजय सिंह प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली दर बढ़ाने को आयोग ने दी मंजूरी।

पावर कंपनी ने घाटे का दिया था हवाला : उल्लेखनीय है कि, पावर कंपनी ने करीब 6 हजार करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में 24 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया है। ऊर्जा विशेषज्ञों ने पहले ही बता दियाा था कि, यदि आयोग कंपनी के दावों को स्वीकार करता है तो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या बदला: घरेलू बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। स्थानीय निकायों के कार्यालयों को गैर-घरेलू श्रेणी से घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया। आवास बोर्ड कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल आपूर्ति को घरेलू टैरिफ का लाभ मिलेगा। घरेलू इस्तेमाल के अस्थायी कनेक्शनों पर 2 साल बाद सामान्य घरेलू टैरिफ लागू होगा। ग्रामीण, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के छात्रावासों को घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया।

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को झटका: गैर-घरेलू बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों को ऊर्जा शुल्क में 25 प्रतिशत छूट जारी।

किसानों को राहत और बढ़ी दरें: कृषि पंपों की बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। गैर-सब्सिडी कृषि पंपों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई। खेतों में पंप कनेक्शन के साथ 100 वॉट तक लाइट और पंखे की सुविधा यथावत रहेगी।

लो-वोल्टेज उपभोक्ताओं के लिए बड़े बदलाव: स्थायी कनेक्शन पर सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना शुल्क लगेगा। 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं पर टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 5 प्रतिशत छूट। ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ जारी

कोलकाता। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। ईडी अभिषेक से कैश-फॉर-स्कूल-जॉब स्कैम में पूछताछ की जा रही है। उन्हें 3 जून को नोटिस जारी कर 15 जून की दोपहर 12 बजे तक एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की चार्जशीट में अभिषेक का नाम है। इससे पहले रविवार को विधायकों के फर्जी साइन मामले में सीबीआई ने अभिषेक से 8 घंटे पूछताछ की थी। इस मामले में अभिषेक को फिर से 16 जून को सीबीआई के सामने पेश होना है।

अभिषेक के कालीघाट स्थित घर पर कोलकाता पुलिस ने 13 जून देर रात 3 बजे छापा मारा। पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची। पुलिस अधिकारी अंदर गए, जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला। छापे की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी तुरंत अभिषेक के घर आईं, थोड़ी देर रुकीं फिर वापस चली गईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी अभिषेक के पीए सुमित रॉय का पता लगाने के लिए की गई थी।

अभिजीत दीपके को जड़ दिया थप्पड़

● **जयपुर में कॉकरोच पार्टी के जुटान में हंगामा**

जयपुर। राजधानी के शहीद स्मारक पर सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद समर्थकों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया।

शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर जुटे थे प्रदर्शनकारी: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, अभिभावक और महिलाएं शामिल हुईं।

कंधों पर लेकर जा रहे थे, तभी मारा थप्पड़: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अभिजीत दीपके के शहीद स्मारक पहुंचने पर समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक उनके पास पहुंचा और थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद वहां मौजूद समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने स्थिति संभाली और आरोपी को अपने साथ ले गई।

प्रदर्शन के दौरान युवकों में भी हुई झड़प: थप्पड़ कांड से पहले भी प्रदर्शन स्थल ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

राम मंदिर चढ़ावा: चोरी की जांच के लिए एसआईटी पहुंची

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की जांच के लिए एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) सोमवार दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंची। सूत्रों के अनुसार, टीम सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय गई और वहां जांच शुरू की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी ली गई है। सूत्रों के मुताबिक, चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है, उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बैठाया गया है। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। टीम पहले उन आईपीएस अधिकारी से भी जानकारी लेगी, जो दिल्ली से गुप्त जांच के लिए आए थे। अयोध्या पहुंचने से पहले एसआईटी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। टीम में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरन एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन शामिल हैं। इधर, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा- अब मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच और सुधार दोनों पर काम किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों- लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13-17 जुलाई तक चलेगा

● **5 बैठकें होंगी, स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर हो सकती है बहस**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना और कार्यसूची जारी कर दी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिनमें प्रश्नोत्तर, शासकीय कार्य और वित्तीय मामलों चर्चा होगी। पहले 4 दिनों तक प्रश्नोत्तर काल और शासकीय कार्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंतिम दिन 17 जुलाई को प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों के साथ गैर-शासकीय कार्य भी लिए जाएंगे। सदन में स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है।

योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखेगी सरकार: मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, किसानों, बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों में हुए विवादित फैसलों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। चूंकि सत्र की अवधि केवल 5 दिन रखी गई है, इसलिए विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी उठ सकती है। सत्र के दौरान स्कूलों में मंत्र-पाठ के आदेश, कानून-व्यवस्था, हसदेव में जंगल कटाई, शराब दुकानों ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को दोबारा परेड कराई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फालता में पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की फिर हाफ पैंट में सड़क पर परेड कराई। इस दौरान जहांगीर ने कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगते दिखे। पुलिस ने चार घंटे नंगे पैर सड़क पर घुमाया। इससे पहले 11 जून को भी फालता में ही जहांगीर की हाफ पैंट में परेड कराई गई थी। जांच के सिलसिले में पुलिस उन्हें फलता लेकर आई है। 8 जून को अवैध वसूली के आरोप में उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। जहांगीर पर अवैध वसूली और महिलाओं को गैंगरेप की धमकी देने का आरोप है। जहांगीर का फालता में दबदबा था। जहांगीर खान ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को फिल्म 'पुष्पा' के किरदार की तरह पेश किया था। उन्होंने कई बार फिल्म का चर्चित डायलॉग 'पुष्पा झुकेगा नहीं साला' भी बोला था। उन्होंने खुद को इलाके के ऐसे मजबूत नेता के रूप में पेश किया, जो किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा।

भरोसे की आड़ में धोखा : रायपुर के शक्कर कारोबारियों से 2 करोड़ की ठगी

● **रायगढ़ के पिता-पुत्र पर मामला दर्ज**

रायपुर। शक्कर कारोबार से जुड़ी एक बड़ी कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर सहित सरगुजा संभाग के कई व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि शक्कर सप्लाई के नाम पर उधार में माल लेने के बाद भुगतान नहीं किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रायगढ़ निवासी एक कारोबारी और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का आरोप: मामले में रायगढ़ निवासी राजेश अग्रवाल और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया है। खमतराई थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने व्यापारियों से बड़े पैमाने पर शक्कर उधार में खरीदी, लेकिन तय समय पर भुगतान नहीं किया। इससे कई कारोबारी आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।

व्यापारी यूनियन के नाम पर बनाया नेटवर्क: शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों ने कारोबारियों का विश्वास हासिल करने के लिए छग-ओडिशा-एमपी शुगर व्यापारी यूनियन नाम से एक समूह बनाया था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जिलों और राज्यों के व्यापारियों से संपर्क स्थापित कर व्यापारिक नेटवर्क तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि इसी नेटवर्क के जरिए कारोबारियों के साथ लेन-देन शुरू हुआ और बाद में बड़ी मात्रा में शक्कर उधार में ली गई।

होटल में हुई थी कारोबारियों की बैठक: जानकारी के अनुसार रायपुर के रामसागरपारा स्थित ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय

● **3 साल पहले पति-पत्नी ने यह पार्टी बनाई थी, नारा था- दलबदलू नेताओं को नकारो**

कोलकाता/नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के विलय के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) चर्चा में है। रिकॉर्ड के अनुसार, 3 साल पहले 2023 में बंगाल के उत्तिया कुंडू और शेउली कुंडू नाम के कपल ने पार्टी की नींव रखी थी।

एनसीपीआई के डॉक्यूमेंट्स में उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं। पत्नी शेउली का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है। एनसीपीआई अध्यक्ष उत्तिया ने 13 मई को फेसबुक पर बंगाल सीएम

शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। हावड़ा में एनसीपीआई का ऑफिस है, जहां सोमवार को सुरक्षाबलों की तैनाती दिखी। ऑफिस के गेट पर उत्तिया ने खुद को बंगाली न्यूजपेपर का एडिटर और टीचर बताया है। उनकी पत्नी शेउली के नाम के नीचे कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील लिखा है।

एनसीपीआई बंगाल में रजिस्टर्ड, त्रिपुरा से चुनावी शुरुआत की: एनसीपीआई का रजिस्टर्ड पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बानीपुर इलाके में है।

भाई को खान सर ने मरवाया : रौशन आनंद

खान सर बोले- बीमारी से नेपाल में मौत हुई, आज अंतिम संस्कार

पटना। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर पर भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। रौशन आनंद ने सोमवार को कहा- खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर एस प्रसाद ने मिलकर मेरे भाई प्रिंस की हत्या की है। रौशन आनंद को खान सर की कोचिंग पर पथराव मामले मे सोमवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। इसके बाद वह बेऊर जेल से बाहर निकले और प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होने सहरसा के लिए रवाना हो गए। रौशन आनंद ने कहा कि मैं बाहर था तो क्यों उसकी हत्या नहीं हुई। मेरे जेल में जाते ही उसकी साजिश के तहत उसे मरवाया गया। फैजन खान बहुत झूठ बोलता है। पहले कह रहा था गोली हमने चलाई। वीडियो सामने आया कि उसने ही गोली चलवाई।

रविवार को नेपाल के विराटनगर के एक होटल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव लाश मिली थी। प्रिंस की आंख पर चोट के निशान थे। आज सहरसा में प्रिंस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर, खान सर का कहना है कि प्रिंस की हत्या नहीं हुई है, वह पहले से बीमार था।

वकील बोले- खान सर के बॉडीगार्ड ने फायरिंग की बात छिपाई: रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 12 दिन बाद उन्हें जमानत मिली है। 2 जून को खान सर कोचिंग में हुए हमले के बाद दर्ज एफआईआर में प्रिंस भी नामजद आरोपी था। रौशन आनंद के वकील रमाकांत शर्मा के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, दोनों टीचर हैं, हेल्दी कम्पीटिशन करें, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व न हों। गुरु हैं, गुरु की तरह व्यवहार करें। रौशन आनंद के वकील रमाकांत शर्मा ने बताया, हमने कोर्ट में कहा अगर इस एफआईआर को एक्सेप्ट भी किया जाए तो रौशन आनंद इस घटना में शामिल नहीं हैं। हमपर षडयंत्र का आरोप है तो खान के बॉडीगार्ड के फायरिंग की बात क्यों छिपाई गई।

खान सर बोले- प्रिंस पहले से बीमार था, उसे किसी ने नहीं मारा: वहीं, रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर खान सर ने अपना एक भावुक वीडियो मैसेज जारी कर दुख जताया है। उन्होंने सफाई दी- उसको किसी ने नहीं मारा। वो हम लोगों का करीबी दोस्त था, ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता ने सुसाइड किया

मुंबई। टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने रविवार रात को सुसाइड कर लिया। वे 22 साल की थीं। पुलिस ने बताया कि एक्ट्रेस का शव घर में सीलिंग फैन से लटका मिला। उन्होंने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाई। सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद वाघ ने मीडिया को दिए बयान में कहा, 'हमारी टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। घटना के समय वे घर में अकेली थीं। उनके पिता ने बेटी की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया।' संचिता अपने माता-पिता के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहती थीं। रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बहन अंजली घर से बाहर गई थी। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था।

अकाल तख्त ने सीएम को गुरु दोषी-पंथ विरोधी करार दिया

● **जत्थेदार बोले- शराब वाली वीडियो सही, आप बोली- उसमें भगवंत मान, ये साबित नहीं होता**

अमृतसर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अकाल तख्त ने पंथ विरोधी और गुरु विरोधी घोषित कर दिया है। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने फसील से संबोधन में कहा कि वायरल वीडियो की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने के बाद सामूहिक तौर पर सिखों ने कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद इस पर 5 सिंह साहिबानों की मीटिंग में चर्चा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी करार दिया जाता है। पूरा खालसा पंथ और गुरु नामलेवा

सीएम को मुंह न लगाएं। यह फैसला सीएम मान की कथित शराब वाली वायरल वीडियो की पुष्टि होने पर लिया गया। इसके अलावा, अकाल तख्त ने आप के सारे सिख विधायकों को भी तलब किया है। उन्होंने सरकार के बेअदबी कानून पर साइन किए थे, जिसे अकाल तख्त ने गलत ठहराया है।

वहीं, आप प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने बयान जारी कर कहा है कि यदि मान भी लिया जाए कि वायरल वीडियो सही है, फिर भी इससे यह साबित नहीं होता कि वीडियो में दिख रहा शख्स कौन है।

मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस एवं समयबद्धता के लिए मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों को दिए प्रशंसा पत्र

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों का निराकरण करने और कार्यालयीन समय पर उपस्थित होने वाले श्रेष्ठ अधिकारी-कर्मचारियों को मई माह के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किये है। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे ई-ऑफिस पर अच्छे से अच्छा कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित कार्यालय में समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए बधाई दी।

विभागों में ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान पर गृह विभाग और दूसरे स्थान पर समाज कल्याण और तीसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन रहा। प्रशंसा पत्र समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने प्राप्त किया।

मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए विभागीय सचिव को सम्मानित किया। इसमें श्रेष्ठ फाईल निष्पादन के लिए ई-ऑफिस पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार को प्रथम स्थान पर सम्मानित किया। वहीं पर विधि एवं विधायी की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत को दूसरे स्थान ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह से तीसरे स्थान पर गृह एवं श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता को ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव ने संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक सहित अन्य कर्मचारियों को भी ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए है।

संयुक्त सचिव श्रेणी में ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेद्वी को प्रथम, दूसरे स्थान पर अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के भूपेन्द्र कुमार राजपूत को सम्मानित किया गया। वहीं पर परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव कमलेश बंसोड को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया है। उप सचिव श्रेणी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप सचिव दूरदेशी राम सोन्टापर को प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-एक के उप सचिव किशोर कुमार भूआर्य को सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-6 की उप सचिव ऋतु वर्मा को सम्मानित किया गया। अवर सचिव श्रेणी में प्रथम स्थान पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव अरूण कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर गृह विभाग के उप सचिव पूरन लाल साहू को सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अवर सचिव मगनलाल पवार को सम्मानित किया गया।

मुख्य सचिव ने अनुभाग अधिकारी श्रेणी में ई-ऑफिस में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनुभाग अधिकारी प्रथम स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-4 व 1 के अनुभाग अधिकारी नंदकुमार मेश्राम को सम्मानित किया। दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग अधिकारी विरेन्द्र कुमार को और तीसरे स्थान के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुभाग अधिकारी भोलेनाथ सारथी को सम्मानित किया। इसी तरह से वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक दूर्गेश रात्रे को सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक रामगोपाल सेन और तीसरे स्थान पर स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय सहायक कमलेश यदु सम्मानित हुए।

इसी प्रकार से कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में प्रथम स्थान पर नगरीय प्रशासन विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक उमेश यादव, दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक भानुप्रसाद और तीसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-2 के कनिष्ठ सहायक सुरेन्द्र कुमार सम्मानित हुए।

वनोपज आधारित आजीविका को मिल रही नई पहचान: रूपसाय सलाम

- वन धन विकास केंद्र पनचक्की में मूल्य संवर्धन गतिविधियों का किया अवलोकन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम ने जशपुर जिले के वन धन विकास केंद्र पनचक्की का निरीक्षण कर वहां संचालित वनोपज आधारित गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन कार्यों का अवलोकन करते हुए केंद्र की उपलब्धियों की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान सलाम ने केंद्र में निर्मित आयुर्वेदिक उत्पादों, विशेष रूप से आरोग्य अमृत अवलेह एवं वसाअवलेह के निर्माण, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वन धन विकास केंद्र स्थानीय वन संसाधनों को आर्थिक अवसरों में बदलने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

उन्होंने केंद्र द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि लघु वनोपजों का वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सलाम ने वनोपज आधारित उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता तथा बाजार में उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को उनके पारंपरिक संसाधनों का अधिकतम लाभ मिले और उनकी आजीविका मजबूत हो।

फसल विविधीकरण और नैनो उर्वरकों से किसानों की बढ़ रही आय

मक्का उत्पादन, जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों का समन्वय बन रहा सफलता की नई पहचान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए किसान अब फसल विविधीकरण, जैविक पोषण प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं। राज्य शासन और कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहित वैज्ञानिक खेती की पद्धतियां किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक आय अर्जित करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। इसके सकारात्मक परिणाम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। सरगुजा जिले के ग्राम सरगांवा के प्रगतिशील किसान बिराज विश्वास ने फसल विविधीकरण और नैनो उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से खेती में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पारंपरिक खेती की पद्धति में बदलाव करते हुए पिछले चार वर्षों से धान के स्थान पर मक्का उत्पादन को अपनाया है। आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से वे अपनी कृषि भूमि में वर्षभर उत्पादन लेकर बेहतर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। बिराज विश्वास का मानना है कि फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। मक्का उत्पादन के साथ-साथ वे सब्जी खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक खेती की पद्धतियों के उपयोग से उत्पादन लागत में कमी आई है तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए वे जैविक खादों का अधिक उपयोग करते हैं। गोबर खाद एवं अन्य जैविक स्रोतों के साथ नैनो उर्वरकों का प्रयोग फसलों को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो रहा है। नैनो उर्वरकों के उपयोग से पोषक तत्व सीधे पौधों तक पहुंचते हैं, जिससे उनकी उपयोग दक्षता बढ़ती है और फसलों को बेहतर वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त होता है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नैनो उर्वरक खेती की लागत कम करने, पोषक तत्वों के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने तथा पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं फसल विविधीकरण किसानों को बाजार आधारित उत्पादन और जोखिम प्रबंधन के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण, जैविक खेती तथा नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिराज विश्वास जैसे प्रगतिशील किसानों की सफलता यह दर्शाती है कि वैज्ञानिक खेती, नवाचार और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख बनाया जा सकता है। उनकी पहल आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

आधुनिक खेती की ओर कदम: नैनो उर्वरक और स्वीट कॉर्न ने बदली रामचंद्र की किस्मत

रायपुर। कोण्डागांव जिले के किसान अब पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए धान, सब्जियों और अन्य नगदी फसलों के साथ-साथ स्वीट कॉर्न की खेती कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। जिले में कृषि के क्षेत्र में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव का एक प्रेरणादायक उदाहरण बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्राम मारंगपुरी निवासी किसान रामचंद्र साहू हैं, जिन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती को अपनाकर आर्थिक समृद्धि की नई पहचान बनाई है।

स्वीट कॉर्न की खेती से समृद्धि की नई मिसाल बने किसान रामचंद्र

रामचंद्र साहू पिछले तीन वर्षों से स्वीट कॉर्न का उत्पादन कर रहे हैं। उनके बेटे राजेन्द्र साहू ने बताया कि बाजार में इसकी बढ़ती मांग और बेहतर लाभ को देखते हुए इस वर्ष लगभग ढाई एकड़ भूमि में अशोका किस्म के स्वीट कॉर्न की खेती की है। इसके लिए उन्होंने लगभग 7 किलोग्राम बीज का उपयोग किया, जिस पर लगभग 21 हजार रुपये की लागत आई। आधुनिक खेती की पद्धतियों को अपनाते हुए उन्होंने फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया, जिसका सकारात्मक परिणाम उन्हें बेहतर उत्पादन और आय के रूप में प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने बताया कि सामान्य मक्का की तुलना में स्वीट कॉर्न की बाजार में मांग अधिक रहती है। तैयार फसल का प्रत्येक भुट्टा लगभग 7 रुपये प्रति नग की दर से विक्रय होता है। अप्रैल से जुलाई के बीच तैयार होने वाली इस फसल से उन्हें एक सीजन में लगभग दो लाख रुपये तक की आय प्राप्त होती है। कम समय में बेहतर लाभ मिलने के कारण स्वीट कॉर्न किसानों के लिए लाभकारी विकल्प के रूप में उभर रही है। फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए साहू नैनो यूरिया का भी उपयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार नैनो यूरिया के प्रयोग से फसल की वृद्धि बेहतर हुई है तथा पौधों के विकास और उत्पादन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को और अधिक सशक्त बनाया है।

रामचंद्र साहू को कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत शैलो ट्यूबवेल तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ भी प्राप्त हुआ है। इन सुविधाओं के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो रही है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आने के साथ-

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों से सुदृढ़ हुआ राजस्व प्रशासन

- नवीन तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय भवनों से नागरिकों को मिल रही बेहतर राजस्व सेवाएं

रायपुर। कोरबा जिले में राजस्व प्रशासन को अधिक सक्षम एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नवीन तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, कोरबा द्वारा निर्मित इन आधुनिक भवनों में अधिकांश स्थानों पर नियमित कार्यालयीन कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोरबा जिले के लिए 5 नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल 4 करोड़ 3 लाख 63 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति के अंतर्गत भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान एवं अजगरबहार में नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा पाली में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है।

वर्तमान में भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान तथा पाली स्थित नवीन भवनों में नियमित रूप से कार्यालयीन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन भवनों के उपयोग में आने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त हुआ है, वहीं आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक व्यवस्थित, सुगम और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो रही हैं। अजगरबहार तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में विद्युत कनेक्शन से संबंधित औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं। विद्युत लाइन जोड़ने एवं भवन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही वहां भी कार्यालयीन कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

रायपुर में टीबी एवं फेफड़ों के कैंसर की प्रारंभिक जांच सेवाओं के एकीकरण पर राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा PATH एवं The Bristol Myers Squibb Foundation के सहयोग से टीबी एवं फेफड़ों के कैंसर की प्रारंभिक जांच सेवाओं के एकीकरण विषय पर राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन रायपुर में किया गया। बैठक का उद्देश्य टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध जांच एवं निदान तंत्र का प्रभावी उपयोग करते हुए फेफड़ों के कैंसर की शीघ्र पहचान एवं देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना था।

बैठक में राज्य क्षय अधिकारी एवं उप संचालक (एनसीडी) डॉ. संजीव मेश्राम तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर डॉ. मिथलेश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर के प्रतिनिधियों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों तथा टीबी एवं गैर-संचारी रोग (NCD) के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से बदली किसान क्रांति कुमार चंद्राकर की तकदीर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि नवाचार और उद्यानिकी फसलों के विस्तार का असर अब धरातल पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। महासमुंद जिले के विकासखंड महासमुंद अंतर्गत ग्राम लोहारडीह निवासी प्रगतिशील किसान क्रांति कुमार चंद्राकर ने पारंपरिक धान खेती से आगे बढ़कर ग्राफ्टेड बैंगन की आधुनिक खेती अपनाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत आय वृद्धि का उदाहरण है, बल्कि राज्य में कृषि विविधीकरण और तकनीक आधारित खेती की दिशा में एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में उभरी है। एम.टेक. तक शिक्षित चंद्राकर पूर्व में अपनी 1.46 हेक्टेयर सिंचित भूमि पर मुख्यतः धान की खेती करते थे। परंतु अधिक जल उपयोग, बढ़ती उत्पादन लागत तथा सीमित लाभ के कारण उन्हें अपेक्षित आर्थिक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कृषि में नवाचार और उद्यानिकी फसलों की ओर रुख करने का निर्णय लिया।

बेमेतरा जिले में दलहन के रकबे में चार गुना की वृद्धि

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की 'मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस' योजना बेमेतरा जिले में दलहन उत्पादन को नई ऊंचाई दे रही है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और उन्नत खेती तकनीकों के चलते जिले में ग्रीष्मकालीन उड़द-मूंग की खेती का रकबा एक वर्ष में चार गुना से अधिक बढ़ गया है। पिछले वर्ष 285 हेक्टेयर में होने वाली खेती इस वर्ष बढ़कर 1191 हेक्टेयर तक पहुंच गई है।

विकासखंड नवागढ़ के ग्राम हरदी के किसान इंद्रकुमार ने ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती कर सफलता की नई मिसाल पेश की है। कृषि विभाग के अनुसार उन्हें 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलने की संभावना है। वहीं कोरकापारा के किसान शिवशंकर वर्मा को 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन का अनुमान है। दोनों किसानों ने उन्नत बीजों और वैज्ञानिक खेती पद्धतियों को अपनाकर बेहतर परिणाम हासिल किए हैं।

महिला उद्यमियों को मिला बाजार विस्तार का मंत्र

रायपुर। बदलते तकनीकी दौर में महिला उद्यमियों को आधुनिक साधनों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवा बिहान क्लस्टर में आयोजित डिजिटल साक्षरता कार्यशाला ने महिलाओं को ऑनलाइन विपणन, ब्रांड निर्माण और इंटरनेट आधारित व्यापार की नई संभावनाओं से परिचित कराया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और महिला संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आधुनिक विपणन तकनीकों की जानकारी देकर उनके उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को उत्पाद पहचान निर्माण, आकर्षक पैकेजिंग, लेबलिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, ऑनलाइन विक्रय मंचों तथा बाजार से जुड़ने के विभिन्न तरीकों की व्यवहारिक जानकारी दी।

वसुंधरा यादव ने कहा कि महिला उद्यमिता केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी मजबूत आधारशिला है। उन्होंने महिलाओं को तकनीकी ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग कर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

100 एकड़ कृषि भूमि होगी सिंचित, खरीफ और रबी दोनों फसलों को मिलेगा लाभ

निष्क्रिय सिंचाई योजना को मिला नया जीवन

- लगभग 12 लाख रुपए की लागत से नहर मरम्मत कार्य पूर्ण

गुतकिया के किसानों को मिलेगी वर्षभर सिंचाई सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पण्डरसिली के आश्रित ग्राम गुतकिया में वर्षों से निष्क्रिय पड़ी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित कर किसानों के लिए उपयोगी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की भावना के अनुरूप सिंचित क्षेत्र के विस्तार तथा पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के पुनरोद्धार के लिए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके तहत गुतकिया व्यपवर्तन योजना की नहर मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

मनरेगा से मिली नई गति: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस कार्य के लिए 11 लाख 98 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में नहर मरम्मत कार्य पूर्ण कर योजना को पुनः क्रियाशील बनाया गया है।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ: नहर मरम्मत कार्य पूर्ण होने से ग्राम गुतकिया और आसपास के क्षेत्र की लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसान खरीफ के साथ-साथ रबी सीजन में भी खेती कर सकेंगे। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने से फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा: सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के बाद कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के साथ अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान अधिक आय अर्जित कर सकेंगे।

आदिवासी अंचल में कृषि विकास को मिलेगी नई दिशा: इस परियोजना से क्षेत्र के आदिवासी किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। सिंचाई सुविधा सुदृढ़ होने से खेती अधिक लाभकारी बनेगी और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। गुतकिया में पुरानी योजना का पुनर्जीवन कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनकर सामने आया है।

नहर मरम्मत कार्य पूर्ण होने से स्थानीय किसानों में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों का मानना है कि यह पहल क्षेत्र में कृषि विकास, जल प्रबंधन और किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

रक्तदान करने वालों का राज्यपाल ने किया सम्मान

लोकभवन में 130 रक्तदाता हुए सम्मानित, मेकाहारा में प्रमा फाउंडेशन ने लगाया कैंप

रायपुर। विश्व रक्तदाता दिवस पर रविवार को रायपुर में रक्तदान को लेकर कई आयोजन हुए। लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशभर के 130 स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया। वहीं, मेकाहारा के मॉडल ब्लड सेंटर में आयोजित रक्तदान शिविर में 46 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा की ओर से लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडप में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने कई जिलों से आए 130 रक्तदाताओं को सम्मानित किया।

स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए: राज्यपाल ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है। रक्तदाता किसी अनजान व्यक्ति का जीवन बचाकर समाज में संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और हर स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। रेडक्रॉस के चेयरमैन तोमन साहू ने कहा कि, संस्था का प्रयास है कि प्रदेश में किसी भी जरूरतमंद को रक्त के अभाव का सामना न करना पड़े। उन्होंने रक्तदाताओं को समाज का वास्तविक नायक बताया।

मेकाहारा में प्रमा फाउंडेशन का रक्तदान शिविर: विश्व रक्तदाता दिवस पर समाजसेवी संस्था प्रमा फाउंडेशन ने भी मेकाहारा स्थित मॉडल ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संस्था के अनुसार शिविर में कुल 46 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। प्रमा फाउंडेशन के सचिव राजकुमार मिश्रा ने बताया कि, संस्था पिछले 13 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है। इस बार भी युवाओं, महिलाओं और स्वयंसेवकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रमा फाउंडेशन सम्मानित: रक्तदान और समाजसेवा के क्षेत्र में लगातार योगदान के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) के डीन डॉ. विवेक चौधरी ने प्रमा फाउंडेशन को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संस्था ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम है।

रक्तदान को जनआंदोलन बनाने पर जोर: दोनों आयोजनों में एक ही संदेश प्रमुखता से सामने आया रक्तदान जीवनदान है। वक्ताओं ने कहा कि, एक यूनिट रक्त कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए और इसे सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की अगस्त-सितंबर परीक्षा का टाइम टेबल जारी

- **हाईस्कूल की परीक्षा 25 अगस्त तक और हायर सेकेंडरी की परीक्षा 29 तक चलेंगी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने अगस्त-सितंबर 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 10 अगस्त 2026 से शुरू होंगी। हाईस्कूल की परीक्षाएं 10 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएंगी, जबकि हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 10 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक चलेंगी।

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने परीक्षा कार्यक्रम के साथ परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम को भली-भांति नोट कर लें। परीक्षाकाल के दौरान यदि शासन द्वारा सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। आवश्यकता पड़ने पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा की तिथि एवं समय में परिवर्तन कर सकता है। प्रायोगिक परीक्षाएं 29 अगस्त 2026 तक संबंधित केंद्राध्यक्ष अपनी सुविधा अनुसार अनिवार्य रूप से आयोजित कराएंगे तथा इसकी सूचना सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को दी जाएगी। हायर सेकेंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा तथा हाईस्कूल की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन हायर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। छात्र-छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी अपने परीक्षा केंद्र से संपर्क कर प्राप्त करें।

छात्रों के लिए सलाह: परीक्षार्थी परीक्षा तिथि, विषय और समय का मिलान पहले से कर लें तथा प्रवेश पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखें, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।

अस्पतालों में नकली-फेक दवाओं की सप्लाई का आरोप

- **कांग्रेस ने राज्यपाल से की उच्चस्तरीय जांच की मांग, विकास बोले- कॉरपोरेशन खुद जारी कर चुका है सर्कुलर**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही दवाओं की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (ष्टत्रूष्ट) की तरफ से खरीदी और सप्लाई की जा रही कथित अमानक, नकली और निम्न स्तरीय दवाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि, पिछले कई महीनों से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन खुद समय-समय पर सर्कुलर जारी कर अपनी सप्लाई की गई दवाओं को ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के आधार पर अमानक और निम्न गुणवत्ता वाला बताकर वापस मंगाता रहा है।

दवाएं फेल हो रही हैं, फिर भी मरीजों को बांटी जा रही थी- विकास: उपाध्याय ने आरोप लगाया कि, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों-नर्सिंग स्टाफ ने भी कई बार दवाओं और इंजेक्शनों के विपरीत प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। इसके बावजूद उच्च स्तर पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हो रही हैं, तो यह सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अस्पतालों में सलाइन और जरूरी दवाओं की कमी का आरोप: कांग्रेस ने सरकारी अस्पतालों में कई जरूरी दवाओं और मेडिकल सामग्री की कमी का भी मुद्दा उठाया। आईवी फ़्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन (एनएस), डीएनएस और आरएल जैसी जरूरी सलाइन कई अस्पतालों में महीनों से उपलब्ध नहीं हैं। गर्भवती महिलाओं और सिकल सेल मरीजों को दी जाने वाली फोलिक एसिड की गोलियों की सप्लाई प्रभावित है। सिकल सेल की जांच के लिए जरूरी किट कई अस्पतालों में नहीं मिल रही। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जरूरतमंद मरीजों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की सहायता मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में यह योजना लगभग निष्क्रिय हो गई है। गरीब मरीजों को महंगे इलाज और दवाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

राज्यपाल से जांच दल बनाने की मांग: कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले दो वर्षों में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा की गई दवा खरीदी और सप्लाई की जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

'टूरा भोको लोलो' फेम रैपर एप्पी राजा का निधन

- **6 महीने पहले तबीयत बिगड़ी, ऑपरेशन के बाद शरीर में खून की कमी थी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोकप्रिय रैपर और सिंगर एप्पी राजा उर्फ चेतन चांडक (32) का निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। रायपुर में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि, करीब 6 महीने पहले एप्पी राजा की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके दोस्तों ने बताया था कि, एक ऑपरेशन के बाद उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी।

लगातार हीमोग्लोबिन गिरने के कारण उन्हें कमजोरी, चक्कर और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत थी। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था और उन्हें रक्त भी चढ़ाया जा रहा था।

भानुप्रतापपुर के रहने वाले थे एप्पी राजा: बस्तर के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के रहने वाले एप्पी राजा ने अपने दम पर छत्तीसगढ़ी रैप को नई पहचान दिलाई थी। कम उम्र से ही रैप गीत लिखने वाले एप्पी ने आर्थिक संघर्षों के बीच अपना सफर तय किया। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें कुछ समय तक गुजरात के सूरत में नौकरी भी करनी पड़ी, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून उन्हें फिर इसी क्षेत्र में वापस ले आया।

एप्पी राजा को सबसे ज्यादा पहचान उनके चर्चित रैप सॉन्ग 'टूरा भोको लोलो' से मिली। यह गीत रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार छत्तीसगढ़ी संगीत प्रेमियों को नए गीत दिए।

रायपुर रेलवे स्टेशन पर महिला से मारपीट

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक महिला के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटते और पेट पर लात मारते और घूंसों से पीटते दिखाई दे रहे हैं।

घटना रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में हुई, जहां उस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बावजूद किसी ने महिला को बचाने या बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला खुद को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन युवक लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे।

स्टेशन के आसपास मौजूद लोग पूरी घटना देखते रहे, जबकि कुछ लोग वीडियो बनाते नजर आए। घटना के दौरान महिला चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल युवक और महिला के बीच विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और मामला मारपीट तक कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

बीएसयूपी कॉलोनी में पुलिस का ऑपरेशन

- **300 से ज्यादा घरों की जांच, गुंडे-बदमाश, किरायेदार और संदिग्धों का सत्यापन**

रायपुर। रायपुर पुलिस ने बीएसयूपी कॉलोनी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। सरस्वती नगर, आमानाका और न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फैली कॉलोनी में करीब 100 पुलिस अधिकारियों और जवानों ने दबिश देकर 300 से ज्यादा मकानों की जांच की।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप पटेल के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्तों ने की। सुबह 8 बजे शुरू हुए अभियान में कॉलोनी के अलग-अलग ब्लॉकों, मकानों और सार्वजनिक स्थानों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान क्षेत्र में रहने वाले गुंडा-बदमाशों, निगरानीशुदा अपराधियों, आदतन अपराधियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने बाहर से आकर किराये या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के दस्तावेज भी खंगाले। टीमों ने घर-घर पहुंचकर रहवासियों से जानकारी ली और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षा संबंधी जरूरी सुझाव भी दिए।

सामाजिक एकता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश लेकर सम्पन्न हुई

- **प्रदेश कुंनबी समाज महासंघठन छ. ग. की भव्य महापंचायत, शपथ ग्रहण एवं कुंनबी रत्न एवं कुंनबी गौरव सम्मान**

रायपुर। रविवार को प्रदेश कुंनबी समाज महासंघठन द्वारा आयोजित भव्य सामाजिक महापंचायत, शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए समाज के वरिष्ठजन, पदाधिकारी, महिला एवं युवा प्रतिनिधि, समाजसेवी तथा बड़ी संख्या में समाजबंधुओं ने सहभागिता कर संगठन की एकजुटता एवं सामाजिक चेतना का परिचय दिया।समारोह के दौरान चुनाव अधिकारी एस.एस. ब्राह्मणकर एवं जे.एन. गोंधुड़े द्वारा नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी को विधिवत शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रंजीतभाऊ मुनेश्वर को पुनः प्रदेश अध्यक्ष तथा श्रीमती सारिका गेडेकर को महिला प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। दोनों पदाधिकारियों ने समाज के हित, संगठन के विस्तार एवं सामाजिक उत्थान के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करने का

संकल्प व्यक्त किया तथा अपनी-अपनी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रदेश अध्यक्ष रंजीतभाऊ मुनेश्वर ने कहा कि समाज की प्रगति शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरूकता से ही संभव है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से समाजहित को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। वहीं महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सारिका गेडेकर ने महिलाओं की सहभागिता को समाज की शक्ति बताते हुए उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

फ्यूजन फाइनेंस ने पिथौरा शाखा में धन के गबन के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की

- **कंपनी जीरो टॉलरेंस के प्रति कटिबद्ध**

रायपुर। एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी पिथौरा शाखा (सरायपाली क्लस्टर, अंबिकापुर क्षेत्र) में कंपनी के फंड के अनधिकृत उपयोग और संदिग्ध गबन के मामले में शाखा प्रबंधक के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी ने हितधारकों के हितों की रक्षा करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए यह त्वरित कदम उठाया है।

यह मामला 1 जून, 2026 को प्रकाश में आया, जब पिथौरा शाखा में नकदी की कमी पाई गई। इसके बाद आंतरिक सत्यापन में शाखा के पास मौजूद नकदी में विसंगतियां सामने आईं। 2 जून, 2026 को शाखा प्रबंधक रोहित पटेल ने क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित किया कि शाखा की नकदी का एक हिस्सा व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। प्रारंभिक जांच के आधार पर, फ्यूजन फाइनेंस ने शाखा की नकदी के अनधिकृत उपयोग और रिकॉर्ड में विसंगतियों की पहचान की, जिसमें लगभग 5 लाख रुपये की संदिग्ध धोखाधड़ी शामिल है। कंपनी ने तुरंत मामले को आगे बढ़ाया और सुधारात्मक, कानूनी और समीक्षात्मक उपाय शुरू किए।

अनियमितताओं की पुष्टि होने पर, कंपनी ने पुलिस को मामले की सूचना दी, कानूनी कार्यवाही शुरू की और आरोपी कर्मचारी से एक हलफनामा प्राप्त किया, जिसमें उसने शाखा की नकदी के अनधिकृत उपयोग की बात स्वीकार की है। कानूनी विभाग ने उचित आपराधिक कार्रवाई के लिए कानूनी सलाहकारों और आंतरिक टीमों के साथ समन्वय किया। कंपनी की शिकायत के आधार पर, 5 जून, 2026 को भारतीय न्याय संहिता के विश्वासघात और संबंधित अपराधों के प्रावधानों के तहत एफआईआर संख्या 142/2026 दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने रोहित मोहनलाल पटेल को इस मामले में गिरफ्तार किया और कंपनी को सूचित किया। कंपनी चल रही जांच में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रही है।

बस एवं कार ऑपरेटर फेडरेशन ऑफ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम संपन्न

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह कार्यक्रम के मुख्य अथिति परिवहन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि एवं रायपुर शहर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी, संघ के संरक्षक व नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस आयोजन में बी.ओ.सी.आई. के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ पूर्व महापौर प्रमोद दुबे परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एस प्रकाश अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रवि शंकर कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी परिवहन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण तमाम मिडिया के साथी गण उपस्थित रहे। साथ ही परिवहन उद्योगों से जुड़े औद्योगीक एवं व्यापारिक संस्थानों के स्टॉल भी सभी की जानकारी के लिए लगाए गए।

कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4.30 बजे हुई ,जिसमें व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में परिवहन उद्योग की संभावनाओं एवं समस्याओं और उसकी उन्नती के लिए विशेष चर्चा हुई। अतिथियों को उसके बारे में अवगत भी कराया गया एवं आपस में विचार विमर्श हुआ। यह मौका परिवहन उद्योग से जुड़े सभी लोगों के लिए मिलन समारोह तो था ही साथ ही अपनी बातों को शीर्ष सत्ता तक पहचानें का सशक्त माध्यम भी रहा। बीओएफसी के अध्यक्ष अनिल पुसदकर, महासचिव भावेश दुबे ने कार्यक्रम में बताया कि किस प्रकार स्थानीय पेसेंजर व्हीकल ऑपरेटर की समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रयास किया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके।

इस पर अपने संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तीन बार मुख्यमंत्री रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह व विशिष्ट अतिथि परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य भर के परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों को सरकार से सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

छत्तीसगढ़ में परिवहन उद्योग को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। उनकी हर समस्या पर सरकार की नजर है और सरकार ट्रांसपोर्टरों को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्कूल बस नवशरण गरचा, फ़ेडरेशन के उपाध्यक्ष अनुराग शुक्ला, अजय गिल, अभिनित शुक्ला,जसविंदर सिंह साहनी,बृजेश दुबे,महेंद्र पंडित, मुन्ना मिश्रा, संजय गुप्ता, अलोक त्रिपाठी, प्रफुल्ल तिवारी, सत्यानंद पांडे, गुरमीत सिंह, नन्दलाल वर्मा, किरथ बल विनीत जैन, कस्तूरिया, अभिनन्दन, रोशन, रितेश वर्मा, दिनेश, नोबल देवांगन, गुलताज एवं पुरे प्रदेश से बस एवं कार के व्यवसाय से जुड़े सारे ऑपरेटर शामिल हुए।

7 जून को इंडोर स्टेडियम में भव्य सहस्त्रावधान कार्यक्रम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक ऐतिहासिक एवं अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। सकल जैन श्री संघ, छत्तीसगढ़ एवं श्री अखिल भारतीय खरतरगच्छ महासंघ के तत्वावधान में 17 जून 2026 को प्रातः 7:30 बजे इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर में भव्य सहस्त्रावधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस आयोजन की विशेषता यह है कि 14 वर्षीय बालमुनि, 22 आगमों के ज्ञाता एवं महारतावधानी पूज्य श्री हँसभद्र मुनि जी महाराज एक ही समय में पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। सहस्त्रावधान को जैन परंपरा के अत्यंत दुर्लभ, विलक्षण एवं ज्ञानप्रधान आयोजनों में माना जाता है। आयोजकों के अनुसार यह केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और आत्मबल का अद्भुत प्रदर्शन है। इतनी कम आयु में इस प्रकार की असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन समाज के लिए प्रेरणा का विषय है।

रायपुर में पहली बार आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक सहस्त्रावधान को लेकर जैन समाज सहित विभिन्न वर्गों में उत्साह का वातावरण है। आयोजकों ने धर्मप्रेमी बंधुओं एवं आमजन से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस दुर्लभ आध्यात्मिक आयोजन के साक्षी बनने तथा धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। यह आयोजन आस्था, ज्ञान और साधना के अद्वितीय संगम का साक्षी बनेगा तथा रायपुर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ने वाला सिद्ध होगा।

विधवा से रिश्वत लेते बैंक मैनेजर का वीडियो वायरल

बलौदाबाजार में मृत पति के खाते की रकम दिलाने 5 हजार लिए, 10 हजार मांगे थे, सस्पेंड

बलौदाबाजार। जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपनिया ब्रांच का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर महिला मैनेजर अनिता पांडेय को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला अपने मृत पति के खाते से पैसे निकलवाने आई थी तो मैनेजर ने 10 हजार रुपए मांगे थे लेकिन 5 हजार रुपए लेते हुए उनका वीडियो एक ग्रामीण ने बनाकर वायरल कर दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने जनदर्शन में कलेक्टर से करते हुए सबूत सौंपा था।

वहीं इस कार्रवाई के बीच भाटापारा विधायक इंद्र साव ने भी मैनेजर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया कि पहले भी इसकी कई शिकायतें मिली थीं और एक साल पहले फोन पर बात करने पर इस महिला अधिकारी ने मैं बिहारी हूं जो करना है कर लो कहकर फोन काट दिया था।

पति के खाते में 1 लाख 10 हजार थे

शिकायतकर्ता खेलन बाई सतनामी ने बताया कि उनके पति रूपदास सतनामी का करीब एक साल पहले निधन हो गया था। उनके पति का निपनिया शाखा में एक बैंक खाता था, जिसमें लगभग 1 लाख 10 हजार रुपए जमा थे। महिला का आरोप है कि ब्रांच मैनेजर अनीता पांडेय ने पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करने के बदले पहले 10 हजार रुपए की मांग की। बाद में यह रकम घटाकर 5 हजार रुपए कर दी गई।

वायरल वीडियो में मैनेजर ने महिला से उसके पति के बारे में पूछताछ की। इसके बाद दस्तावेजों पर साइन करवाए, फिर महिला के बेटे से कहा किज्जल्दी पैसे निकालो बोल रही हूं। मैनेजर ने पूछा कितने रुपए हैं। बेटे ने जवाब दिया कि 5 हजार रुपए। इसके बाद मैनेजर महिला और उसके बेटे से कहती हैज्मेरे पास आना कभी भी आना हो तो। अगर कोई परेशानी होगी तो बुलाऊंगी बेटा।

विधायक ने उठाए बैंक मैनेजर की कार्यशैली पर सवाल

वहीं भाटापारा विधायक इंद्र साव ने भी ब्रांच मैनेजर की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी के पहले वाले कामकाज के दौरान भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। निपनिया के किसान भी उनके काम करने के तरीके से परेशान हैं। विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें होना सही बात नहीं है। कुछ ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया है कि बैंक के काम के लिए उनसे रिश्वत मांगी जाती है। बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शिकायत के बाद संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं।

रमन सिंह बोले-राहुल जहां जाते हैं,वहां बंटाधार हो जाता है

- **भूपेश ने भाजपा की जीत पर उठाए सवाल,कहा-बीजेपी का 90फीसदी स्ट्राइक रेट लोकतंत्र की डकैती**

रायपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की चुनावी जीत और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भाजपा की जीत का प्रतिशत करीब 90 फीसदी तक पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे चोरी नहीं, लोकतंत्र की डकैती करार दिया है। यह बयानबाजी दुर्ग में हुई।

रमन सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज

दरअसल, दुर्ग सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. रमन सिंह ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को एक-दो बार छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए, ताकि यहां कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो सके।

भूपेश बघेल ने किया पलटवार

रमन सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने भाजपा की चुनावी जीत और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बघेल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भाजपा का स्ट्राइक रेट 90 फीसदी तक पहुंच गया है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। बघेल ने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा को मिली सफलता सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में संभव नहीं दिखती। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे और लोकप्रिय भी थे, तब भी उन्हें ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे चोरी नहीं, लोकतंत्र की डकैती करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका कमजोर की जा रही है। बघेल के अनुसार, पहले मतदाता सरकार चुनते थे, लेकिन अब सरकारें ही निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं के जरिए यह तय करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन मतदाता रहेगा और कौन नहीं।

भूपेश ने चुनावी प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने कहा कि यह कोई सामान्य राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साथ डकैती जैसी स्थिति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सुधार और दूसरी प्रक्रियाओं के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है।

ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने ईवीएम मशीनों को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 हजार ईवीएम मशीनों के नष्ट होने की खबरें सामने आई हैं, जो गंभीर जांच का विषय है।

धमतरी में घर में मिली दंपती की लाश

पति हॉल में और पत्नी कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली

धमतरी। जिले में एक बुजुर्ग दंपती की घर में फंदे से लटकी हुई लाश मिली है। दंपती के शव घर के 2 अलग-अलग कमरों में लटके मिले हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब घर में कोई नहीं था। बेटा संतु राम साहू (47) और बहू बाहर गए हुए थे।

सूचना मिलने पर पुलिस एएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला है कि पति किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जबकि पत्नी सायटिका (कमर और पैर के दर्द) की समस्या से परेशान थी। फिलहाल, घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह घटना कुरुद थाना क्षेत्र के बिरेतरा गांव की है। एक दिन पहले ही दुर्ग जिले के वैशाली नगर इलाके में भी पति-पत्नी अपने घर में मृत पाए गए थे। पहले कमरे में पत्नी का शव मिला, जबकि दूसरे कमरे में पति का शव नायलॉन की मोटी रस्सी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।

जानकारी के अनुसार, बिरेतरा गांव में नंदकुमार साहू (70) पत्नी सुशीला बाई साहू (65) और बेटे-बहू के साथ रहते थे। बेटे-बहू रविवार की शाम किसी निजी काम से बाहर गए हुए थे। सोमवार को गांव की एक महिला किसी काम से बुजुर्ग दंपती के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि घर के 2 अलग-अलग कमरों में नंदकुमार और सुशीला की लाश फंदे पर लटके हुए थे। उसने बताया कि पति नंदकुमार साहू का शव हॉल में पड़ा था, जबकि पत्नी सुशीला बाई साहू का शव एक कमरे में फंदे से लटका हुआ था। महिला ने तुरंत इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वृंदानगर कैंप-1 में जी वेंकटरमण मूर्ति (55) अपनी पत्नी जी विद्यावती (52) के साथ रहते थे। उनका एक लड़का भी है, जो ओडिशा में काम करता है।

सीदी में नीट री-एग्जाम को लेकर भारी मुस्तैदी: एयरफोर्स के विशेष विमान से लाए गए पेपर

- **बस्तर में बने 4 केंद्र**

रायपुर। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए सोमवार को वायुसेना के विमान से प्रश्नपत्र पहुंचाए गए। विमान के पहुंचने के बाद प्रश्नपत्रों को जिला प्रशासन की निगरानी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया।

पुलिस अधिकारी और जवान एयरपोर्ट पहुंच गए थे

प्रश्नपत्रों के आगमन से करीब दो घंटे पहले ही पुलिस अधिकारी और जवान एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि पूरा माहौल किसी वीवीआईपी आगमन जैसा दिखाई दे रहा था। जानकारी के अनुसार संभाग के अन्य जिला मुख्यालयों में प्रश्नपत्र वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष तीन मई को आयोजित नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद 12 मई को निरस्त कर दिया गया था। अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी गई है।

ये हैं परीक्षा केंद्र

बस्तर जिले में परीक्षा के लिए चार केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय धरमपुरा, पीजी कॉलेज धरमपुरा, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर तथा जगतु महरा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला जगदलपुर शामिल हैं।

1450 परीक्षार्थी होंगे शामिल

परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार आसनानी ने बताया कि जिले में लगभग 1450 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा तैयारियों के प्रभारी अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने बताया कि परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

छत्तीसगढ़ में रविशंकर महाराज बनाम सीबीआई

- **याचिका पर हाई कोर्ट ने 24 घंटे में मांगा हलफनामा, 24 जून को अगली सुनवाई**

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ दायर एक अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने रविशंकर महाराज बनाम सीबीआई मामले में फोन इंटरसेप्शन (फोन टैपिंग) के कानूनी पहलुओं को लेकर दोनों पक्षों से शपथ पत्र तलब किया है।

मामले में नए दूरसंचार नियमों (2024) के तहत फोन टैपिंग से जुटाए गए सबूतों की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर

और सीबीआई को 24 जून 2026 तक सक्षम अधिकारी के माध्यम से कोर्ट में जवाब दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया है।

दूरसंचार नियम 2024 का हवाला : सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से देश के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ अधिवक्ता मनु शर्मा (सहयोगी अधिवक्ता पंकज पांडेय, राहुल अंबस्ट, गिरीश त्रिपाठी और कार्तिक खन्ना) ने कोर्ट में जोरदार पैरवी की। उन्होंने दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 के नियम 3 (3) (ङ) का हवाला देते हुए एक बड़ा कानूनी मुद्दा उठाया। उन्होंने दलील दी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28 जून 2025 को जारी फोन इंटरसेप्शन आदेश को नियमानुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर समीक्षा समिति के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जाना अनिवार्य था।

समीक्षा समिति की पुष्टि न होने पर साक्ष्यों की वैधता पर सवाल : अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यदि समीक्षा समिति निर्धारित समय में इसकी पुष्टि नहीं करती है, तो वह आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में, उस निर्धारित अवधि के बाद सीबीआई द्वारा फोन टैपिंग से जुटाए गए किसी भी साक्ष्य को ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) द्वारा विचार में नहीं लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने 28 जून 2025 के इंटरसेप्शन आदेश को मूल याचिका में सीधे चुनौती नहीं दी थी ।

फ्रूटी में मिली फंगस, पीने से बिगड़ी बच्ची की तबीयत

- **खाद्य विभाग ने लिए सैंपल**

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्ची के फरूटी के अंदर फंगस जैसी चीज मिली। इसके बाद बच्ची को एहतियात के तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर खाद्य विभाग की टीम ने जनरल स्टोर से फरूटी की जांच के लिए सैम्पल लिए हैं।

फरूटी पीते ही नजर आई संदिग्ध चीज: मिली जानकारी के अनुसार, मगरलोड के करेलीबड़ी में रहने वाली एक बच्ची ने पास ही के एक जनरल स्टोर से फरूटी खरीदी थी। जब वह घर जाकर उसे पी रही थी, तभी अचानक परिजनों की नजर जूस के डिब्बे के अंदर गई। डिब्बे के भीतर कोई अनजान वस्तु या कीड़े जैसी चीज तैरती हुई नजर आई। इसे देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। एहतियात के तौर पर परिजन तुरंत बच्ची को लेकर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है।

हरकत में आया खाद्य विभाग, लिए गए सैंपल : इस पूरी घटना की भनक लगते ही खाद्य विभाग की टीम तुरंत एक्शन मोड में आ गई। अधिकारियों ने तत्काल उक्त जनरल स्टोर पर छापेमारी की और संबंधित फरूटी के बैच के सैंपल जब्त किए। विभाग अब इस बात की कड़ाई से जांच कर रहा है कि यह माल किस होलसेल दुकान या डीलर के माध्यम से इस रिटेल दुकान तक पहुंचा था।

छत्तीसगढ़ कैडर के 3 नए आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

- **सीएम साय का युवा अफसरों को मंत्र... संवेदनशीलता**

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तीन प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी सफलता के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कि प्रशासनिक सेवा जनसेवा का सबसे प्रभावी माध्यम है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रत्येक निर्णय में जनहित सर्वोपरि होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता, निष्पक्षता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसका उपयोग समाज और आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदेश है। यहां के लोग सरल, सहज, मेहनती और आत्मीय स्वभाव के हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, तेजी से विकसित हो रही कनेक्टिविटी, पर्यटन की संभावनाओं, नक्सल उन्मूलन की सफलता तथा राज्य के विकास की यात्रा से अवगत कराया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और विकास के नए अवसरों पर भी अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को कहा कि ईमानदारी, निष्ठा और जनहित की भावना से लिया गया प्रत्येक निर्णय प्रदेश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर जिलों सहित सरगुजा संभाग के जशपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों का भ्रमण करने का अवसर मिला।

स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान, 30 वाहनों की हुई जांच

- **45 संचालकों को नोटिस जारी**

गरियाबंद। विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गरियाबंद जिले में स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय की संयुक्त टीम ने स्कूल वाहनों की जांच कर सुरक्षा मानकों, दस्तावेजों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 45 स्कूल बस संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

बता दें कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुरूप संचालित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि 15 जून से जिले में संचालित सभी स्कूल बसों का चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा।

30 स्कूल बसों की हुई जांच : जिले में पंजीकृत 75 स्कूल बसों में से 30 बसों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहनों में निर्धारित सड़क सुरक्षा मानकों, आवश्यक उपकरणों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जांच की गई। परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण-पत्र, कर (टैक्स), बीमा, फिटनेस प्रमाण-पत्र और परमिट सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया।

चालक-परिचालकों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण : निरीक्षण अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल बस चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी जांची गई : जिला सेनानी कार्यालय की टीम ने बसों में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों की जांच की और चालक-परिचालकों को इनके उपयोग की जानकारी दी। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर भी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

बलौदाबाजार में नकली खाद का बड़ा खेल

- **ग्रामीणों ने पकड़ी पिकअप, विक्रेता फरार**

बलौदाबाजार। जिले के पलारी क्षेत्र के ग्राम सुंदरावन में किसानों को कथित रूप से नकली एवं संदिग्ध खाद बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने यूरिया और डीएपी के नाम पर खाद बेच रहे बाहरी लोगों की एक पिकअप वाहन को पकड़ लिया। हालांकि, खाद बेचने वाले लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से बाहरी राज्यों से आए कुछ लोग गांव-गांव घूमकर किसानों को किसान खाद के नाम पर यूरिया और डीएपी खाद कम कीमत और तत्काल उपलब्धता का झांसा देकर बेच रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये लोग क्षेत्र में 100 बोरी से अधिक खाद बेच चुके हैं। खाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग पर संदेह होने के बाद ग्रामीणों ने निगरानी शुरू की और एक पिकअप वाहन को रोक लिया।

हरियाणा से आये लोगों ने गाड़ी किराए पर ली थी : पकड़े गए पिकअप वाहन के चालक ने ग्रामीणों को बताया कि हरियाणा से आए कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी किराए पर ली थी और गांवों में खाद बेचने के लिए उसे बुक किया था। चालक ने स्वयं को केवल वाहन चालक बताते हुए खाद की गुणवत्ता और बिक्री की जानकारी नहीं होने की बात कही।

तलाश में जुटी पुलिस : घटना की सूचना तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को दी गई है।

दिल्ली में जनजातीय समागम : धमतरी के अजय ध्रुव हुए शामिल

- **बोले-संस्कृति केवल विरासत नहीं, विकसित भारत का आधार**

नगरी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम में सहभागिता कर लौटे धमतरी जिला पंचायत सभापति अजय ध्रुव ने कहा कि जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति की आत्मा और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के सम्मान, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण शक्ति है जनजातीय समाज : हरिभूमि से विशेष चर्चा में अजय ध्रुव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति मानती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, प्रकृति संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जनजातीय समागम में शामिल अजय ध्रुव :

अजय ध्रुव ने बताया कि जनजातीय सुरक्षा मंच एवं वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भव्य समागम में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, जीवन मूल्यों और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था।

लोकसंस्कृति और परंपराओं का हुआ भव्य प्रदर्शन : समागम में विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा प्रस्तुत लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे।

आफताब आलम को मिला प्रदेश स्तरीय 'रक्त अलंकरण' सम्मान

भिलाई। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सेवक जन फाउंडेशन द्वारा कला मंदिर भिलाई में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में भिलाई निवासी एवं राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय समाजसेवी आफताब आलम को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय 'रक्त अलंकरण' सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रक्तदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, दृष्टिबाधित सेवा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 200 से अधिक संस्थाओं और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल थे। विशेष अतिथियों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, बीएसएफ आईजी संजय पंत, एन.के. बंछोर, परविंदर सिंह, अमित साहू, मनीष पाण्डेय, इंद्रजीत सिंह एवं वीरेंद्र सतपथी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शौर्य चक्र से अलंकृत निरीक्षकों का हुआ सम्मान

निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का दुर्ग पुलिस ने नागरिक अभिनंदन किया

दुर्ग। नक्सल विरोधी अभियानों में असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से अलंकृत निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का सोमवार को दुर्ग पुलिस द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में दोनों अधिकारियों की वीरता और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया।

समारोह में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक तथा पुलिस परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निभाई अहम भूमिका

सम्मान समारोह में दोनों अधिकारियों के सेवा जीवन और नक्सल विरोधी अभियानों में दिए गए योगदान का उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हुए दोनों अधिकारियों ने साहस, धैर्य और नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

निरीक्षक लक्ष्मण केवट

मनेन्द्रगढ़ निवासी निरीक्षक लक्ष्मण केवट ने वर्ष 2007 में पुलिस सेवा में प्रवेश किया था। वर्तमान में वे कांकेर जिले के पखांजूर थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं। बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं देते हुए उन्होंने 40 सफल नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व और साहस के चलते कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन सफल हुए। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें शौर्य चक्र के अलावा छह पुलिस वीरता पदक, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक सहित अनेक राष्ट्रीय एवं विभागीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख

दुर्ग जिले के झोला गांव निवासी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख ने वर्ष 2007 में पुलिस सेवा की शुरुआत की थी। वर्तमान में वे कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर में सेवाएं देते हुए उन्होंने 25 सफल नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनकी वीरता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें शौर्य चक्र, पुलिस वीरता पदक, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक तथा अन्य महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

शौर्य चक्र वीरता और समर्पण का प्रतीक

कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि शौर्य चक्र देश का शांतिकाल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान उन सैन्य, अर्धसैनिक बलों, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया हो।

युवाओं और पुलिस बल के लिए प्रेरणा

पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख की उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार और दुर्ग जिले के लिए गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों की कार्यशैली, समर्पण और साहस युवा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण के साथ किया गया कार्य अंततः सम्मान और पहचान दिलाता है। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने दोनों अधिकारियों का खड़े होकर स्वागत किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना की।

कृषि पंपों में कैपेसिटर: बेहतर वोल्टेज, बेहतर फसल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) दुर्ग क्षेत्र ने समस्त किसानों से अपने कृषि पंपों में उचित क्षमता का कैपेसिटर अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की है। दुर्ग रीजन के अंतर्गत दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में लगभग 01 लाख 50 हजार से अधिक कृषि पंप संचालित हैं। विद्युत अभियांत्रिकी के नियमानुसार, इंडक्शन मोटरें कार्य करने के लिए विद्युत लाइन से वास्तविक पावर के साथ-साथ रिएक्टिव पावर भी लेती हैं, जिससे मोटर का पावर फैक्टर कम हो जाता है। इस वजह से मोटरें आवश्यकता से अधिक करंट (एम्पीयर) लेती हैं, जिससे न केवल बिजली का अनावश्यक नुकसान होता है, बल्कि वोल्टेज ड्रॉप और ट्रांसफार्मर के बार-बार खराब होने जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।

खरीफ सीजन में जब लाखों की संख्या में पंप एक साथ चलते हैं, तो सिस्टम पर रिएक्टिव लोड का दबाव बढ़ जाता है, जो कुल लोड का लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक हो सकता है। यह ओवरलोडिंग वितरण ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप खेतों में न केवल पानी की आपूर्ति कम हो जाती है बल्कि पंप जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि केवल नए उपकेंद्रों या लाइनों के विस्तार से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है, क्योंकि इसमें समय और भारी बजट लगता है। इसका सबसे प्रभावी और त्वरित तकनीकी समाधान मोटर के टर्मिनल पर कैपेसिटर लगाना ही है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों (छ.ग. राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011) के अनुसार, किसानों को अपनी मोटर की क्षमता के अनुरूप कैपेसिटर स्थापित करना अनिवार्य है। इसके तहत 03 अश्वशक्ति(एचपी) तक की मोटर के लिए 01 केवीएआर, 03 से 05 एचपी के लिए 02 केवीएआर, 05 से 7.5 एचपी के लिए 03 केवीएआर, 7.5 से 10 एचपी के लिए 04 केवीएआर और 10 से 15 एचपी की मोटर के लिए 05 केवीएआर क्षमता का कैपेसिटर लगाना आवश्यक है।

सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संजय खंडेलवाल ने कहा कि कैपेसिटर का उपयोग न केवल वोल्टेज की समस्या को दूर करेगा, बल्कि यह पंप की कार्यक्षमता को बढ़ाकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा एवं विद्युत उपकेंद्रों में भार को कम करेगा। कैपेसिटर की लागत, खराब पंप को बार-बार बनवाने या जलने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की तुलना में अत्यंत कम है। उन्होंने दुर्ग क्षेत्र के सभी कृषकों से अपील करते हुए कहा कि कृषक इस प्रमाणित तकनीकी उपाय को अपनाकर विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और अपनी सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने में सहयोग करें।

नगरपालिका में अफसरशाही हावी है: डिकेश पटेल

कुम्हारी। नगरपालिका परिषद कुम्हारी में आयोजित प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में अनुपस्थित एक सदस्य पार्षद डिकेश पटेल ने चुप्पी तोड़ते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमे उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा हमे पी आई सी के बैठक की सूचना मात्र दी जाती है। लेकिन किसी भी सदस्य को बैठक के एजेंडा की कॉपी नहीं दी जाती है। साथ ही एजेंडा की कॉपी मांगने पर बैठक के दिन ही तत्काल उसी समय दिया जाता है। कुम्हारी नगरपालिका में अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है। पालिका के अधिकारी पी आई सी के सदस्यों और पार्षदों की बात सुनते नहीं। गर्मी को देखते हुए 1करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपए का पाईप लाइन विस्तारीकरण का टेंडर हुआ था किन्तु पालिका के अधिकारी और पालिका द्वारा अभी तक वर्क आर्डर जारी नहीं किया गया। जबकि गर्मी का मौसम भी लगभग समाप्ति की ओर है। इन सभी को जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। पी आई सी की बैठक में सिर्फ प्रस्ताव पास करते है मगर धरातल पर कुछ काम होता नहीं है।

पी आई सी सदस्य डिकेश पटेल ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका परिषद कुम्हारी में पी आई सी की बैठक नाम मात्र की होती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कई प्रकार के नियमो का हवाला देकर एजेंडा के कार्यो में अवरुद्ध उत्पन्न करते है। पालिका में अधिकारियों की मनमानी चलती है और जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना किया जाता है।

स्वनिधि महोत्सव एवं लोक कल्याण मेला का आयोजन हुआ

जामुल। नगर पालिका जामुल में पी.एम.स्वनिधि के अंतर्गत विशेष अभियान के तहत स्वनिधि महोत्सव एवं लोक कल्याण मेला का आयोजन किया गया। जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने 15 पात्र हितग्राहियों को चेक वितरण किया। नपा अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि आत्म निर्भर भारत निर्माण की दिशा में छोटे फुटकर व्यवसायियों को आगे व्यवसाय बढाने हेतु हमारे केन्द्र सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। इसी परिपेक्ष में विशेष अभियान के तहत नगर पालिका जामुल क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, सेलुन, दर्जी, मोची, मनियारी अन्य छोटे विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने लोन प्रदान किया जा रहा है। लोन वितरण का यह प्रथम चरण है। दुसरे आयोजन 17 जुन को इसी कार्यालय में और आयोजित होगा।

GST रजिस्ट्रेशन नम्बर बनवाएं मात्र 3 दिन में
5 साल पुरानी ITR फाइल बनवाएं
मात्र 5000/- में
(व्हाट्सएप पर बनवाएं)
www.onlytds.com
GST-Return
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
TDS रिफंड
CMA DATA
MSME रजिस्ट्रेशन
Food लाइसेंस
संपर्क - शेखर गुप्ता 9300755544, 8878655544

आईआईटी भिलाई का फ्रांस की कंपनी के साथ एमओयू

भिलाई। आईआईटी भिलाई ने फ्रांस के नीस में 14-16 जून 2026 तक चल रहे भारत इनोवेट्स (भारतीय शिक्षा इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल एक्सेलेरेशन) कार्यक्रम के दौरान इकोल सेंट्रेल डी नैनटेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एमओयू दोनों संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों और छात्रों के बीच शैक्षिक, पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय समझ, शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक मेलजोल और दोस्ती को बढ़ाने के लिए एक ढांचा तैयार करता है। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं: फैकल्टी सदस्यों का आदान-प्रदान और संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियां; छात्रों का आदान-प्रदान; निजी और/या सरकारी प्रायोजकों द्वारा वित्तपोषित साझा हितों वाले बहु-राष्ट्रीय और बहु-संस्थागत सहयोग स्थापित करने के लिए संयुक्त शोध गतिविधियां। यह साझेदारी वैश्विक शैक्षणिक जुड़ाव को मजबूत करने और शिक्षा, शोध तथा इनोवेशन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

1200 वर्गमीटर से अधिक भूमि को कब्जामुक्त कराया गया

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने सोमवार तड़के शहर में अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को अंजाम देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच चलाए गए अभियान में मदरसा, स्कूल, बाउंड्रीवाल समेत विभिन्न निर्माणों को ध्वस्त कर लगभग 1200 वर्गमीटर से अधिक भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।

आरक्षित भूमि पर वर्षों से था कब्जा : नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई वार्ड क्रमांक 7 के आनंद नगर और उल्लास नगर क्षेत्र में की गई। राजस्व ग्राम कोहका के खसरा नंबर 293/5 एवं 293/6 की भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास निर्माण के लिए आरक्षित है। आरोप है कि इस भूमि पर वर्षों से विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि पर मदरसा, कर्बला, आवासीय निर्माण तथा एक निजी स्कूल की बाउंड्रीवाल बनाई गई थी, जिससे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग बाधित हो रहा था।

कई बार नोटिस, फिर भी नहीं हटाया गया कब्जा : नगर निगम के मुताबिक अतिक्रमणकारियों को समय-समय पर नोटिस जारी कर भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने और स्वयं कब्जा हटाने का अवसर दिया गया था। हालांकि निर्धारित अवधि में न तो कब्जा हटाया गया और न ही स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद निगम ने बेदखली की कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

वर्षों से लंबित था मामला : जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रयास पूर्व में भी कई बार किए गए थे। वर्ष 2014, 2018, 2020 और 2025 में कार्रवाई की तैयारी की गई, लेकिन कानून-व्यवस्था की आशंका और पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं होने के कारण अभियान को पूरा नहीं किया जा सका। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी मामले को लेकर उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखाः सारंगढ़ (छ.ग.)
Central Bank of India Branch: Sarangarh (C.G.)

यतः **परिशिष्ट-4 नियम-8 (1) कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)**

अधोहस्ताक्षरी ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 का अधिनियम के अधीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी हैं, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधार लेने वाले को निम्नलिखित तिथि को एक मांग नोटिस में उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज उक्त नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी। उधार लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, उधार लेने वाले और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधार लेने वाले को विशिष्ट रुप से और जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह इस संपत्ति से संबंधित कोई व्यवहार न करें एवं यदि करता है तो वह निम्नलिखित देय धनराशि तथा उस पर देय ब्याज तथा व्यय के लिए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभार के अधीन होगा।

देनदार का ध्यान रक्षित संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय हेतु अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/जमानतदार का नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/राशि
1.	**ऋणीः मेसर्स आयुष ट्रेडर्स प्रोप. श्री जीवन राम रात्रे एवं जमानतदार श्रीमती रेवती रात्रे**	1) **श्री जीवन राम रात्रे** के नाम पर प्लॉट नं. **57/2 एवं 57/5** पर स्थित, आवासीय उपयोग के लिए बदली गई जमीन और उस पर बनी इमारत का पूरा हिस्सा, क्षेत्रफल क्रमशः **0.1660** हेक्टेयर और **0.2260** हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल **0.3920** हेक्टेयर), यह संपत्ति वार्ड नं. 4, चंद्रशेखर वार्ड, ग्राम- चिंगरीपाली, प.ह.नं. 61, रा.नि.मं. सारंगढ़, नगर पालिका सारंगढ़, तहसील- सारंगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ । इसे 25/05/2022 को सब-रजिस्ट्रार सारंगढ़ के यहाँ रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड नंबर 918 (बुक नंबर 1, ग्रंथ नंबर 7394, पेज 260 से 281) के जरिए हासिल किया गया था। गिफ्ट डीड के अनुसार **चौहद्दीः खसरा नं. 57/2ः उत्तर-** रेवती, **दक्षिण-** जोहित, **पूर्व-** विजय, **पश्चिम-** मोहन प्यारे । **खसरा नं. 57/5ः उत्तर-** जीवन, सड़क, **दक्षिण-** रेवती, **पूर्व-** विजय, **पश्चिम-** मोहन प्यारे । रायगढ़ जिले के बंटवारे के बाद, ऊपर बताया गया खसरा अब सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले में स्थित है ।	07/03/2026 ₹ 4,33,48,947.35 + ब्याज एवं अन्य शुल्क कब्जा लेने की तारीख 10/06/2026

2) **श्रीमती रेवती रात्रे पति श्री जे. आर. रात्रे** के नाम पर जमीन खसरा नं. **558/4Ga और 560/4Ga** जिन्हें बाद में B1 रिकॉर्ड के अनुसार मिलाकर नया खसरा नंबर **15041** दिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल **0.040** हेक्टेयर है। यह भूमि ग्राम- सारंगढ़ (प.ह.नं. 28, रा.नि.मं. सारंगढ़, तहसील- सारंगढ़, जिला- रायगढ़ में जायसवाल एग्रीकल्चर फार्म से टेंगनापली तक जाने वाले कैनाल रोड के किनारे स्थित है। यह संपत्ति एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (दान-पत्र) नंबर 6277 के जरिए हासिल की गई थी, जो दाता **श्री जीवन लाल पुत्र स्व.झिंगुट** और प्राप्तकर्ता **श्रीमती रेवती रात्रे** के बीच हुई थी। इसे सब-रजिस्ट्रार सारंगढ़ के यहाँ 06/05/2017 को दस्तावेज सं. **6277** के तहत रजिस्टर किया गया था। गिफ्ट डीड के अनुसार इसकी **चौहद्दीः इस प्रकार हैं - खसरा नं. 558/4Ga और 560/4Gaः उत्तर** - कैनाल रोड, **दक्षिण** - तालाब, **पूर्व** - गनेशू की जमीन, **पश्चिम** - ईश्वर देवांगन व परदेशी की भूमि ।
रायगढ़ जिले के बंटवारे के बाद, ऊपर बताया गया खसरा अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित है ।

3) **श्री जीवन** के नाम पर मौजूद जमीन और इमारत का वह हिस्सा जो खसरा नं. **57/4** (क्षेत्रफल **0.1860** हेक्टेयर) में आता है एवं ग्राम- चिंगरीपाली, प.ह.नं. 61, रा.नि.मं.- सारंगढ़, तहसील- सारंगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित यह संपत्ति बंटवारे के उस डीड (दस्तावेज नंबर 1511) के जरिए हासिल की गई थी, जिसे 27/06/2022 को सब-रजिस्ट्रार सारंगढ़ के यहाँ बुक नं. 1, ग्रंथ नं. 7430 में पेज नंबर 253 से 274 पर रजिस्टर किया गया था। यह डीड **श्री झिंगुर के बेटे श्री जीवन (पहला पक्ष) और स्व.संदीप की पत्नी श्रीमती शारदा, स्व. संदीप के पुत्र मास्टर पीयूष और स्व. संदीप की पुत्री मिस बसुंधरा (दूसरा पक्ष)** के बीच हुआ था। ऊपर बताए गए डीड के अनुसार इसकी **चौहद्दी इस प्रकार हैं- श्री जीवन का खसरा नं. 57/4 (क्षेत्रफल 0.1860): उत्तर**- राजेंद्र मत्री की भूमि, **दक्षिण-** जीवन राम की भूमि, **पूर्व-** श्रीमती शारदा की भूमि का हिस्सा, **पश्चिम-** श्री जीवनराम की निजी सड़क ।
रायगढ़ जिले के बंटवारे के बाद, ऊपर बताया गया खसरा अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित है ।

4) **मेसर्स जे.के. फ्लाई ऐश ब्रिक्स एण्ड ब्लॉक्स** के नाम पर डायवर्ट की गई इंडस्ट्रियल जमीन का पूरा हिस्सा, जिसका खसरा नं. **558/3Kha और 560/3Kha** , कुल क्षेत्रफल **0.081** हेक्टेयर है। यह जमीन रायगढ़-सारंगढ़ मेन रोड से लगभग 200 मीटर और नगर पंचायत सारंगढ़ से लगभग 3 किमी दूर स्थित है ग्राम- टेंगनापली, सारंगढ़ (ग्रामीण इलाका), प.ह.नं. 20/28, ग्राम पंचायत पानीसागर, रा.नि.मं. सारंगढ़, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़)। यह जमीन सेल डीड नंबर **5685, Ad/1** के जरिए हासिल किया गया था। पेज 36 से 50 तक, जिसे 24/08/2015 को सब-रजिस्ट्रार सारंगढ़ के यहाँ रजिस्टर किया गया था। यह डीड खरीदार **मेसर्स जे.के. फ्लाई ऐश ब्रिक्स एण्ड ब्लॉक्स प्रोप्राइटर श्रीमती रेवती रात्रे पति श्री जीवन रात्रे** और विक्रेताओं - **श्री प्रेमलाल पिता कंचन प्रसाद, सुश्री राधा बाई पिता तुलसीराम, श्री दिनेश कुमार मोवार पिता तुलसीराम, सुश्री बृहस्पति मोवार पिता तुलसीराम, सुश्री सरस्वती पिता तुलसीराम, सुश्री सोनकुंवर पति श्री तुलसीराम, सुश्री सुशीला बाई पिता कंचन प्रसाद, श्री उमाप्रसाद पिता श्री कंचन प्रसाद, सुश्री रामबाई पति कंचन प्रसाद** के बीच निष्पादित की गई थी। इसकी चौहद्दी ऊपर बताई गई डीड के अनुसार हैं। **खसरा नं. 558/3Kha और 560/3Kha : उत्तर-** मेसर्स जे.के. फ्लाई ऐश ब्रिक्स एण्ड ब्लॉक्स की जमीन, **दक्षिण-** नहर, **पूर्व-** सुंदर की जमीन, **पश्चिम-** नेहरू मैत्री की जमीन।
रायगढ़ जिले के उप-विभाजन के बाद, ऊपर बताया गया खसरा अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित है।

5) **मेसर्स जे.के. फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ब्लॉक** के नाम पर खसरा नं. **557/10, 0.061** हेक्टेयर और खसरा नं. **558/4/खा और 560/4** हेक्टेयर, दोनों **0.101** हेक्टेयर और सभी 3 भूमि, **0.162** हेक्टेयर, रायगढ़ रोड, ग्राम- टेंगनापाली, प.ह.नं. 28 (जीए. एलए. 20) तहसील- सारंगढ़, जिला रायगढ़, बिक्री विलेख के माध्यम से प्राप्त किया गया भूमि व भवन के सभी हिस्से जिसका दस्तावेज क्र. **5159, एडी1**, पृष्ठ 59 से 69 उप-रजिस्ट्रार सारंगढ़ के पास 13/01/2014 को पंजीकृत, विक्रेता के रूप में **श्री जीवन लाल रात्रे पुत्र स्व.झिंगुतराम रात्रे** और क्रेता के रूप में **मेसर्स जे.के. फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, प्रोपराइटर श्रीमती रेवती रात्रे** के बीच निष्पादित किया गया- उपर्युक्त विलेख के **अनुसार निम्नलिखित चौहद्दीः खसरा नं. 557/10, 558/4/खा और 560/4खाः उत्तर-** अमरू की भूमि, **दक्षिण-** सड़क, **पूर्व-** फार्म अश्मान, **पश्चिम-** नेहरू का फार्म । रायगढ़ जिले के उप-विभाजन के बाद, ऊपर बताया गया खसरा अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित है।

6) **श्री जीवन रात्रे पुत्र श्री झिंगुट राम रात्रे** के नाम पर है। खसरा नं. **558/3 घ और 560/3 घ** (कुल **0.040** हेक्टेयर) में मौजूद जमीन और उस पर बनी इमारत। यह संपत्ति गाँव टेंगनापाली, चंद्रपुर रोड, सारंगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 3, प.ह.नं. 20, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है यह संपत्ति बंटवारे की डीड (दस्तावेज सं. 10326, जिसे 13/03/2009 को सब-रजिस्ट्रार सारंगढ़ के यहाँ रजिस्टर किया गया था) के जरिए हासिल की गई थी। यह डीड **श्री जीवन राम रात्रे पुत्र स्व.श्री झिंगुट और श्री गणेशु पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ व श्री संदीप पुत्र स्व. श्री झिंगुट** के बीच हुई थी। नजरी नक्शे के अनुसार इसकी **चौहद्दी इस प्रकार हैं- खसरा नं. 558/3 घ और 560/3 घः उत्तर-** सड़क, नहर, **दक्षिण-** श्री गणेशु की जमीन, **पूर्व-** श्री संदीप की जमीन, **पश्चिम-** सारंगढ़ रायगढ़ रोड ।
रायगढ़ जिले के विभाजन के बाद, ऊपर बताया गया खसरा अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित है ।

गिरवी रखी गई सभी चल संपत्तियों का विस्तृत विवरणः
चल संपत्ति-
1) कच्चे माल का स्टॉक, WIP (प्रक्रियाधीन कार्य), स्टोर और स्पेयर पार्ट्स, तैयार माल, उपभोग्य स्टोर और स्पेयर पार्ट्स
2) सिविल कार्य, प्लांट एवं मशीनरी तथा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ।

दिनांकः 15.06.2026, स्थान- सारंगढ़ (छ.ग.) — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

महापौर निधि के कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों से मांगी प्रगति रिपोर्ट

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर अलका बाघमार की अध्यक्षता में महापौर कक्ष में शहर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत व महापौर निधि के किए जा रहे कार्यों, सड़क डामरीकरण, सीमेंट कांक्रीट सड़कों, नाली-पुलिया निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था एवं शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।

महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की तथा कार्यों को निर्धारित समयसीमा एवं मानक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने महापौर निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जानकारी ली कि एक वर्ष में प्राप्त 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि से कितने कार्य पूर्ण हुए हैं तथा कितने कार्य प्रगतिरत अथवा शेष हैं। उन्होंने पुराने कार्यों के साथ-साथ नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं फील्ड में उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकें। भूमिपूजन के उपरांत संबंधित स्थल पर शिलापट्ट स्थापित करने तथा कार्य की प्रगति का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड संधारित कर जानकारी साझा करने के भी निर्देश दिए गए।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें।

पनेका के एमजीएम स्कूल में अवैध चर्च बनाकर धर्मांतरण का आरोप

- **कलेक्टर-एसपी को ज्ञापन**

राजनांदगांव। शहर के नजदीकी ग्राम पनेका स्थित एमजीएम स्कूल में अवैध रूप से चर्च संचालित कर हिंदुओं और स्कूली बच्चों का धर्मांतरण (मतांतरण) कराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिलाधीश और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

हिंदू जागरण मंच ने शिकायत में बताया कि पनेका के इस संस्थान को सिर्फ स्कूल संचालन की अनुमति प्रशासन से मिली थी। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर स्कूल परिसर के भीतर ही अवैध रूप से चर्च का निर्माण और संचालन किया जा रहा है। यहां प्रत्येक रविवार को विशेष प्रार्थना सभा रखी जाती है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के अलावा दूर-दराज और बाहरी इलाकों से संदिग्ध लोगों को बुलाया जाता है। आरोप है कि यहां पढ़ाई कर रहे मासूम बच्चों और सीधे-साधे ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर मत्तांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिससे सनातन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने प्रशासन से दो टूक मांग की है कि इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाए। यह समिति स्कूल के भीतर चल रही संदिग्ध गतिविधियों और फंडिंग की जांच करे।

राम नाम की लूट है... अयोध्या मंदिर में चढावे के चोरी का विवाद

संपादकीय

'राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट।'

कबीर का यह दोहा आध्यात्मिक चेतना का संदेश था। इसका आशय यह था कि जीवन रहते हुए ईश्वर के नाम, सत्य, मर्यादा और सदाचार को आत्मसात कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन विडंबना देखिए कि भारत के मंदिरों से जुड़े अधिकांश भक्तों और कर्मचारी ने इसका अर्थ अपने हिसाब से तय कर लिया कि राम के नाम पर जो भी चंदा और दान आया है, उसे मंदिर के भक्त लूट सकते हैं और वह इसकी लूट में लग गए। मंदिर से जुड़े कर्मचारी-भक्त रातों-रात अमीर हो गए हैं। लोग कहते हैं कि अब राम को ही लूट रहे हैं, क्योंकि जो चंदा और दान आया था वह राम के लिए आया था। राम के कुछ काम आता है, उसके पहले भक्तों राम का धन लूट लिया। हमारे शहर के पुजारी जी का कहना है यदि पुजारियों और भक्तों ने राम के नाम का आया पैसा लूट भी लिया तो क्या गलत किया? राम भगवान क्या पैसों को लेकर बाजार में खरीदारी करने जाते? अब राम नाम की लूट आध्यात्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक होती दिखाई दे रही है। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और ईश्वर के नाम पर चल रही लूट के नए-नए रूप लगातार सामने आ रहे हैं।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों से राशि चोरी होने के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश धर्म प्रधान सरकार को एसआईटी गठित करनी पड़ी है। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमत निकेतन मंदिर के दानपात्रों में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। इससे पहले तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। वहां पर नकली घी से लड्डू बनाए जा रहे थे। वहां के पुजारियों का भी तर्क बिल्कुल उचित था कि लड्डू कोई भगवान तो खा नहीं रहे थे, जो उनकी तबीयत खराब होती। लड्डू तो भक्त खा रहे थे और एक लड्डू में भक्त कौन से मर जाते हैं?

दरअसल, जब हर चीज बाजार के हवाले हो रही है तो धर्म और भक्ति को भी इस दलदल में गिरना ही था। इन घटनाओं को अलग-अलग मामलों के रूप में देखने के बजाय एक व्यापक संकट के रूप में देखने की आवश्यकता है। यह संकट केवल वित्तीय अनियमितताओं का नहीं, बल्कि लोगों की आस्था पर चोट का है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को लोभ, मोह और अहंकार से दूर करना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जैसे धार्मिक स्थल मनुष्य को आत्मशुद्धि और नैतिकता का मार्ग दिखाने के लिए बने थे। लेकिन नासमझ जनता को मालूम नहीं कि आत्मा की शुद्धि और नैतिकता का मार्ग सामान्य लोगों के लिए है। मंदिरों के कर्मचारी और भक्त हैं, जो सीधे भगवान के संपर्क में हैं। उनके लिए शुद्धता, नैतिकता और ईमानदारी अलग होती है। अब मंदिरों के आसपास बड़े पैमाने पर दुकानें बनने लगी हैं। धर्म और भक्ति का बाजार सजा हुआ है। इन स्थलों के आसपास धन, व्यवसाय और सत्ता का जाल बुनने लगा है। धर्म का स्वरूप बदलने लगा है। भक्ति की जगह बाजार और श्रद्धा की जगह लोभ लालच का गणित हावी होने लगा है। चंदे और दान का पैसा गिनने वाले कर्मचारी अपना गणित अलग लगाते हैं। वे इसे धर्म के नाम पर बेईमानी, भ्रष्टाचार और अनैतिकता नहीं मानते हैं। कुछ कहा जाए तो वे खुद कहते हैं कि राम के नाम पर लूट की छूट मिली हुई है। संत का गए हैं कि, 'राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट!' जब संतों ने कह दिया तो फिर क्या दिक्कत! हम लूट सकते हैं। हमारे पास लूटने की सुविधा है। अवसर है, ताकत है।

यह सच है कि बड़े मंदिरों में करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है। महाकाल मंदिर में एक वर्ष में 65 करोड़ रुपये के लड्डू प्रसाद की बिक्री इसका उदाहरण है। इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि श्रद्धालु प्रसाद खरीद रहे हैं, मंदिर प्रशासन गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रख रहा है तथा उस धन का उपयोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हो रहा है, तो यह धार्मिक अर्थव्यवस्था का सकारात्मक पक्ष माना जा सकता है। यह सब सुनने में बहुत भला लगता है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां धन का हिसाब गड़बड़ हो जाता है। जहां चढ़ावे पर कुछ लोगों का लोभी भक्ति और आस्था का कब्जा हो जाता है। मंदिर का रुपया हड़पने वाले कर्मचारियों का कथित कथन है कि हमने भगवान की सेवा की है तो यह मेवा मिला है।

मंदिरों में अब हर चीज के लिए पैसा लगता है। कहा जाता है कि प्रसाद की दुकानें मंदिर के पुजारियों या महंतों के मनपसंद ठेकेदारों के कब्जे में होती हैं। कहीं वीआईपी दर्शन की अलग व्यवस्था है तो कहीं सामान्य भक्त घंटों धक्के खाते हैं। कई जगहों पर प्रसाद और पूजा सामग्री की ऐसी एकाधिकार व्यवस्था बना दी गई है कि श्रद्धालु को मजबूरी में निर्धारित दुकानों से ही सामान खरीदना पड़ता है। यह स्थिति किसी आध्यात्मिक केंद्र की नहीं, बल्कि एक नियंत्रित बाजार की है। विडंबना यह भी है कि जो लोग भक्तों को ईश्वर के भय और कर्मफल का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हीं धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और चंदे और दान की कथित खुली लूट है। अब ये आरोप आम जन तक फैल गए हैं। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि यदि मंदिर के दानपात्र से पैसा चोरी हो रहा है, यदि नकली नोट चढ़ावे के नोट से बदले जा रहे हैं। यदि धार्मिक ट्रस्टों की संपत्तियों पर कथित बाहुबलियों के कब्जे हो रहे हैं, तो यह कानून का मामला तो है ही लेकिन यह नैतिक पतन का चरम है जो धर्म के संरक्षण के दावे करने वालों के भीतर भी घर कर चुका है।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि मंदिरों में आने वाला धन आखिर किसके लिए है? हिंदू संगठनों का एक वर्ग लंबे समय से यह मांग करता रहा है कि मंदिरों की आय का उपयोग हिंदू समाज के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण में होना चाहिए। दूसरी ओर कई मंदिरों की संपत्तियों और आय पर सरकारी नियंत्रण को लेकर भी बहस होती रही है। लेकिन इस बहस का मूल प्रश्न पारदर्शिता होना चाहिए। चाहे प्रबंधन सरकार करे, ट्रस्ट करे या समाज, हर रुपये का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि यह धन किसी व्यक्ति का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का धन है। धर्म का अर्थ को लूट का पर्याय होने से बचाना होगा। राम त्याग के प्रतीक हैं, कृष्ण कर्म के, बुद्ध करुणा के और महावीर अहिंसा के। इन महापुरुषों ने संग्रह नहीं, समर्पण का मार्ग दिखाया। यदि उनके नाम पर चलने वाली संस्थाएं ही संग्रह, लोभ, लालच, लूट और लाभ के केंद्र बन जाएं, तो यह उनके आदर्शों के साथ अन्याय है।

करोड़ों लोगों की श्रद्धा धार्मिक संस्थाओं से उठ जाएंगी। आज आवश्यकता मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थाओं को बदनाम करने की नहीं, बल्कि उन्हें अधिक जवाबदेह बनाने की है। अधिकांश श्रद्धालु ईश्वर को कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास के भाव से चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसलिए उस चढ़ावे की रक्षा करना, उसका पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना और धर्मस्थलों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। यदि धर्म के नाम पर चल रही आर्थिक लूट को नहीं रोका गया, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी मंदिर, ट्रस्ट या सरकार का नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान उस आस्था का होगा, जो सदियों से भारतीय समाज की आत्मा रही है।

सैन्य परंपराओं और पोशाक में ऐतिहासिक बदलाव

-महेन्द्र तिवारी

भारतीय सेना का इतिहास पराक्रम, शौर्य और अप्रतिम बलिदान की गाथाओं से समृद्ध है। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। हालांकि, स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी सेना की कुछ आंतरिक व्यवस्थाओं, नियमों, पोशाक और प्रतीकों में ब्रिटिश काल की स्पष्ट छाप दिखाई देती थी। वर्तमान समय में भारतीय सेना अपनी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक युगांतरकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सेना द्वारा अपनी वेशभूषा नीति, औपचारिक परंपराओं और सदियों पुराने रीति-रिवाजों में किए जा रहे बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि अब देश अपनी औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुका है। इन महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराकर विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अपनी ऐतिहासिक जड़ों से गहराई से जोड़ना है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत सरकार के उन 5 महासंकल्पों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिन्हें पंच प्रण के नाम से जाना जाता है। इन संकल्पों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रण गुलामी की हर सोच और उसके प्रत्येक प्रतीक से पूर्ण मुक्ति पाना है, जिसे भारतीय सेना अब धरातल पर पूरी निष्ठा के साथ उतार रही है।

सैनिक परंपराओं में सबसे पहला और प्रत्यक्ष बदलाव सैन्य कवायद और आधिकारिक समारोहों के दौरान देखा जा सकता है। ब्रिटिश शासनकाल से ही यह व्यवस्था निरंतर चली आ रही थी कि जब भी कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी किसी सैनिक कदमताल या विदाई समारोह की सलामी लेता था, तो वह समीक्षा अधिकारी के रूप में अपने साथ एक विशेष औपचारिक तलवार रखता था।

यह तलवार ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी शक्ति, सर्वोच्च कमान और भारतीय सैनिकों पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करने का एक मुख्य माध्यम मानी जाती थी। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संप्रभु राष्ट्र में इस तरह के सामंती प्रतीकों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब समीक्षा अधिकारी द्वारा सैन्य मार्च के दौरान या किसी भी अन्य औपचारिक निरीक्षण में तलवार रखने की इस पुरानी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा अपनी कमान और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में ले जाई जाने वाली विशेष छड़ी के उपयोग की भी गहन समीक्षा की गई है और इसके इस्तेमाल को अब बेहद सीमित कर दिया गया है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारतीय सेना में नेतृत्व और सम्मान का आधार कोई बाहरी वस्तु या औपनिवेशिक दिखावा नहीं, बल्कि अधिकारी की अपनी योग्यता, कर्तव्यपरायणता और अपने देश के प्रति अटूट निष्ठा है।

इस वैचारिक परिवर्तन का सीधा और गहरा असर सैन्य अधिकारियों के पहनावे और पोशाक से जुड़े नियमों पर भी दिखाई दे रहा है। एक लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि सैन्य अधिकारियों के भोजनालयों और अन्य महत्वपूर्ण औपचारिक आयोजनों में पश्चिमी देशों के कोट, औपचारिक वस्त्रों और गले के बंध का ही प्रचलन अनिवार्य बना हुआ था। भारतीय जलवायु और यहाँ की गौरवशाली संस्कृति के सर्वथा विपरीत इस तरह के विदेशी पहनावे को ढोना भी एक प्रकार की मानसिक परतंत्रता का ही हिस्सा माना जा सकता है। इस पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अब अधिकारियों की औपचारिक पोशाक में पहली बार %बंदी% नाम के पारंपरिक भारतीय परिधान को आधिकारिक तौर पर स्थान दिया गया है। यह बिना आस्तीन का एक विशेष वस्त्र है, जिसे आम बोलचाल में पारंपरिक कुर्ता या भारतीय नेहरू वेशभूषा के रूप में भी जाना जाता है। अब सैन्य अधिकारी इसे अपनी कमीज और पतलून के साथ अत्यंत गर्व से धारण कर सकते हैं। यह कदम न केवल भारतीय वस्त्र उद्योग और स्थानीय शिल्पकला को नया सम्मान देता है, बल्कि सैन्य जीवनशैली में एक विशिष्ट भारतीय पहचान का समावेश भी करता है। इसके माध्यम से यह दृढ़ संदेश दिया गया है कि हमारे अपने पारंपरिक परिधान भी दुनिया के किसी भी उच्च स्तरीय आधिकारिक आयोजन के लिए पूरी तरह से गरिमापूर्ण और सर्वश्रेष्ठ हैं।

परंपराओं के इस शुद्धिकरण के अंतर्गत केवल पहनावा ही नहीं बदला गया है, बल्कि अधिकारियों की विदाई के तौर-तरीकों में भी बड़े सुधार किए गए हैं। पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार, जब भी सेना के शीर्ष पदों पर आसीन अधिकारी, जैसे थल सेनाध्यक्ष या सैन्य कमान प्रमुख अपनी लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते थे, तो उन्हें विदाई देने के लिए घोड़ों से खिंचने वाली एक पुरानी पारंपरिक बग्घी का उपयोग किया जाता था। यह घोड़ों वाली बग्घी प्रथा पूरी तरह से ब्रिटिश राजसी ठाट-बाठ और आम जनता तथा साधारण सैनिकों से दूरी बनाए रखने की औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित थी, जो एक लोकतान्त्रिक देश की सेना में उचित नहीं जान पड़ती थी। अब सेना ने इस सामंती विदाई प्रथा को भी हमेशा के लिए बंद करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। अब अधिकारियों की विदाई बेहद सादगीपूर्ण, अनुशासित और भारतीय मूल्यों के अनुरूप की जाती है। यह बदलाव सैन्य अधिकारियों और उनके अधीन काम करने वाले जवानों के बीच की दूरी को कम करने तथा सेना के भीतर एक समतावादी और आत्मीय वातावरण स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है।

सैन्य संस्कृति का एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा उसका संगीत होता है, जो सैनिकों के भीतर अदम्य साहस का संचार करता है। युद्ध के मैदान से लेकर शांति काल के समारोहों तक, सैन्य संगीत दल हमेशा से जवानों में जोश और देशप्रेम की भावना भरते रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमारे विभिन्न सैन्य संगीत दल पुरानी अंग्रेजी और स्कॉटिश धुनों को बजाने के लिए विवश थे। गणतंत्र दिवस उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में वर्षों तक एक विदेशी प्रार्थना धुन बजाई जाती थी, जिसका भारतीय जनमानस से कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। अब इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उस पुरानी विदेशी धुन के स्थान पर %ऐ मेरे वतन के लोगों% जैसी अमर, लोकप्रिय और हृदयस्पर्शी भारतीय देशभक्ति धुन को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेना के सभी संगीत दल अब विदेशी धुनों की बजाय भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और देश की माटी से जुड़ी देशभक्ति की धुनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब सैन्य वाद्यों से भारतीय राग और लोक धुनें निकलती हैं, तो वे न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाती हैं बल्कि पूरे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का काम करती हैं।

इस प्रकार, सैन्य व्यवस्था और उसकी जीवनशैली में किए गए ये सभी बदलाव केवल ऊपरी या सतही परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय समाज और राष्ट्र की सोच में आ रहे एक व्यापक गुणात्मक सुधार को रेखांकित करते हैं। वर्ष 1947 में भले ही हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन प्रशासनिक और सैन्य स्तर पर अपनी जड़ों को पहचानकर पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में यह एक अत्यंत ठोस कदम है। भारतीय सेना द्वारा उठाए गए ये कदम 21वीं सदी के आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वाभिमानी भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

व्यंग्य

अखबार का भविष्यफल

सुदर्शन सोनी

अखबार के बदलते रंग तो हम रोज देख रहे हैं, अब यह अखबार के स्थान पर 'विज्ञापनबार' हो गया है! एक जमाना ऐसा था जब कि अखबार के दोनों शीर्ष पर केवल लघु बाक्स में ही लघु विज्ञापन प्रथम पृष्ठ के इकलौते जुड़वा विज्ञापन होते थे। पहले पृष्ठ से यह विज्ञापन के सफर की शुरुवात थी। इसको भी शुरू में पाठकों ने ठीक नही माना होगा। इस समय तक पहले व दूसरे पृष्ठ और बाद के सभी पृष्ठ तो निश्चित रूप से लगभग पूरे के पूरे केवल समाचारों से बजबजाते थे! समाचारो में इतनी ताकत होती थी कि कोई भी विज्ञापन पूरे पृष्ठ पर कब्जा करने की जुर्रत नही कर सकता था! समाचारों से विज्ञापनों को विकर्षण होता था! फिर एक दौर ऐसा आया कि प्रथम पृष्ठ में विज्ञापनों ने अपनी जमीन तलाशना शुरू किया। पहले एक छोटा सा विज्ञापन दाएँ या बाएँ कोने मे नीचे की ओर आया। इसने धीरे धीरे अपनी ताकत यानी कि आकार बढ़ा ऊपर उठना शुरू किया। विज्ञापन मतलब की एक तरह से व्यापार ने 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की तरह जरा सी जगह तब की समाचार रूपी सरकार से अपने लिए माँगी। हाँ, इस समय तक समाचार की ही समाचार पत्र में सरकार होती थी! और फिर यह सुरसा की तरह मुँह खोलते हुए पहले पृष्ठ के वजूद को ही धीरे धीरे करके लीलने के अपने एक सूत्रीय मिशन मे लग गया, और इसमे यह सफल भी हो गया। नतीजा आज पूरा का पूरा पहला पृष्ठ विज्ञापनी है, अब विज्ञापनों और समाचारों के बीच आर्कषण के युग की शुरुवात हो गई थी। जित्ते समाचार तो कम से कम उत्ते तो विज्ञापन होना ही होना! खिचड़ी समाचार पत्र के युग का आगाज हो गया था! इसको देखकर अब प्रथमदृष्टया समाचार पत्र का भान तो होता ही नही था। बात यहीं तक रहती तो भी चल जाता? अब तो व्यापारिक उद्देश्य वाली 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की तर्ज पर इसने अपने पैर फैलाते हुए दूसरे पृष्ठ में विज्ञापन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसार की बात करें तो एक और शहर में व्यापार के अधिकार प्राप्त कर लिए। अखबार ने इसके बाद तो हर पृष्ठ मे अपने वजूद की संधि विज्ञापन से वैसे ही कर ली जैसे कि कंपनी ने देश के कई शहरों में धीरे धीरे अपने गोदाम व कार्यालय बनाने की संधि कर ली थी! यहीं से कंपनी की सोच में बदलाव शुरू हो गया, वह सोचने लगी की व्यापार मे अव्वल रहने के लिए क्यों न अकेले दम ही इस विशाल देश को ही धीरे धीरे अपने कब्जे मे कर लिया जाए। यहाँ भी वही हुआ! विज्ञापन ने अखबार के दूसरे, तीसरे व अंतिम पृष्ठ तक जीत लिए थे। इनमें कोई समाचार अब घुस ही नही सकता था! यहाँ अघोषित रूप से घोषित हो गया था कि 'समाचारी ट्रेसपासर्स विल बी प्रासीक्यूटेड' यदि कोई स्थान पाता था तो, वह विज्ञापन की दया पर विज्ञापनी समाचार ही होता था जो कि वास्तव मे समाचार तो नहीं होता था, लेकिन उसका एक धोखा वर्जन होता था! विज्ञापन भी यही सोच रहे थे कि अब पूरे अखबार को ही क्यों फतह न कर लिया जाए। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाले भूभाग में भी होता था! ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे पूरे भारत मे धीरे धीरे कब्जा कर लिया उसके लिए उसे एक दो छोटे युद्ध करने पड़े। यहाँ विज्ञापनों ने भी अब लगभग पूरे अखबार पर कब्जा कर लिया था। इसके लिए इसे कोई युद्ध नही लड़ना पड़ा, बस धीरे धीरे जैसे गेहूँ को घुन खाता है, वैसे ही विज्ञापन रूपी घुन समाचार रूपी स्वर्णिम दानों को खाता रहा! अब तो आपको समाचार वाले पन्ने या कि हिस्से ढूँढ़ने पड़ते हैं? कोई भी समाचार बिना विज्ञापन के ग्रहण के आप नही पढ़ सकते हैं? 'अखबार मे समाचार की खोज' नामक खेल भी एक फनी खेल के रूप मे अब खेला जा सकता हैं! आप 'ब्रम्हचर्य आज भी प्रासंगिक है' पर एक समाचार पढ़ रहे हैं और लो न उसके ठीक नीचे कोई सनी लियोनी जैसी मोहतरमा ब्रा व पेंटी का विज्ञापन कातिलाना मुस्कान के साथ कर रहीं हैं! एक पल संयम का ख्याल आया और दूसरे पल आपकी बैंड बज गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रमुख शहरों में अपनी स्थिति मजबूत करने अपने गैरीसन बना लिए थे, वैसे ही अब प्रमुख पृष्ठों पर कब्जा करने विज्ञापनों ने अपने को स्थायी रूप से बैठा अपने 'विज्ञापनी गैरीसन' ही एक तरह से बना लिए। ये विज्ञापनी व्यापार के सिक्योरिटी गार्ड सरीखे हैं। चौनल को जैसे ब्रेक चलाते हैं नहीं तो उसमे स्थायी ब्रेक लग जाए और वैसे ही अखबारों को विज्ञापन चलाते हैं नहीं तो वह भी हमेशा के लिए बैठ जाए। विज्ञापन ने तो एक तरह से अखबार को स्थायी ज्ञापन दे दिया है कि अब समाचार उसकी मर्जी पर ही जिंदा रहेंगे। भविष्य का अखबार अब कैसा होगा? भविष्य मतलब अगली सदी नहीं अगले पंद्रह बीस सालों बाद की बात हो रही है? बस कल्पना करना बाकी है। आज तो हर अखबार के पहले तीन पृष्ठों और आखिरी पृष्ठ मे विज्ञापनों का न्यूनतम व अधिकतम स्वामित्व है और उसके बाद के कई में आधा पृष्ठ या उससे अधिक जगह पर यह कुंडली मार कर बैठा है। आज विज्ञापनों के प्रभुत्व के कारण समाचारों में बैचेनी देखकर लगता है कि जैसे उसका मल्टीपल आर्गन फेलियर जैसी स्थिति बन रही है। आठ पन्ने का वर्गीकृत अलग होता है! वह तो जिसकी अटकी है कहीं इन्हें भी झेलेगा ही, तो भविष्य का अखबार 'विज्ञापन बार' होगा! इसमे केवल और केवल विज्ञापन होंगे।

कविता संसार

ऐसा हो अपना स्कूल

चन्द्रकांत खुंटे 'क्रांति'

चमक पड़े डिजिटल पट्ट, लुप्त हो जाए चाक की धूल।
बैठने की उत्तम व्यवस्था, छात्र जाए क्लांति को भूल।
ज्ञान बढ़ाती ग्रंथशाला हो, मिलता जहाँ बोध का मूल।
कक्षा डिजिटल बनवाओ, ज्ञान सरिता बहेंगे अनुकूल।
आधुनिक हो भव्य भवन, महक उठे प्रगति के फूल।
प्रयोगशाला में विद्यार्थी,संधानित करे सत्य का मूल।
रटने की प्रथा अब छोड़ों, कौशल बहे सदा अनुकूल।
वैश्विक संकट से लड़ने को, तत्पर खड़े वीर मकूल।
देश हमारा बदलेगा तब, जब बदलेगा अपना स्कूल।
ग्राम-ग्राम में खुले ऐसी, शिक्षा की यह नई अमूल।
पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, टूटेगा हर पाखंड का मूल।
विश्व गुरु फिर हम बनेंगे, बनेगा जब मॉडर्न स्कूल।
सस्ता सुंदर ज्ञान मिले, न हो कोई भी बाल मलूक।
हर हाथों में हुनर सजे, कोई न बैठे यहाँ अचूक।
नव प्रभात गर लाना है, तोड़ों रूढ़िवादी सब शूल।
ऐसी ही हो अपनी शिक्षा, ऐसा ही हो अपना स्कूल।।

आज के युवा, कल के बुजुर्ग: संवेदनाओं को समझने का समय

-डॉ विजय गर्ग

समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। जीवन का हर चरण अपने साथ नई चुनौतियाँ, अनुभव और जिम्मेदारियाँ लेकर आता है। बचपन से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था तक का यह सफर प्रकृति का अटल नियम है। आज जो युवा अपनी ऊर्जा, महत्वाकांक्षाओं और सपनों के साथ जीवन की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, वही कल वृद्धावस्था की दहलीज पर खड़ा होगा। इसलिए बुजुर्गों की संवेदनाओं को समझना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने भविष्य को समझने और संवारने की आवश्यकता भी है।

भारत को युवा देश कहा जाता है। देश की बड़ी आबादी युवा है, जो विकास और प्रगति की धुरी मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही भारत में बुजुर्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण अधिक लोग लंबा जीवन जी रहे हैं। ऐसे में समाज के सामने यह चुनौती है कि वह पीढ़ियों के बीच संवाद, सम्मान और संवेदनशीलता को कैसे बनाए रखे।

बुजुर्गों की भावनाएँ भी महत्वपूर्ण हैं: अक्सर यह माना जाता है कि बुजुर्गों की आवश्यकताएँ केवल भोजन, दवा और आर्थिक सुरक्षा तक सीमित हैं। जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम, सम्मान, अपनापन और संवाद की होती है। वे चाहते हैं कि परिवार के लोग उनकी बात सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें यह महसूस कराएँ कि वे आज भी परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जब उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता या उन्हें केवल उम्र के कारण अप्रासंगिक समझ लिया जाता है, तो उनके मन को गहरी चोट पहुँचती है। शारीरिक कमजोरी से अधिक मानसिक उपेक्षा उन्हें पीड़ा देती है। इसलिए उनकी भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है।

बदलते समय और बढ़ती दूरी: आज का युवा डिजिटल युग में जी रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जीवन की गति और शैली दोनों बदल दी हैं। दूसरी ओर, बुजुर्गों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ऐसे दौर में बिताया है जहाँ प्रत्यक्ष संवाद और सामाजिक संबंधों का महत्व अधिक था। इस अंतर के कारण कई बार दोनों पीढ़ियों के बीच दूरी पैदा हो जाती है। युवा बुजुर्गों की सलाह को पुरानी सोच समझ लेते हैं, जबकि बुजुर्ग नई पीढ़ी की जीवनशैली को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह पीढ़ीगत अंतर यदि संवाद की कमी से जुड़ जाए तो गलतफहमियाँ और बढ़ जाती हैं। समाधान एक-दूसरे को बदलने में नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझने में है।

तमिलनाडु में विजय क्या सफल होंगे?

-विनीत नारायण

मुख्यमंत्री विजय ने अपने व्यवहार से एक शुभ संकेत दिया है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही वे विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के घर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने गए थे। इसे तमिलनाडु की राजनीति में एक अनूठी पहल माना गया है। शपथ ग्रहण करते ही तीन अहम आदेशों पर हस्ताक्षर किए। जिनमें दो प्रमुख थे। एक, नशीली दवाओं की रोकथाम के कड़े कदम उठाना और दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन को मुस्तैद करना।ज विजय ने सख़्त आदेश दिए हैं कि नागरिकों की ऐसी छोटी-छोटी समस्याओं का हल 24 घंटों के भीतर हो जाना चाहिए।

तमिलनाडु के नए युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजयने शपथ ग्रहण करते ही तीन अहम आदेशों पर हस्ताक्षर किए। जिनमें दो प्रमुख थे। एक, नशीली दवाओं की रोकथाम के कड़े कदम उठाना और दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन को मुस्तैद करना। पर जिन कारणों से विजय की ओर सबका ध्यान गया है, वो है उनकी सादगी, सहृदयता और धर्म निरपेक्षता। विजय के पिता ईसाई हैं और माँ सनातनी हिंदू। इसलिए विजय दोनों धर्मों में आस्था रखते हैं और दोनों के धार्मिक कृत्यों में श्रद्धा से भाग लेते हैं। उनका यही रवैया अन्य धर्मों के प्रति भी है। आज जब देश में धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ता जा रहा है तब श्री विजय की इस पहल ने तमिलनाडु के लोगों को बहुत राहत प्रदान की है।

प्रायः राजनीति में जो लोग आते रहे, वे होते हैं जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि मज़बूत नहीं होती थी। इसीलिए वे राजनीति को कमाई का ज़रिया बना कर अकूत धन संपत्ति जमा करने में जुट जाते थे। कमोबेश यह इतिहास हर राजनेता का रहा है।

विजय तमिलनाडु के सुपर स्टार हैं और 600 करोड़ से अधिक की अर्जित संपत्ति के मालिक हैं। वे अपने राज्य में एक कलाकार के रूप में लोकप्रियता के शिखर पर रहे हैं। इसलिए माना जा सकता है कि राजनीति में उनका प्रवेश धन या यश कमाने के लिए नहीं हुआ।

वे कुछ नया कर गुज़रना चाहते हैं। उन्होंने तमिलनाडु में नेताओं के कटआउट और पोस्टर लगाने को प्रतिबंधित कर दिया है। जबकि हर दल के नेता अपने फ़ोटो के विज्ञापनों और कटआउटों पर देश की ग़रीब जनता का अरबों रुपया बर्बाद करते हैं। जिन पाठकों ने तमिलनाडु का दौरा किया है उन्होंने यह आश्चर्यजनक संस्कृति वहाँ देखा होगी कि राजनेताओं के 100-100 फुट ऊँचे कटआउट जगह-जगह लगे होते हैं।

विजय राजनीति से वीआईपी संस्कृति समाप्त करना चाहते हैं और इस दिशा में भी उन्होंने कई पहल की हैं जिसका अच्छा संदेश गया है। इतने सम्पन्न और सुप्रसिद्ध व्यक्ति होते हुए विजय एक कर्मचारी की तरह समय पर दफ़्तर आते हैं और अपना लंच बॉक्स साथ लाते हैं। दोपहर को वे अपनी मेज़ पर डिब्बा खोल कर अकेले लंच करते हैं, कोई तामझाम नहीं। ऐसी छोटी-छोटी बातों का जनता पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। दरअसल आम जनता की सरकार से अपेक्षाएँ बहुत सीमित होती हैं।

मसलन बिजली-पानी की आपूर्ति गड्ढा-मुक्त सड़कें, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों में आम जनता के प्रति ज़िम्मेदारी और सम्मान का भाव आदि। विजय ने सख़्त आदेश दिए हैं कि नागरिकों की ऐसी छोटी-छोटी समस्याओं का हल 24 घंटों के भीतर हो जाना चाहिए। देश की जो कार्य संस्कृति रही है उसमें ऐसा हो पाना आसान नहीं है। पर नेतृत्व में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं है।

आज के राजनैतिक माहौल में जब अपने विपक्षी दलों के नेताओं को अपमानित करना, उनके प्रति अपशब्द बोलना और उनके परिवार पर छींटाकशी करना आम बात हो गई है, वहाँ विजय ने अपने व्यवहार से एक शुभ संकेत दिया है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही वे विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के घर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने गए थे। इसे तमिलनाडु की राजनीति में एक अनूठी पहल माना गया है। छोटे दलों के कुछ नेताओं का तो ये कहना था, कि उनके जीवन में पहली बार कोई मुख्यमंत्री उनके आवास पर इस तरह शिष्टाचार प्रदर्शित करने आया। जाहिर है कि विपक्ष के नेता भी विजय की इस विनम्रता से अभिभूत हैं।

आज के दौर में जब धर्मांध लोग एक दूसरे के धर्मस्थलों को अपमानित या ध्वस्त करना अपनी उपलब्धि मानते हैं, उस दौर में विजय ने एक नई पहल की है। उन्होंने सभी धर्मों के उपेक्षित पड़े धर्मस्थलों का सरकारी प्रयास से जीर्णोद्धार कराए जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस दिशा में वे कितने सफल हो पायेंगे, ये तो आनेवाला समय ही बताएगा। पर भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत है।

कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने बहुत आशा जगाई थी। लंबे-चौड़े दावे किए थे। अनेक क्रांतिकारी कदमों का ऐलान किया था। पर क्रमशः वह सब काफ़ूर हो गया। आम आदमी पार्टी ने जनहित में कुछ अच्छे कार्य भी किए पर वो उन दावों की तुलना में बहुत कम थे, जो शुरू में किए गए थे। अब इसे देश का दुर्भाग्य कहें या राजनीति का यथार्थ कि सत्ता पाकर हर व्यक्ति बदल जाता है या हालात उसे बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं।

मेरा मानना है कि जिनमें आध्यात्मिक चेतना और नैतिक बल होता है वही राजनीति की दलदल कमल की तरह खिल पाते हैं। पर ऐसा यदा-कदा ही होता है। मुझे याद है किस तरह वाजपेयी जी की सरकार में जगमोहन जी के मंत्रालय तीन बार बदल दिए गए। वे कर्मठ व्यक्ति थे और पारदर्शिता के साथ सुधार करना चाहते थे। पर जिस मंत्रालय में भी वे सुधार के प्रयास करते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता था। यही रवैया अन्य दलों के सत्ता में आने बाद देखा जाता है कि योग्य और भले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है।

शिक्षा विभाग के नए फरमान पर उठे गंभीर संवैधानिक सवाल, मनमानी का नया सर्कुलर

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश विवादों के घेरे में, स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य करने पर बवाल। क्या शिक्षा विभाग भूल गया अनुच्छेद 25 और 28 सरकारी खर्च पर चलने वाले स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों की अनिवार्यता पर कानूनी विशेषज्ञों ने उठाए सवाल।

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
।। मंत्रालय ।।
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

क्रमांक GENCOR-35010/1981/2026-SCHOOL EDUCATION SECTION दिनांक 12-06-2026

प्रति,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषय:- शालाओं में विभिन्न गतिविधियां संचालित किये जाने के संबंध में।

--00--

नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित समस्त शालाओं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बौद्धिक विकास एवं अपनी संस्कृति/परंपराओं से अवगत कराये जाने उद्देश्य से शालाओं में निम्नानुसार गतिविधियां संचालित किया जाना है:-

1.	सुबह प्रार्थना में स्कूल लगने पर	1. राष्ट्रगान 2. राष्ट्रगीत 3. दीपमंत्र 4. सरस्वती वंदना 5. गुरु मंत्र 6. महापुरुषों का जीवनी का वाचन
2.	मध्यान्ह भोजन में	भोजन मंत्र
3.	संध्या के समय छुट्टी होने पर	1. राज्यगीत 2. गायत्री मंत्र 3. शांति मंत्र

2/ उक्त गतिविधियां प्रतिदिन ऊपर वर्णित क्रमानुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by RAMESHWAR PRASAD VERMA
Date: 12-06-2026 17:46:23
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक GENCOR-35010/1981/2026-SCHOOL EDUCATION SECTION दिनांक 12-06-2026
प्रतिलिपि:-
1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. आयुक्त, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, पेंशनबाड़ा, रायपुर छ.ग.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

बच्चों पर मानसिक बोझ

सुबह से शाम तक प्रार्थना, वंदना और मंत्रों की लंबी सूची, क्या यह शिक्षा का सत्र है या किसी विशिष्ट विचार को थोपने का एजेंडा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी किया गया एक नया आदेश क्रमांक जेनकोर : 35010/1981/2026- स्कूली शिक्षा विभाग विवादों के केंद्र में आ गया है।

विभाग के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना, मध्याह्न भोजन और शाम की छुट्टी के समय मंत्रों, वंदनाओं और विशिष्ट धार्मिक प्रकृति वाले गीतों का गायन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं।

इस आदेश के सामने आते ही शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसके तीखे खंडन के साथ सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अनुच्छेद 28(1) का सीधा उल्लंघन

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि पूर्णत राज्य-निधि सरकारी पैसे से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह आदेश बच्चों और शिक्षकों की अंतःकरण की स्वतंत्रता को बंधक बनाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राज्य सरकारी आदेश के बल पर किसी विशिष्ट धार्मिक पद्धति जैसे दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र को सभी नागरिकों / छात्रों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं कर सकता।

भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है। सरकारी स्कूलों में हर वर्ग, जाति और धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में क्या स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को बौद्धिक विकास के नाम पर एक खास धार्मिक विचारधारा की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षा के मूल एजेंडे से भटकता विभाग

आदेश में सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ-साथ दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महापुरुषों की जीवनी के वाचन को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, दोपहर के खाने से पहले, भोजन मंत्र और शाम को छुट्टी के समय राज्यगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्रज की अनिवार्यता तय की गई है।

आलोचकों का कहना है कि, समय की बर्बादी

यदि बच्चे स्कूल लगने से लेकर छुट्टी होने तक सिर्फ मंत्रों और वंदनाओं के क्रम को ही पूरा करते रहेंगे, तो विज्ञान, गणित, भाषा और तार्किक विषयों के लिए समय कहां बचेगा। 21 वीं सदी में जहां शिक्षा विभाग को डिजिटल साक्षरता, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और गिरते हुए शिक्षा स्तर को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, वहां विभाग का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे दिन में कितनी बार मंत्र पढ़ रहे हैं।

यह आदेश इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर स्कूलों को एक खास सांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है। बुद्धिजीवियों और जागरूक नागरिक मंचों ने इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार ने इस जबरन थोपे गए सांस्कृतिक एजेंडे को वापस नहीं लिया, तो इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाना तय है। स्कूलों का काम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है, न कि उन्हें किसी शासकीय आदेश के भय से धार्मिक कर्मकांडों में उलझाना। शिक्षा विभाग को यह याद रखना होगा कि वह संविधान से संचालित होता है, किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक एजेंडे से नहीं।

दबंगई, घर से सटाकर जबरन बनाई जा रही सड़क

विरोध करने पर थाने में फंसाने की धमकी

सूरजपुर/प्रतापपुर। जिले के आकांक्षी ब्लॉक मुख्यालय प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खड़गाँवकला में विकास के नाम पर ग्रामीण इलाकों में दबंगई और आपसी रंजिश के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम खड़गाँवकला से सामने आया है, जहाँ एक पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने नियमों को ताक पर रखकर जबरन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन सौंपकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।

क्या है पूरा मामला : ग्राम खड़गाँवकला निवासी पीड़ित हरिश कुमार राजवाड़े ने एसडीएम कार्यालय में दिए अपने शिकायती पत्र में बताया कि उनके घर के सामने सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। नियमानुसार सड़क का रास्ता दोनों पक्षों की सहमति से बीच से निकाला जाना था, जिसके लिए पीड़ित पूरी तरह तैयार भी था लेकिन दूसरा पक्ष अपनी तरफ से रास्ता देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। विरोध करने पर केस दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं पीड़ित का आरोप है कि जब उसने इस गलत निर्माण का विरोध किया, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार को चुप कराने के लिए स्थानीय थाने में झूठा केस दर्ज कराकर फंसाने की खुली धमकी दी जा रही है।

आने वाले बारिश को ध्यान में रखते हुए मंडरा रहा है आशियाना उजड़ने का खतरा : इस विवाद के कारण पीड़ित परिवार बेहद खौफ और मानसिक तनाव में जीने को मजबूर है। पीड़ित ने प्रशासन को आगाह किया है कि यदि घर से बिल्कुल सटाकर सड़क का निर्माण कर दिया गया, तो आगामी बरसात में पूरी सड़क और आसपास का पानी सीधे उनके घर में भर जाएगा। पानी के इस भराव के कारण उनका कच्चा मकान ढह सकता है, जिससे जान-माल का बड़ा नुकसान होने की पूरी आशंका है।

नक्शे' के विपरीत हो रहा काम : आवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जिस जगह से रास्ता निकाला जा रहा है उसकी कोई वैध नकल या नक्शा नहीं निकाला गया है, यानी बिना प्रशासनिक मापदंडों और पैमाइश के केवल दबंगई के दम पर इस निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

प्रशासनिक रुख का इंतजार: ग्रामीण ने एसडीएम से इस संवेदनशील मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, मौके की जांच करवाने और समस्या का उचित समाधान करने की मांग की है।

बेटे ने चाचा के साथ मिलकर की पिता की हत्या, दोनों गिरफ्तार

बलरामपुर। चौकी डवरा क्षेत्र के ग्राम लिलौटी में जमीन बंटवारे को लेकर उपजे विवाद में बेटे ने अपने चाचा के साथ मिलकर पिता की टांगी से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकी डवरा थाना पस्ता में जीवन लाल पिता स्व. दिलबर उम्र 40 वर्ष, निवासी लिलौटी स्कूलपारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता दिलबर, चाचा पूरन और नन्दकेश्वर तीन भाई हैं। संजय रवि पूरन का नाती है। चाचा नन्दकेश्वर और संजय रवि जमीन के बंटवारे से असंतुष्ट थे। दोनों को लगता था कि मृतक दिलबर ने अपने हिस्से में ज्यादा जमीन रख ली है। दिनांक 13 जून 2026 की शाम करीब 7 बजे दिलबर खाना खाकर अपने प्रधानमंत्री आवास में अकेला सो रहा था। आवास के दोनों तरफ के दरवाजे खुले थे। इसी दौरान जमीन बंटवारे से नाराज संजय रवि और नन्दकेश्वर ने षड्यंत्र रचकर दिलबर के कान, गर्दन और बाएं हाथ की उंगली पर टांगी से वार कर हत्या कर दी।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पस्ता में अपराध क्रमांक 30/2026 धारा 103(1), 332, 61 भा.न्या.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी संजय कुमार रवि 32 वर्ष और नन्दकेश्वर रवि 55 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम लिलौटी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 15 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

कर्मचारियों की कमी, पेयजल संकट और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही तहसील, ग्रामीणों में बढ़ रहा असंतोष

जनधारा समाचार

सूरजपुर/रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत स्थित देवनगर तहसील कार्यालय इन दिनों कर्मचारियों की भारी कमी, पेयजल संकट और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र के 25 से 30 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्यों के लिए इस कार्यालय पर निर्भर हैं, लेकिन सीमित संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तहसील कार्यालय में लंबे समय से कई आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव बना हुआ है, जिससे शासकीय कार्यों की गति प्रभावित हो रही है।

देवनगर तहसील में वर्तमान में अधिकांश कार्यालयीन कार्यों का भार केवल दो लिपिकों के कंधों पर है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा-खसरा, ऋण पुस्तिका, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील पहुंचते हैं। सीमित स्टाफ के कारण कई बार लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है तथा छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि तहसील कार्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से समस्या और गंभीर हो जाती है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। कार्यालय में एक घड़े की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन उसमें नियमित रूप से पानी उपलब्ध नहीं रहता। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि तहसील पहुंचे ग्रामीणों और पक्षकारों को बाजार जाकर 20 रुपये की बोतलबंद पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और अधिक विकराल रूप ले लेती है।

स्थानीय लोगों के अनुसार तहसील कार्यालय में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए इनवर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। बिजली गुल होने पर कई बार कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो जाते हैं। वहीं दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए फोटोकॉपी मशीन की सुविधा नहीं होने से लोगों को बाजार का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और अतिरिक्त धन दोनों खर्च होते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि तहसील कार्यालय में भृत्य अथवा पियून का पद रिक्त होने अथवा उपलब्ध कर्मचारी नहीं होने के कारण कई व्यवस्थाएं प्रभावित हैं। फाइलों का संधारण, दस्तावेजों की खोज, अभिलेखों को व्यवस्थित रखने जैसे कार्यों में भी कठिनाइयां सामने आती हैं। इसका सीधा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र के कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्यालय में भृत्य और सफाईकर्मी की कमी के चलते ग्राम कोटवारों से नियमित रूप से सफाई, पानी भरने, कार्यालय की साफ-सफाई, नाश्ता-चाय की व्यवस्था और अन्य दैनिक कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोटवारों की नियुक्ति ग्राम स्तरीय राजस्व एवं सूचना संबंधी कार्यों के लिए की जाती है, ऐसे में उनसे लगातार अन्य कार्य लिए जाने से उनके मूल दायित्व प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों ने इस व्यवस्था की जांच की मांग भी उठाई है।

वहीं कुछ स्थानीय नागरिकों ने नायब तहसीलदार के कार्यशैली और आम लोगों के प्रति व्यवहार को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि जनता से संवाद और समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया को और अधिक सहज एवं संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है।

देवनगर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तहसील कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारियों की पदस्थापना, भृत्य एवं सफाईकर्मी की व्यवस्था, पेयजल सुविधा, इनवर्टर, फोटोकॉपी मशीन सहित अन्य मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आम जनता की परेशानियां और बढ़ सकती हैं।

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)
Email ID-commissionerdhamatari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

-:: मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना ::-

क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/निविदा/2026/682 धमतरी, दिनांक 11/06/2026

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा अधोसंरचना मद् अंतर्गत सोरिद वार्ड क्र. 35 स्थित सोरिद नाला में सार्वा रजक घर से काम्पटेक कॉलेज तक आर.सी.सी. टो-वॉल निर्माण कार्य (अनुमानित लागत राशि 8.08 लाख रू.) के लिए एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गतम सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से छ.ग. पी.डब्ल्यू.डी. भवन एस.ओ.आर. 01.01.2015 अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र ''ए'' में चार-लिफाफा पद्धति से मैनुअल निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02.07.2026 तक आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्य का निर्धारित अमानत राशि, निविदा की सामान्य शर्तें तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा से प्राप्त की जा सकती है एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर छ.ग. के वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी

जीवनदीप समिति की कार्यकारिणी बैठक में कलेक्टर ने दी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

जनधारा समाचार

कोरिया। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में जीवनदीप समिति की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय में आवश्यक व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिला चिकित्सालय की विद्युत व्यवस्था, जल निकासी, बेड की उपलब्धता, स्ट्रीट लाइट तथा पार्किंग व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अस्पताल परिसर में बारिश के मौसम के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों की समुचित देखभाल एवं उन्हें प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

नशीले इंजेक्शन के साथ तस्कर गिरफ्तार

बलरामपुर। पस्ता पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50-50 नग नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की यामाहा बाइक और एक एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया मिली जानकारी के अनुसार 13 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शंकरगढ़ की ओर से पस्ता की तरफ बिना नंबर प्लेट की बैंगनी-सफेद यामाहा बाइक से एक व्यक्ति नशीले इंजेक्शन लेकर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर थाना प्रभारी ने टीम के साथ ग्राम बासेन कोदोडीपा कोलावाड़ी में घेराबंदी की।

कुछ देर बाद संदिग्ध बाइक सवार आता दिखा। रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अतिकुर रहमान पिता जसिमुद्दीन, उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम बासेन, थाना पस्ता, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज बताया। संदेही पहले टाल-मटोल करने लगा और असामान्य व्यवहार किया। बाइक की डिग्गी की तलाशी लेने पर 04 सीलबंद पैकेट मिले। इनमें से 02 पैकेट में फेनिरामाइन मैलेट इंजेक्शन आईपी एविल के कुल 50 नग शीशी और अन्य 02 पैकेट में ब्यूप्रेनोर्फिन इंजेक्शन आईपी रेक्सोजेसिक के कुल 50 नग इंजेक्शन मिले। जब्त इंजेक्शन की कीमत करीब 1107.5 रुपये आंकी गई है।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र./..../बी-121/2025-26
ग्राम भरूवागुड़ा प.ह.नं. 06

एतद् द्वारा ग्राम भरूवागुड़ा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ओंकार राय आ. सीताराम राय जाति सतनामी निवास भरूवागुड़ा तहसील व जिला मुंगेली द्वारा ग्राम भरूवागुड़ा हल्का नं. 06 तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने नाती सुशांत राय आ. मनोज राय की मृत्यु/जन्म दिनांक 10/11/2017 को होने एवं सचिव, ग्राम पंचायत भरूवागुड़ा के पंजी में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 25/06/2026 समय 11:00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि को पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
सील मुंगेली (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र. /अ-6 अ/2025-26
ग्राम करही , प.ह.नं. 17

एतद् द्वारा ग्राम करही के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र कुमार साहू पिता/पति आजूराम जाति तेली निवासी करही तहसील एवं जिला मुंगेली के द्वारा ग्राम करही स्थित भूमि खसरा नं. 31/1, 283/42 , 287/2 कुल रकबा 0.2100 हे./ए. भूमि का आवेदक का नाम त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है जिसे सुधार कर सही नाम दर्ज किये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यकित को किसी भी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति हो तो स्वयं या अभिभाषक या अधिवक्ता के या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 19/06/2026 को समय 11.00 बजे दिन के तहसील कार्यालय मुंगेली में स्वयं उपस्थित होकर लिखित दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
सील मुंगेली (छ.ग.)

शपथ पत्र
प्रारूप- (एक)

मैं शंकर कुमार नायक पिता श्री उदय, उम्र-37 वर्ष, जो कि-08 ग्राम आरगट्टा, पोस्ट आरगट्टा, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा, (छ.ग.) पिन-494122 ने अपने पुत्र के पूर्व नाम श्रेयश मड़कम (SHREYASH MAD-KAM) एवं पिता का नाम शंकर कुमार मड़कम (SHANKAR KUMAR MADKAM) को बदलकर श्रेयश नायक (SHREYASH NAYAK) एवं पिता का नाम शंकर कुमार नायक (SHANKAR KUMAR NAYAK) रख लिया है।

श्रेयश नायक (ना.बा.)
की ओर से अभिभावक/पिता
नाम-शंकर कुमार नायक

कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी/तहसीलदार बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)
ग्राम- सोंठी, दिनांक 12/06/2026

ईश्तहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मंगल धनुहार पिता स्व. कोंदा धनुहार जाति धनुहार निवासी सोंठी तहसील बम्हनीडीह जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) ने इस न्यायालय में अपने पिता कांदा धनुहार के मृत्यु दिनांक 25/04/2023 स्थान पर सोंठी कारण से होने पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पटवारी प्रतिवेदन मय पंचनामा शपथ पत्र सहित पेश किया है। अतः जिस किसी व्यक्ति को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 29/06/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रसतुत कर सकते हैं। नियत तिथी के पश्चात दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14/06/2026 को न्यायालय के सील मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।

जारी दिनांक 12/06/2026
पेशी दिनांक 29/06/2026

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
सील बम्हनीडीह

न्यायालय कार्यालय कार्यपालिक चांपा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)
क्र./क्यू/तह./2026
चांपा दिनांक 09/06/2026

ईश्तहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका बीरबल लहरे पिता स्व. श्री लक्ष्मण लहरे, जाति सतनामी निवासी ग्राम कुरदा, तहसील चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ने इस न्यायालय में अपने पुत्र/पुत्री/पिता/पति अपने दादी छेदीन बाई पति झाडूराम सतनामी का मृत्यु दिनांक 02.10.2022 स्थान पर ग्राम कुरदा, तहसील चाम्पा में मृत्यु होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु 1. आवेदन पत्र 2. शपथ पत्र 3. पटवारी प्रतिवेदन 4. ग्राम पंचायत कुरदा से जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित पेश किया है। अतः जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 25/06/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं नियत तिथि के पश्चात दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/06/2026 को न्यायालय के सील एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।

दिनांक 09/06/2026
पेशी दिनांक 25/06/2026

कार्यपालक दण्डाधिकारी
सील चांपा

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र./..../बी-121/2025-26
ग्राम लैकडुम प.ह.नं. 06

एतद् द्वारा ग्राम लैकडुम के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोंगरा चतुर्वेदी पति कुमका जाति सतनामी निवास कोलिहाडीह तहसील व जिला मुंगेली द्वारा ग्राम लैकडुम हल्का नं. 06 तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने देवर केशराम आ. घुमदास की मृत्यु/जन्म दिनांक 02/11/2022 को होने एवं सचिव, ग्राम पंचायत लैकडुम के पंजी में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 18/06/2026 समय 11:00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि को पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
सील मुंगेली (छ.ग.)

समक्षः- श्रीमान नोटरी महोदय मुंगेली तहसील व जिला मुंगेली (छ.ग.)

//शपथ-पत्र//

मैं पुष्पराज कुर्रे उम्र 42 वर्ष पिता गौसिंह कुर्रे जाति सतनामी निवासी रेहुटा तहसील मुंगेली जिला मुंगेली छ.ग. का स्थाई निवासी हूं, जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन करता हूं :- आधार क्रमांक 3374 2129 7218

1. यह कि मैं उक्त पते का स्थाई निवासी हूं।
2. यह कि मेरे पुत्र बेलेन्द्र कुमार कुर्रे के आधार कार्ड जिसका क्रमांक - 4216 1459 5271 है। जिसमें पुत्र का नाम बलेन्द्र कुमार कुर्रे दर्ज हो गया है, जो भूलवश व त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज हो गया है।
3. यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वेलेन्द्र कुर्रे उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है।
4. यह कि मैं अपने पुत्र उक्त आधार कार्ड से पुत्र का नाम बेलेन्द्र कुमार कुर्रे को सूधार करवाकर वास्तविक नाम वेलेन्द्र कुर्रे दर्ज करवाना चाहता हूं। जिसके संबंध में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
5. यह कि मैंने किसी भी बातों एवं तथ्यों को नहीं छिपाया है और ना ही झूठे तरीके पेश किया हूं।

सत्यापन

मैं पुष्पराज कुर्रे यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त कण्डिका 01 से 05 तक की समस्त बातें मेरी जानकारी एवं ज्ञान से सत्यापित है जिसे लिखाकर पढ़कर व समझकर आज दिनांक 09.06.2026 नोटरी महोदय के समक्ष अपना हस्ताक्षर किया हूं।

शपथकर्ता
सील पुष्पराज कुर्रे

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. ....../धारा 170 ख/2025-26
दिनांक 05.06.2026 ग्राम महुदा

नोटिस

बुधवारा बाई उम्र 53 पिता तीजराम जाति गोड़ निवासी ग्राम कुरदा हा. मु. बांधापाली तहसील डभरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)........... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. कोंदा पिता बोधन
2. सहारू पिता पहारू दोनो जाति सतनामी निवासी कुरदा तहसील चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

प्रति,
1. कोंदा पिता बोधन
2. सहारू पिता पहारू दोनो जाति सतनामी निवासी कुरदा तहसील चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)...... उत्तरवादीगण

अपीलार्थी बुधवारा बाई उम्र 53 पिता तीजराम जाति गोड़ निवासी ग्राम कुरदा हा. मु. बांधापाली तहसील डभरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) द्वारा आवेदन पत्र वास्ते धारा 170 (ख) छ.ग.भू.रा. संहिता के अंतर्गत भूमि वापस दिलाये जाने बाबत् आवेदन पत्र अन्य दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में उत्तरवादी की उपस्थिति/सुनवाई हेतु दिनांक 18.06.2026 नियत किया गया है। नियत दिनांक को आप न्यायालय में स्वतः या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रकरण की सुनवाई में भाग ले सकते है। नियत दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आपके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से आज दिनांक 05.06.2026 को जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सील चांपा

न्यायालय तहसीलदार मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

// उद्घोषणा //

रा.प्र.क्र. 202606250200005/
अ-27/2025-26
ग्राम-रामाकापा प.ह.नं.-41

एतद् द्वारा ग्राम रामाकापा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहनदास पिता/पति पुनदास जाति सतनामी निवासी रामाकापा तह. व जिला मुंगेली के द्वारा ग्राम रामाकापा प.ह.नं. 41 स्थित भूमि ख.नं. 138/1, 210 रकबा 0.453, 0.393 हे. का खाता विभाजन किये जाने हेतु संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 01/07/2026 को समय 11.00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
सील मुंगेली

न्यायालय तहसीलदार मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

// उद्घोषणा //

रा.प्र.क्र. 202605250200096/
अ-27/2025-26
ग्राम-रामाकापा प.ह.नं.-41

एतद् द्वारा ग्राम रामाकापा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहनदास पिता/पति पुनदास जाति सतनामी निवासी रामाकापा तह. व जिला मुंगेली के द्वारा ग्राम रामाकापा प.ह.नं. 41 स्थित भूमि ख.नं. 32/4 कुल रकबा 0.202 हे. का खाता विभाजन किये जाने हेतु संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 22/06/2026 को समय 11.00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
सील मुंगेली

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र./..../बी-121/2025-26
ग्राम पडरभट्ठा प.ह.नं. 48

एतद् द्वारा ग्राम पडरभट्ठा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक यशवंत सिंह आ. खेलसिंह जाति गोंड निवासी पडरभट्ठा तहसील व जिला मुंगेली द्वारा ग्राम पडरभट्ठा हल्का नं. 48 तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने बड़े पिता रामखिलावन आ. भागवत सिंह की मृत्यु दिनांक 21/01/2020 को होने एवं सचिव, ग्राम पंचायत पडरभट्ठा के पंजी में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 16/06/2026 समय 11:00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि को पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
सील मुंगेली (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र./..../बी-121/2025-26
ग्राम पडरभट्ठा प.ह.नं. 48

एतद् द्वारा ग्राम पडरभट्ठा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक यशवंत सिंह आ. खेलसिंह जाति गोंड निवासी पडरभट्ठा तहसील व जिला मुंगेली द्वारा ग्राम पडरभट्ठा हल्का नं. 48 तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने पिता खेलसिंह आ. भागवत सिंह की मृत्यु दिनांक 18/01/2019 को होने एवं सचिव, ग्राम पंचायत पडरभट्ठा के पंजी में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 16/06/2026 समय 11:00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि को पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
सील मुंगेली (छ.ग.)

पुलिया के पिलर में सरिए की जगह ठूंस दीं सीमेंट की बोरियां

● ग्राम किलेपार में बड़ा भ्रष्टाचार :धंसने लगा पुल

चारामा। जिले से विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिला खनिज न्यास निधि से लाखों रुपये की लागत से बनी एक पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस पुलिया के पिलर (खंभों) की मजबूती के लिए उसमें लोहे के सरिए डालने के बजाय, सीमेंट की खाली बोरियां भरकर ढलाई कर दी गई। निर्माण के कुछ ही महीनों के भीतर पुलिया का पिलर अब धंसने लगा है, जिससे मानसून के दौरान बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है।

इस मामले को लेकर जनपद पंचायत चारामा की क्षेत्र क्रमांक 04 से जनपद सदस्य और सभापति श्रीमती रेणुका सिन्हा ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

डीएमएफ फंड के 16.18 लाख रुपये का गबन!

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड चारामा के अंतर्गत ग्राम पंचायत किलेपार में नदियापारा से टांहकापार मार्ग पर 300 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया का निर्माण कराया गया था। इस कार्य के लिए वर्ष 2024-25 में जिला खनिज न्यास निधि से 16.18 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई थी। इस निर्माण कार्य की मुख्य एजेंसी खुद ग्राम पंचायत किलेपार थी। दस्तावेजों के मुताबिक, इस पुलिया का निर्माण कार्य 24 अप्रैल 2025 को प्रारंभ हुआ था और यह फरवरी 2026 में पूरी तरह तैयार हो चुका था। लेकिन महज 4 महीनों के भीतर ही इसकी गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई है।

जनपद सदस्य के औचक निरीक्षण में खुला राज

ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद, दिनांक 10 जून 2026 को जनपद सदस्य श्रीमती रेणुका सिन्हा ने अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीरें और तथ्य सामने आए, वे बेहद डराने वाले हैं।

पिलर में सरिए की जगह बोरियां: पुलिया को मजबूती देने वाले मुख्य पिलर के भीतर लोहे के सरियों की जगह सीमेंट की खाली बोरियां ठूंसकर कंक्रीट भर दिया गया है। पिलर टूटने पर यह धोखाधड़ी साफ नजर आ रही है।

अभी से धंसने लगा पुलः यद्यपि निर्माण कार्य को पूरा हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन घटिया निर्माण के कारण पुलिया का पिलर अभी से नीचे की ओर धंसना शुरू हो गया है।

जनपद सदस्य श्रीमती रेणुका सिन्हा ने कहा कि तकनीकी अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की मिलीभगत से शासकीय राशि का खुलेआम गबन किया गया है। यदि मानसून की बारिश से पहले इस पर तत्काल तकनीकी जांच और सुधार नहीं किया गया, तो यह पुल कभी भी ढह सकता है, जिससे जान-माल का बड़ा नुकसान होने की पूरी आशंका है।

कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से कड़ी कार्रवाई की मांग

जनपद सदस्य ने आज, 15 जून को कलेक्टर कांकेर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर और सीईओ जनपद पंचायत चारामा को आधिकारिक पत्र किलेपार पुल निर्माण का शिकायत पत्र और सबूत सौंपकर निम्नलिखित मांगें की हैं। पुलिया की तुरंत किसी स्वतंत्र विंग से तकनीकी जांच कराई जाए। दोषी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित तकनीकी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। शासकीय धन की बर्बादी करने वाले दोषियों से ही पुल के पुनर्निर्माण की पूरी राशि वसूली जाए। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और दोषियों पर क्या गाज गिरती है।

पीएम श्री सेजस कुम्हारी में समर कैंप का रंगारंग समापन

कुम्हारी। पीएम श्री सेजस कुम्हारी में आयोजित ग्रीष्मकालीन समर कैंप का समापन उत्साह एवं उल्लास के साथ किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसएमडीसी अध्यक्ष आलोक दुबे, सांसद प्रतिनिधि सुजीत यादव, सदस्य दीपक सिंह बैस तथा विशेष अतिथि कैलाश नागवंशी (प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला धरमपुरा) उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती विजया श्रीवास्तव के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने समर कैंप में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का आकर्षक प्रदर्शन किया। कैंप में बच्चों को ज्वेलरी मेकिंग, सॉन्ग, ड्रामा, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फन विद साइंस, फन विद मैथ्स तथा हेल्थ एंड हाइजीन जैसी उपयोगी एवं रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। विशेष अतिथि कैलाश नागवंशी द्वारा प्रस्तुत रोचक मैजिक शो ने बच्चों का भरपूर मनोरंजन किया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

अतिथियों ने समर कैंप के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता तथा आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखते रहने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया।

पेड़ों में कील ठोककर विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग

● सर्व आदिवासी समाज ने उठाई आवाज, वन मंत्री को भेजा पत्र

कांकेर। मुख्य सड़कों और मार्गों के किनारे लगे वृक्षों में कील ठोककर विज्ञापन पोस्टर लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ (युवा प्रभाग) ने कड़ा विरोध जताया है। समाज ने इसे पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य बताते हुए दोषी कंपनियों एवं व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

युवा प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप तथा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गूकोदल को भी भेजी गई है।ललित नरेटी ने अपने पत्र में कहा है कि विभिन्न कंपनियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सड़क किनारे लगे वृक्षों पर विज्ञापन पोस्टर लगाने के लिए लोहे की कीलों का उपयोग कर रहे हैं। इससे वृक्षों की छाल को नुकसान पहुंच रहा है और उनके प्राकृतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार तनों में कील ठोकने से वृक्षों में संक्रमण और सड़न की संभावना भी बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। वे ऑक्सीजन, छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। ऐसे में विज्ञापन के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाना गंभीर और असंवेदनशील कृत्य है। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि एक ओर सरकार वृक्षारोपण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग व्यावसायिक हितों के लिए पेड़ों को क्षति पहुंचा रहे हैं।सर्व आदिवासी समाज ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषियों पर कार्रवाई करने, अवैध पोस्टरों को तत्काल हटाने तथा प्रभावित वृक्षों का आकलन कर जिम्मेदार लोगों पर आर्थिक दंड लगाने की मांग की है।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसी-2026) का सफल आयोजन

कुम्हारी। द आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, कुम्हारी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , रायपुर के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर स्मार्ट सिटीज, हेल्थकेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईसीसी-2026) का सफलतापूर्वक समापन हुआ। सम्मेलन को एडवांस्ड फ्यूचर टेक लैब्स, यूनाइटेड किंगडम का सह-प्रायोजन प्राप्त था।

सम्मेलन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, सतत विकास, इंडस्ट्री 4.0 तथा अन्य उभरती तकनीकों के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधानों एवं नवाचारों पर विचार-विमर्श हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को एक साझा मंच प्रदान करना था।

आईसीसी-2026 को देश-विदेश के शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों से उत्साहजनक प्रतिसाद प्राप्त हुआ। सम्मेलन में कुल 132 शोध सार प्राप्त हुए, जो बुद्धिमान प्रणालियों, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, सतत विकास, इंडस्ट्री 4.0 एवं उभरती तकनीकों सहित विभिन्न विषयों से संबंधित थे। सभी स्वीकृत शोध सारों को कोपल पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित आईएसबीएन युक्त आईसीसी-2026 अबस्ट्रैक्ट बुक में संकलित किया गया। यह प्रकाशन समकालीन शोध कार्यों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साथ ही, इस अबस्ट्रैक्ट बुक को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय इंडेक्सिंग डेटाबेस में भेजा जाएगा तथा इसे गूगल स्कॉलर में भी इंडेक्स किए जाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे शोध कार्यों की वैश्विक दृश्यता एवं शैक्षणिक प्रभाव में वृद्धि होगी।

सम्मेलन का उद्घाटन सरस्वती पूजन, राज्य गीत, अतिथियों के पुष्प स्वागत एवं सम्मेलन स्मारिका के विमोचन के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. राजीव प्रकाश, निदेशक, आईआईटी भिलाई थे, जबकि प्रो. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, निदेशक, आईआईआईटी वडोदरा विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. डॉ. शिव दयाल पाण्डेय, कुलपति, द आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, रायपुर के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

अपने स्वागत उद्बोधन में कुलपति प्रो. (डॉ.) शिव दयाल पाण्डेय ने अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ बनाने तथा अकादमिक जगत, उद्योग और समाज के मध्य सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. राजीव प्रकाश ने वर्तमान सामाजिक चुनौतियों के समाधान में बुद्धिमान तकनीकों, नवाचार एवं अनुसंधान -आधारित समाधानों की भूमिका को रेखांकित किया। प्रो. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह ने उभरती डिजिटल तकनीकों तथा उनके शिक्षा, प्रशासन एवं उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त किए।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें इंटेलिजेंट सिस्टम्स एवं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटी एवं अर्बन इनोवेशन, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी एवं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं डेटा प्राइवेसी, इंडस्ट्री 4.0 एवं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सहित अनेक विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। देश-विदेश के शोधकर्ताओं ने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए, जिससे ज्ञान-विनिमय एवं शोध सहयोग के नए अवसर विकसित हुए। सम्मेलन में संध्या को विश्वविद्यालय द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक एवं संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया।

द्वितीय दिवस की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के मुख्य व्याख्यानों से हुई। डॉ. अबू सरवर जमानी, प्रिंस सत्तम बिन अब्दुलअज़ीज़ विश्वविद्यालय, सऊदी अरब ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान प्रवृत्तियों एवं भविष्य की संभावनाओं पर व्याख्यान दिया। इसके पश्चात डॉ. मनोज कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, दुबई ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु उन्नत इंजीनियरिंग एवं तकनीकी नवाचारों पर अपने विचार साझा किए।

12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में महिला मोर्चा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां

बलरामपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा बलरामपुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को राजपुर मंडल के महामाया मंदिर प्रांगण में किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी व प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती फुलेश्वरी सिंह रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती शशिकला भगत, जिला अध्यक्ष श्रीमती सुषमा मिंज, सरगुजा महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती प्रियंका चौबे, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुबिन्दा आयम, जिला मंत्री श्रीमती गायत्री प्रजापति और महामाया मंडल अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती यादव उपस्थित थीं।

अतिथियों ने अपने उद्बोधन में मोदी सरकार के 12 वर्षों की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। इसमें स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण योजना, लखपति दीदी योजना, किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण और युवा रोजगार पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में

मातृशक्ति ने रंगोली बनाकर सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। जिला अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को साल भेंट कर सम्मानित किया।मंच संचालन जिला महामंत्री श्रीमती मंजू भट्ट ने किया और आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री श्रीमती माधुरी लकड़ा ने किया। जिला महिला मोर्चा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, पूरी टीम, कार्यकर्ता बहनों और मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया।

55 की उम्र में भी स्वस्थ और ऊर्जावान हैं महेश कुमार दोहरे, 29 बार किया रक्तदान

सूरजपुर। रक्तदान को महादान कहा जाता है और इसे अपने जीवन में साकार कर दिखाया है विकासखंड रामानुजनगर के नगर पंचायत शिवनंदनपुर निवासी महेश कुमार दोहरे ने। वर्तमान में हाई स्कूल कोट के प्राचार्य के रूप में कार्यरत महेश कुमार दोहरे ने 1996 में 24 वर्ष की उम्र में एक गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए पहली बार रक्तदान किया था। उस दिन की घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी और तभी से उन्होंने रक्तदान को मानव सेवा का माध्यम बना लिया। आज 55 वर्ष की उम्र में भी महेश कुमार दोहरे पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे नियमित रूप से मैराथन दौड़ में भाग लेते हैं और प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अब तक 29 बार रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। महेश कुमार दोहरे

बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एक गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए रक्तदान किया था, तब उनके मन में जो संतोष और खुशी का अनुभव हुआ, वही भावना उन्हें लगातार रक्तदान के लिए प्रेरित करती रही। उनका कहना है कि रक्तदान केवल रक्त देना नहीं, बल्कि किसी परिवार को उसके अपने से मिलने वाली खुशी लौटाना है।

वे कहते हैं, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी दुर्घटना पीड़ित, गर्भवती महिला, सिकल सेल, थैलीसीमिया जैस बीमारी से जूझ रहे मरीज या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन की डोर बन सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से न केवल किसी की जान बचती है, बल्कि मन को भी अद्भुत शांति और खुशी मिलती है।

महेश कुमार दोहरे का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि नियमित रक्तदान से स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। 29 बार रक्तदान करने के बाद भी वे पूरी तरह स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान हैं। उनका समर्पण समाज के लिए प्रेरणा है और यह संदेश देता है कि यदि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति रक्तदान का संकल्प ले, तो किसी भी जरूरतमंद को रक्त के अभाव में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी।

प्राचार्य होने के नाते वे विद्यालय में विद्यार्थियों को भी सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करते हैं। वे बच्चों को रक्तदान के महत्व की जानकारी देते हुए बताते हैं कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर किसी जरूरतमंद की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा समाज में मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों को रक्तदान के लिए आगे आने का संदेश देती है। रक्तदान के माध्यम से अनगिनत जीवन बचाए जा सकते हैं और यही सच्ची मानव सेवा है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के आवेदनों में शिथिलता नहीं, त्वरित करें निपटान : कलेक्टर

बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, न्यायालयीन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना है। उन्होंने लंबित प्रकरणों की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का संतोषजनक निराकरण

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहायता पेंशन से संबंधित प्रकरणों को विशेष प्राथमिकता से निराकरण करें।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जनपद पंचायत के सीईओ को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रतिदिन प्रगति की निगरानी करने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए।

एग्रीस्टैक पंजीयन की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक पंजीयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसके बावजूद कई क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने, नियमित मैदानी भ्रमण कर प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्य को समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर ने समितिवार खाद एवं बीज की भण्डारण तथा उठाव की स्थिति की जानकारी लेते हुए किसानों को समय पर कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण पर फोकस करते हुए कलेक्टर ने निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीजी पोर्टल, जनदर्शन एवं जन शिकायत के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के भी निराकरण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के लंबित रहने से नागरिकों को अनावश्यक परेशानी होती है, इसके लिए त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए आपेक्षिक प्रगति लाएं।

वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव एवं जन सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें।

नोटिस बेअसर, अवैध निर्माण करने वालों ने सरपंच को दी धमकी

कलेक्टर-एसपी से शिकायत

- **सोमनी में व्यावसायिक परिसर की दुकानों में अवैध निर्माण का मामला**

जनधारा समाचार

राजनांदगांव। ग्राम सोमनी में व्यावसायिक परिसर की दुकानों को तोड़कर अवैध निर्माण कराने व्यापारी अपनी जिद में अड़ गए हैं। ग्राम पंचायत से नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण पर रोक नहीं लगी है, सरपंच नीलिमा साहू को दुकानदारों ने धमकी दे डाली। पूरे मामले की शिकायत सरपंच ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित एसडीएम से की है।

बता दें कि बीते 15 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत ने शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल से लगकर करीब 24 दुकानों का निर्माण कराकर आवंटन किया है। वर्तमान में इनमें से कई दुकानों की खरीदी बिक्री हो चुकी है, जिसके बाद से व्यापारी इस दुकानों में बगैर अनुमति तोड़फोड़ कर अवैध तरीके से निर्माण कराने में लग गए हैं। अभी हाल में चार दुकानों का निर्माण हो रहा है। इस अवैध निर्माण की शिकायत पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यापारी राजेश गुप्ता और जितेंद्र वैष्णव को नोटिस भेजा गया, यही नहीं सरपंच नीलिमा साहू ने व्यापारियों को मौखिक रूप से निर्माण कार्य रोकने की बात कही। इसके बाद भी व्यापारियों ने काम बंद नहीं किया, बल्कि सरपंच को ही व्यापारियों ने काम नहीं रोकने की धमकी दे डाली। निर्माण कार्य बंद नहीं करने और धमकी देने के मामले में सरपंच नीलिमा साहू ने व्यापारी जितेन्द्र वैष्णव और राजेश गुप्ता के खिलाफ कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

नोटिस के बाद करा दी ढलाई

व्यावसायिक परिसर की चार दुकानों का निर्माण बिना पंचायत की अनुमति से हो रहा है। दुकानों को तोड़कर अवैध निर्माण कराने वाले व्यवसायी पंचायत से नोटिस जारी कर तत्काल काम रोकने के निर्देश दिए गए, लेकिन व्यापारियों ने मनमानी कर दुकानों की छत की ढलाई करा दी है।

सरपंच ने की कार्रवाई की मांग

सोमनी सरपंच नीलिमा साहू ने कहा कि अवैध निर्माण की शिकायत पर व्यवसायियों को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद भी व्यवसायी ढलाई का काम करा लिए है। सरपंच ने बताया कि काम पर रोक लगाने की बात कहने पर व्यवसायी जितेंद्र वैष्णव ने जो करना है कर लो, देख लूंगा जैसे शब्द बोलकर धमकी दी है। व्यवसायी जितेंद्र वैष्णव और राजेश गुप्ता के खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत की गई है। पंचायत अधिनियम के तहत भी निष्पक्ष जांचकर कार्रवाई की मांग की है।

समय-सीमा बैठक में मानसून तैयारियों एवं खरीफ उर्वरक वितरण की हुई व्यापक समीक्षा

- **सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण तथा जर्जर भवनों में संस्था संचालन पर रोक के दिए निर्देश**

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में मानसून की पूर्व तैयारियों, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि आमजन तक उनका प्रभावी लाभ सुनिश्चित करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आमजन की समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण मंच है और सभी संबंधित अधिकारी हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निराकरण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए जिले में उर्वरक भंडारण एवं वितरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। विकासखंड एवं समितिवार यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी तथा पोटाश की उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली गई। समीक्षा में सामने आया कि जिले में वर्ष 2026 के लिए कुल 43,420 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। 12 जून की स्थिति में 31,717 मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है, जबकि अब तक 14,394 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया गया है, जो लक्ष्य का 33 प्रतिशत एवं भंडारण का 45 प्रतिशत है।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने निर्देश दिए कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद समितियां शनिवार को भी खुली रखी जाएं। उन्होंने कृषक बंधुओं से अपील की कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार खाद का उठाव सुनिश्चित करें ताकि मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखी जा सके। साथ ही जिन विकासखंडों में वितरण की गति धीमी है, वहां इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी सांसों का बैंक हैं: विवेक मोनू भंडारी

डोंगरगढ़। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य को लेकर समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी विवेक मोनू भंडारी ने लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जल संकट के दौर में वृक्ष मानव जीवन के सबसे बड़े प्राकृतिक संरक्षक हैं।

भंडारी ने कहा कि लोग अक्सर पेड़ों को केवल लकड़ी या ईंधन का साधन मानते हैं, जबकि वास्तव में पेड़ हमारी सांसों का बैंक हैं। जिस तरह बैंक में धन जमा कर भविष्य सुरक्षित किया जाता है, उसी तरह वृक्ष ऑक्सीजन का भंडार तैयार करते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं।

उन्होंने कहा कि लगातार हो रही वृक्ष कटाई के कारण पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। इसका असर बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखते जलस्रोत और भूजल स्तर में गिरावट के रूप में सामने आ रहा है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

भंडारी ने बताया कि वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण, मिट्टी कटाव रोकने और तापमान नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान सराहनीय हैं, लेकिन पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है।

उन्होंने नागरिकों से जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। विशेष रूप से बरगद, पीपल और नीम जैसे दीर्घायु वृक्षों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि अनुपयुक्त स्थानों पर उग आए पौधों को नष्ट करने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रोपित किया जाना चाहिए।

भंडारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही यह अभियान सफल हो सकता है। स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को मिलकर जनजागरण अभियान चलाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण और संरक्षण से जुड़ सकें।

जनदर्शन में कलेक्टरने सुनी आमजनों की समस्याएं

बलरामपुर। आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के पश्चात जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में मांग व शिकायत के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए जिसमें आमजनों द्वारा विभिन्न विषयों संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये गए। प्राप्त आवेदनों का कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी अवि मानिकपुरी का किया सम्मान

राजनांदगांव। अंडर-19 एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले युवा हॉकी खिलाड़ी अवि मानिकपुरी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने अवि की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवि मानिकपुरी की उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है तथा उनकी सफलता से अन्य खिलाड़ी भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होंगे।

अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम के सदस्य के रूप में अवि मानिकपुरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की स्वर्णिम सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि अवि मानिकपुरी ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर भारतीय टीम में स्थान बनाया तथा एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए अवि एक प्रेरणास्रोत हैं और उनकी सफलता से खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह और बढ़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि हॉकी भारत का गौरवशाली खेल है और इस खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। अवि मानिकपुरी ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। अवि मानिकपुरी मूलतः छत्तीसगढ़ से हैं और अपनी मेहनत, लगन एवं अनुशासित खेल शैली के बल पर उन्होंने भारतीय टीम में स्थान बनाया। उनकी इस सफलता ने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में नया उत्साह भर दिया है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कोरिया में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ

- **जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक प्रदर्शित**

कोरिया,। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कोरिया जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ मानस भवन बैकुंठपुर में किया गया।

इस प्रदर्शनी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के पूर्व संसदीय सचिव अवधेश चंदेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विगत 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें वित्तीय समावेशन, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, आधारभूत संरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी जा रही है। तीन दिवसीय फ़ोटो प्रदर्शनी 17 जून तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देशभर में शौचालय निर्माण जैसी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया अभियान एवं ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है।

पंडो बाहुल्य बस्ती में पहुंची स्वास्थ्य टीम

बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में संभावित महामारी की रोकथाम एवं ग्रामीणों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत चेरा के आश्रित पंडो बाहुल्य हरिजन पारा में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।शिविर के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य टीम द्वारा 17 लोगों का रक्तचाप (बीपी) परीक्षण, 17 लोगों की शुगर जांच तथा 46 लोगों की हीमोग्लोबिन जांच की गई। साथ ही खुजली से पीड़ित 15 मरीजों, दर्द संबंधी समस्या वाले 5 मरीजों तथा दाद से प्रभावित 6 मरीजों का उपचार किया गया। 5 लोगों की कुष्ठ रोग संबंधी जांच भी की गई। शिविर में कुल 54 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाइयां एवंचिकित्सकीय सलाह प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सक्रिय सहभागिता का किया आह्वान

- **बच्चों की मुस्कान, शिक्षा का सम्मान- यही विकसित छत्तीसगढ़ की पहचान-सीएम साय**

कोरिया। नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को शुभकामनाएँ देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात कही है। इसी क्रम में 16 जून से 27 जून तक प्रदेशभर में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों सहित जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों तथा नगरीय निकायों के महापौर एवं अध्यक्षों को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा प्रत्येक बालक-बालिका का विद्यालय में प्रवेश एवं नियमित अध्ययन सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में सुविधानुसार किसी एक दिवस उपस्थित होकर इस अभियान में सहभागी बनें तथा ऐसे बच्चों की पहचान एवं नामांकन हेतु प्रेरित करें, जो अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इससे यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप प्राप्त करेगा।

शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा रहा है। पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण विकसित किया जा रहा है तथा वर्ष 2026 से 150 विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित किए जाने की योजना है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शासकीय विद्यालयों को आधुनिक, तकनीक-संपन्न एवं छात्र-केंद्रित संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है-बच्चों की मुस्कान, शिक्षा का सम्मान-यही विकसित छत्तीसगढ़ की पहचान है।

गलवान के वीर शहीद गणेश कुंजाम की छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई

चारमा। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ग्राम गिधाली के वीर सपूत, शहीद गणेश कुंजाम की छठी पुण्यतिथि 15 जून को उनके गृह ग्राम में अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहीद के परिजनों द्वारा उनके स्मारक स्थल पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

नम आंखों से दी गई पुष्पांजलि

सुबह से ही शहीद गणेश कुंजाम के स्मारक पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होने पहुंचे। सैनिक कल्याण बोर्ड एवं पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी, चारमा थाना पुलिस जवानों की टीम,बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, सभी उपस्थित लोगों ने शहीद के स्मारक पर माल्यार्पण कर, पूजा-अर्चना की और नम आंखों से पुष्पांजलि

अर्पित करते हुए उन्हें याद किया।

लाखों सैनिकों में अलग पहचान बना गए गणेश— थाना प्रभारी

इस गरिमामयी अवसर पर शहीद की वीरता को नमन करते हुए चारमा थाना प्रभारी सुरेश राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लाखों सैनिक हमेशा डटे रहते हैं और अपना सर्वोच्च त्याग करते हैं। लेकिन उन लाखों में से कुछ सैनिक ऐसे होते हैं, जो बेहद कम उम्र में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बना लेते हैं। वीर गणेश कुंजाम उन्हीं में से एक थे। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज पूरे चारमा, कांकेर और छत्तीसगढ़ में उनका नाम गूंज रहा है। उनकी वीरता की कहानी आज भी हर नागरिक की जुबान पर है। थाना प्रभारी ने ऐसे वीर सपूत को जन्म देने के लिए उनके माता-पिता और परिजनों के प्रति विशेष आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।

आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणापुंज हैं शहीद

पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से आए पदाधिकारियों ने भी शहीद गणेश कुंजाम को याद करते हुए कहा कि ऐसे जांबाज जवानों के कारण ही आज देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। इनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और आने वाली पीढ़ियां इस सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा लेकर खुद को देश सेवा के लिए तैयार करेंगी।

वर्ष 2020 की गलवान घाटी झड़प में हुए थे शहीद

इस दौरान शहीद के परिजनों ने भी भावुक होते हुए गणेश कुंजाम की यादों और उनकी बातों को ग्रामीणों के बीच साझा किया। विदित हो कि 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सपूत गणेश कुंजाम ने अपने 20 साथी जवानों के साथ वीरगति प्राप्त की थी। देश उनके इस सर्वोच्च बलिदान को हमेशा नमन करता रहेगा।

12 साल- सेवा के, सुशासन पर सूरजपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन

सूरजपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सफल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूरजपुर जिले के पुराने बस स्टैंड पर '12 साल - सेवा के, सुशासन के, जनविश्वास के' थीम पर एक भव्य छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 17 जून से 19 जून 2026 तक आयोजित होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन 17 जून को सायं 4 बजे किया जाएगा।

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION Co. Ltd.
(A Government of Chhattisgarh Undertaking) CIN-U40108CT2003SGC015820
O/o Chief Engineer (Sub-station), Raipur Address-Shed No.-04, Danganiya, Raipur-492013 Website-www.cspc.co.in
E-Mail-CE.TnC@cspc.co.in, Phone-0771-2574256, Fax No.-0771-2574267

No. 02-07/Tender/P-1954/298 Raipur, Dtd. 12.06.2026

NOTICE INVITING TENDER (Through E-bidding module of SAP-SRM)

Sealed tenders are invited from experienced eligible bidders for following work on labour contract basis :-

S. No.	Particulars of works	Qty.	EMD (Rs.)	Last date/ time for submission of tender
1.	Loading of 132/33KV, 63 MVA Technical Associates make X-mer, Sl No.SP -1350-5 Tank (oil filled up to core level) with all accessories including available balance oil drum at 132KV S/s Gudhiyari and its transportation to 132KV S/s Birgaon (Approx. 10 Kms.) and thereafter its unloading at suitabl e place in substation switchyard of 132KV s/s Birgaon (At both end dragging may be done, if required. Hence, bidder may visit the site before submitting the offer). **The Details of X-mer are given here under :- Sr.No.: SP -1350-5, YOM :2025, Mass of oil : 24000/29250 Ltr., Total weight of X -mer – 103000 Kg** including accessories and complete oil.	01 Job	9,500/-	22/06/2026 14:00 Hrs.

NOTE :- (I) Other terms & condition details etc. regarding tender can be seen on our website www.cspc.co.in

SAVE ELECTRICITY S-48159/3

Superintending Engineer
O/o Chief Engineer (Sub-Station)CSPTCL: Raipur(C.G.)

ट्रंप-वेंस और गालिबाफ ने शांति समझौते पर किए डिजिटल हस्ताक्षर, 19 जून को जिनेवा में लगेगी मुहर

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर दोनों पक्षों ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किए जाएंगे, जिसके बाद यह प्रभावी हो जाएगा।

ईरान को कब मिलेगी आर्थिक राहत और प्रतिबंधों में छूट?

उपराष्ट्रपति वेंस ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि समझौते के तहत ईरान को किसी भी प्रकार की आर्थिक राहत या प्रतिबंधों में छूट तभी मिलेगी, जब वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक ईरान को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है और यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रदर्शन आधारित होगी। वेंस के अनुसार, यदि ईरान अपने संवर्धित परमाणु सामग्री के भंडार को कम करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था को स्वीकार करने जैसे कदम उठाता है, तो अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में दोबारा शामिल होने का अवसर देना है, बशर्ते वह समझौते की शर्तों का पालन करे।

औपचारिक हस्ताक्षर के बाद ही सार्वजनिक होगा समझौता- ट्रंप

वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते का पूरा हिस्सा शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उपराष्ट्रपति वेंस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होंगे, जबकि उनकी अपनी उपस्थिति अभी तय नहीं है। ट्रंप ने इस समझौते को क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने वाला महान समझौता बताया है। उनका दावा है कि इसके लागू होने के बाद क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा लाभ मिलेगा तथा लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने ये भी कहा कि शुक्रवार तक होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुल जाएगा।

क्या है समझौते का मुख्य उद्देश्य?

फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा, डील पर पूरी तरह से साइन हो गए हैं और जलडमरूमध्य आंशिक रूप से खुल भी गया है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से अहम यह जलमार्ग शुक्रवार तक पूरी तरह से खुल जाएगा, जो ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई को बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। इस प्रारंभिक समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लागू नाजुक युद्धविराम को मजबूत करना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का रास्ता तैयार करना है। यह समुद्री मार्ग दुनिया में तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालांकि, जलडमरूमध्य को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने के बाद ही खोला जाएगा।

अमेरिका-ईरान के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी- अराघची

वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि शुक्रवार के समारोह के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों और अमेरिका द्वारा कथित रूप से किए गए वादाखिलाफी को देखते हुए ईरान बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान इस समझौते के जरिए देश के लिए अधिकतम आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा।

शांति समझौते के सामने हैं कई बड़ी चुनौतियां

हालांकि, समझौते के सामने कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच जारी तनाव तथा लेबनान से जुड़े मुद्दे अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। ईरान लगातार कहता रहा है कि लेबनान से जुड़े मुद्दों को अंतिम समझौते का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उधर, इस्राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कहा कि ट्रंप और ईरान के बीच हुआ समझौता इस्राइल पर बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्राइल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है तथा वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा।

मैं शिलांग में हूं, नेपाल नहीं भागी

इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी जमानत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर है। उन्होंने ईस्ट मोजो को दिए साक्षात्कार में कहा कि, मैं शिलांग में हूं। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं नेपाल चली गई। जिन शर्तों पर मुझे जमानत मिली है, उनका मैंने पूरा पालन किया है। केस खत्म होने तक मैं इंदौर भी नहीं आऊंगी।

सोनम ने कहा कि वह शिलांग में कहां रुकी हुई हैं, इसका खुलासा वह सुरक्षा कारणों से नहीं करेंगी। खुद पर लगे हत्या के आरोप को लेकर उन्होंने कहा, अभी इस केस का ट्रायल चल रहा है। इस बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। सोनम ने कहा कि उनका खर्च कैसे चल रहा है, इस बारे में भी वह कोई खुलासा नहीं करेंगी। यह उनका निजी मामला है। दरअसल, राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने आरोप लगाया था कि सोनम संभवतः नेपाल भाग गई है। उनके वकील भी नेपाल के हैं। उन्होंने इसमें मदद की है। इसके बाद सोनम सोमवार को मीडिया के सामने आई और अपनी बात रखी।

मूर्ति नग्न थी, एनसीईआरटी ने ढंककर छापी

- कांसे की प्रतिमा 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी, अभी नेशनल म्यूजियम में

नई दिल्ली। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति की फोटो बदले हुए रूप में छापी गई है। एनसीईआरटी की किताब में मूर्ति के ढंके धड़ वाली फोटो है। मूर्ति का रंग भी बदल दिया गया है। नर्तकी की तस्वीर 9वीं की किताब मधुरिमा के पहले चैप्टर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में दी गई है। तस्वीर में कंधे से नीचे का हिस्सा ढंक दिया गया है, जबकि मूल मूर्ति में यह हिस्सा खुला दिखाई देता है। 25 साल से छप रही इस कांस्य मूर्ति के मूल स्वरूप में पहले कभी बदलाव नहीं किया गया था।

यह किताब एनसीईआरटी की नई आर्ट्स एजुकेशन सीरीज का हिस्सा है, जिसे नई शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत तैयार किया गया है। अब तक क्लास 1 से 9 तक की किताबें जारी की जा चुकी हैं।

इतिहासकार बोले- यह सेंसरशिप है: इतिहासकार मिशेल डैनिनो ने तस्वीर में किए गए बदलाव को छात्रों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि मूर्ति के पूरे धड़ को ढंकना सेंसरशिप है। इससे ऐसी मूर्ति दिखाई गई है, जो असल में कहीं मौजूद नहीं है। डैनिनो ने सवाल उठाया कि क्या अब छात्रों को नेशनल म्यूजियम में रखी मूल प्रतिमा और दूसरी अर्धनग्न या नग्न ऐतिहासिक मूर्तियां देखने से भी रोका जाएगा?

एनसीईआरटी बोला- कोई खास वजह नहीं: तस्वीर में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि छठी क्लास की सोशल साइंस किताब में नर्तकी की तस्वीर अपने मूल रूप में मौजूद है और यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खोजों में से एक है।

पहले भी तस्वीर पर उठी थी आपत्ति: इतिहासकार मिशेल डैनिनो ने मई में बताया था कि एनसीईआरटी ने सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर के पहले पेज पर नर्तकी की फोटो लगाने पर आपत्ति जताई थी। डैनिनो उस समय एनसीईआरटी की छठी क्लास की नई सोशल साइंस किताब की 'टेक्स्टबुक डेवलपमेंट कमेटी' के प्रमुख थे। डैनिनो के मुताबिक, कुछ लोगों का मानना था कि मूर्ति के नग्न वाले स्वरूप को लेकर विवाद हो सकता है। बाद में तस्वीर को चैप्टर की शुरुआत से हटाकर अंदर के पन्ने पर छोटे रूप में रखा गया था, लेकिन तस्वीर को हटाया नहीं गया। डैनिनो ने कहा था कि अगर नर्तकी की फोटो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फिर उन्हें नेशनल म्यूजियम भी नहीं जाना चाहिए, जहां यह मूर्ति रखी हुई है।

मूर्ति से जुड़ी 3 जरूरी बातें: डांसिंग गर्ल नाम से मशहूर करीब 4 इंच की कांस्य मूर्ति 1926 में मोहनजोदड़ो से मिली थी। मूर्ति में जूड़ा बांधे एक युवती को दिखाया गया है, जिसके हाथों में चूड़ियां और गले में हार है। प्रतिमा में युवती अपना दाहिना हाथ कमर और बायां हाथ जांघ पर रखे हुए है। मूल मूर्ति नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है।

हिमाचल में पेट्रोल और डीजल संकट

केंद्र के आदेश किसानों-बागवानों पर पड़ रहे भारी

- कैनी-बोतल में ईंधन नहीं, स्प्रे-गुड़ाई जैसे काम ठप

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर जारी केंद्र सरकार के आदेशों ने किसानों व बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में किसानों और बागवानों को खुले कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे खेती व बागवानी से जुड़े काम बुरी तरह प्रभावित होने लगे हैं।

कैनी और बोतल में पेट्रोल-डीजल देने पर सख्ती के बाद पंप संचालक खुले में ईंधन नहीं दे रहे। इससे पावर स्प्रेयर, पावर टिलर, ग्रास कटर, वुड कटर, पानी के पंप, मिनी टिलर इत्यादि शो-पीस बन गए है। राज्य की आर्थिकी में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान देने वाले सेब बगीचों में इन दिनों स्प्रे होती है, लेकिन उसके लिए पेट्रोल पंप संचालक ईंधर नहीं दे रहे। इससे बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह, दूसरे कृषि उपकरणों के लिए भी पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा। प्रदेश में इससे हाहाकार जैसी स्थिति बनने लगी है।

केंद्र के आदेश भारी पड़ रहे: रमेश: ठियोग के बागवान रमेश शर्मा ने बताया कि बागवान पहले ही मौसम की मार झेल रहे हैं। अब केंद्र सरकार के नए आदेश उनके लिए नई परेशानी बन गए हैं। सेब बागानों में इस समय स्प्रे करना बेहद जरूरी है, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलने के कारण वे स्प्रे का काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे फसलों पर बीमारियों और कीटों का खतरा बढ़ सकता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश लागू किए जा रहे: रचित- इंडियन ऑयल सर्विस (आईओएस) के स्टेट कोऑर्डिनेटर रचित अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा प्रमाणित कंटेनरों में ही पेट्रोल-डीजल दिया जा सकता है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियां इन्हीं नियमों का पालन कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार खुले कंटेनरों में ईंधन देने की अनुमति देती है तो तेल कंपनियों को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोबारा शुरू हुई जांच

कोलकाता। बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वर्ष 2024 में दुष्कर्म के बाद प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या के मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ के अधिकारियों की एक टीम सोमवार को अस्पताल पहुंची।

टीम में संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी समेत कुल छह अधिकारी शामिल थे। टीम ने अस्पताल के प्राचार्य, चिकित्सा अधीक्षक, उप-प्राचार्य और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। जहां यह अपराध हुआ था। अस्पताल परिसर में नौ अगस्त 2024 की रात महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट किए जाने और मामले को दबाने की कोशिश किए जाने के भी आरोप लगे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले महीने इस मामले में सबूत नष्ट किए जाने के आरोपों और पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए विशेष आरोपों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे।

स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान

- प्रधानमंत्री का ये 33वां ग्लोबल ऑनर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। इस दौरान स्लोवाकिया ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास) से सम्मानित किया। अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित करने वाला स्लोवाकिया 33वां देश है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा।

द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास) स्लोवाकिया सम्मान है। यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति की ओर से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है।

इससे पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए इसे राजनीतिक चमत्कार बताया था। उन्होंने कहा, इतने विविध और जटिल राजनीतिक माहौल में लगातार 12 सालों तक नेतृत्व बनाए रखना असाधारण उपलब्धि है। रॉबर्ट फित्सो ने आगे कहा कि मैं उस राजनीतिक स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, यह उपलब्धि एक राजनीतिक चमत्कार के बराबर है, और यह भारत की लोकतांत्रिक ताकत और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है।

जिसे मैंने दुर्गा कहा, कैसे छोड़ूंगी उन्हें...

- विधायक पत्नी ने नहीं छोड़ा ममता का साथ, सांसद पति ने की बगावत

कोलकाता। बंगाल की राजनीति के निराले रंग देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी में फूट के बाद सांसद पति ने ममता का साथ छोड़ दिया है, लेकिन विधायक अभी भी पूर्व सीएम ममता के साथ है। वो ममता बनर्जी के नाम पर कसमें खा रही हैं। टीएमसी की इस महिला नेत्री ने कहा कि मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूं जिसे मैंने दुर्गा कहा है। ये कहानी पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता सुदीप बंदोपाध्याय और नयना बंदोपाध्याय की है।

बंगाल की राजनीति के जाने-माने चेहरे सुदीप बंदोपाध्याय रविवार को टीएमसी छोड़ बागियों के गुट में आकर मिल गए और बाद में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। सुदीप बंदोपाध्याय उत्तरी कोलकाता से सांसद भी हैं।

सुदीप बंदोपाध्याय ने 19 अन्य बागी सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि वे सांसद के रूप में एनडीए का समर्थन करेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय के पार्टी छोड़ने के बाद उनकी विधायक पत्नी नयना बंदोपाध्याय की राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा होने लगी। कई नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कहा कि नयना अपनी राहें टीएमसी से अलग कर लेंगी। लेकिन नयना ने इन सारी अटकलों को खारिज किया है। नयना ने कहा है कि वे ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगी।

नयना ने कहा कि उनके पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ममता को अपना नेता मान लिया है। यह बात उनके लिए बिल्कुल सच है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि अगर ममता बनर्जी उन्हें छोड़ भी दें, तो भी वे उन्हें नहीं छोड़ेंगी। नयना बनर्जी के शब्दों में, मैं दीदी के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई हूं। वह मुझे छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूं जिन्हें मैंने अपनी दुर्गा कहा है? दीदी मुझे छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।

तमिलनाडु में 3 साल की बच्ची से रेप, मौत

पटना। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची रविवार से लापता थी। सोमवार को वह झाड़ियों में गंभीर हालत में मिली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 19 साल के विबिन मंच के तौर पर हुई है, जो तिरुवल्लूर में मजदूरी करता है। वहीं पीड़ित परिवार भी बिहार का ही बताया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार को आरोपी बच्ची को बिस्किट का लालच देकर अपने साथ ले गया था। जिसके बाद बच्ची घर नहीं लौटी। सोमवार को एक महिला ने झाड़ी में बच्ची को गंभीर हालत में देखा। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं, पुलिस ने बताया कि बच्ची आरोपी को जानती थी।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर फिर तनाव

- 9 बांग्लादेशी नागरिकों को बीजीबी ने वापस लेने से किया इनकार

गुवाहाटी। असम के मनकाचर सेक्टर में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। नो-मैन्स लैंड (दोनों देशों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की भूमि) में 9 बांग्लादेशी नागरिक फंसे हुए हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) इन नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है।

फ्लैग मीटिंग बेनतीजा

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) और बीजीबी के बीच कई दौर की फ्लैग मीटिंग भी हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक बेनतीजा रही। बीएसएफ सूत्रों ने बताया कि आज फिर से दोनों पक्षों के बीच नई बैठक होगी, जिसमें इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

रविवार को फैला तनाव

रविवार को मनकाचर इलाके में जब 9 व्यक्ति नो-मैन्स लैंड में फंसे पाए गए, तो तनाव बढ़ गया। एक वायरल वीडियो में उनमें से एक व्यक्ति साफ तौर पर कहता सुनाई दे रहा है, हम बांग्लादेशी नागरिक हैं। काम के सिलसिले में भारत आए थे। हमारे पास दस्तावेज हैं। भले ही हमें मार दिया जाए और नदी में फेंक दिया जाए, हम भारत नहीं जाएंगे। अन्य वीडियो में इन लोगों को रोते हुए भी देखा गया है।

बीएसएफ की सख्ती

बीएसएफ ने हाल के दिनों में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा है। पिछले हफ्ते असम पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में 21 घुसपैठियों को रोका गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कार्रवाई की सराहना की।

प्रथम पेज का शेष

बिजली हुई महंगी, बढ़ेगा...

शाम 5 से रात 11 बजे तक उपयोग पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क। 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ऑफ-पीक समय में 20 पैसे प्रति यूनिट छूट। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए टैरिफ 7.13 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित। महिला स्व-सहायता समूहों को ऊर्जा शुल्क में 10 प्रतिशत छूट जारी। ग्रामीण, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों को 10 प्रतिशत छूट जारी। पोहा और मुरमुरा मिलों को ऊर्जा शुल्क में 10 प्रतिशत छूट जारी।

हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं के लिए अहम फैसलेः हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 6.42 रुपए प्रति केवीएएच तय। स्टोन माइंस को एचवी-3 औद्योगिक श्रेणी में शामिल किया गया। आयरन वाशरी और बेनिफिसिएशन प्लांट को एचवी-4 श्रेणी में रखा गया। छोटे और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को पहले 5 वर्षों तक डिमांड चार्ज से छूट जारी। सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क संबंधी नई व्यवस्था लागू। पैरेलल ऑपरेशन चार्ज 16 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया आधारित ऊर्जा पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं लगेगा।

उपभोक्ताओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण फैसले : अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत की गई। विलंबित भुगतान अधिभार 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की जगह 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन होगा। प्रीपेड मीटर वाले एलवी उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई। विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिए नया क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज भी तय किया गया है।

अभिजीत दीपके को जड़ दिया...

पर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया था। नारेबाजी के दौरान शुरू हुआ विवाद धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और एक युवक को कस्टडी में लिया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और कार्यक्रम आगे बढ़ा।

कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल हुए चोरीः धरनास्थल पर भीड़ के बीच मोबाइल चोरी की घटनाएं भी सामने आईं। कई लोगों ने अपने फोन गायब होने की शिकायत की। शिकायतें बढ़ने पर मंच से आयोजकों ने लोगों से अपने मोबाइल और कीमती सामान सुरक्षित रखने की अपील की। साथ ही भीड़ में सक्रिय चोरों से सावधान रहने को कहा गया।

प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने हाथों में विभिन्न संदेशों वाले पोस्टर लिए हुए थे। पोस्टरों पर मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है, पेपर लीक बंद करो और युवाओं को न्याय दो जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर भी पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

भरोसे की आड़ में धोखा :...

एक होटल में शक्कर कारोबारियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में व्यापारिक गतिविधियों, सप्लाई व्यवस्था और भविष्य के लेन-देन को लेकर चर्चा हुई थी। कारोबारियों का आरोप है कि इसी दौरान भरोसे का माहौल बनाकर बड़ी मात्रा में माल उठाया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रायपुर और सरगुजा संभाग के 8 से अधिक कारोबारी इस कथित धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। प्रभावित व्यापारियों के अनुसार कुल बकाया राशि दो करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि वास्तविक राशि और प्रभावित लोगों की संख्या जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा व्यापारिक दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड और आर्थिक लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित धोखाधड़ी में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का....

में ओवररेटिंग, किसानों की समस्याएं, नगरीय निकायों के मुद्दे और विभिन्न विभागों में हालिया विवादों को लेकर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आमने-सामने की स्थिति बन सकती है। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पास हुआ था। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बजट सत्र के आखिरी दिन सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पास हुआ।

भाई को खान सर ने मरवायाः...

हम लोग क्यों करेंगे ऐसा। किसी अन्य ने भी उसको नहीं मारा। वो पहले से बीमार था। खान सर वीडियो में एक न्यूज क्लिप दिखाया, जिसमें प्रिंस यादव के दोस्त यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रिंस का पहले से दवाई चलता था। उसको दो बार अटैक आ चुका है। प्रिंस के दोस्त इस वीडियो क्लिप में कहते हैं, उसे किसी ने कुछ नहीं किया है। 2-3 दिन से वो ठीक से सो नहीं रहा था। कल भी हम लोग देखे कि सो रहा है तो हम लोगों को लगा कि चलो अब वो सो रहा है।

न्यूयॉर्क में एनबीए की जीत का जश्न बना हिंसा का अखाड़ा

बेकाबू भीड़ ने स्कूल बसों में लगाई आग, 63 लोग गिरफ्तार

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में शनिवार, 13 जून की रात भारी हंगामा और हिंसा हुई। निक्स के एनबीए (नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन) खिताब जीतने का जश्न मना रही बेकाबू भीड़ ने टाइम्स स्क्वायर में एनवायपीडी की गाड़ियों में तोड़-फोड़ की और फीफी की बसों में आग लगा दी। न्यूयॉर्क शहर में हुई इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हंगामे के दौरान कम से कम 15 संदिग्धों पर आपराधिक आरोप लगे हैं। इस घटना में 17 साल के लड़के के पैर में गोली लगी और चार लोगों पर चाकू से हमला हुआ।

हिंसा के लिए कोई जगह नहीं: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने रविवार को कहा कि ज्यादातर न्यूयॉर्क वासियों ने सही तरीके से जश्न मनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। ममदानी ने कहा कि हमने बार-बार कहा है कि हम चाहे कितने भी उत्साहित क्यों न हों, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हो या किसी और के। मैं हमारे शहर को सुरक्षित रखने के लिए एनवायपीडी के सभी लोगों की तारीफ करता हूं।

बेकाबू भीड़ ने बसों में लगाई आग: पुलिस के मुताबिक, जश्न के दौरान हिंसा करने वालों पर कई आरोप लगाए गए हैं। इनमें टेक्सस के अर्लिंग्टन के 28 वर्षीय व्यक्ति पर पुलिस अधिकारी पर हमला, हथियार रखने, आपराधिक तोड़-फोड़, अव्यवस्थित व्यवहार, गिरफ्तारी का विरोध और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा है।

आज की जनधारा

कारोबार जनधारा

मंगलवार, 16 जून 2026

तिरछी नज़र से

UPI: पैसा गया, पर 'डिजिटल' रहे - यही काफी है न?

प्रभातदत्त झा

सुधी पाठकों, हम एक महान युग में जी रहे हैं। वह युग जब जेब में पैसा न हो तो भी आप 'Digital India' के नागरिक हैं। पहले गरीब वह होता था जिसके पास पैसे नहीं होते। अब गरीब वह है जिसके पास QR Code नहीं है। हमने तरक्की की है। UPI आने के बाद से देश में एक नई समस्या पैदा हुई है- अब यह नहीं पता चलता कि पैसे गए कब। पहले नोट निकालते थे तो दर्द होता था- 'हाय, सौ का नोट गया।' अब UPI करते हैं - उँगली हिली, पाँच सौ गए, पता ही नहीं चला। Painless Surgery है-पर Painless Poverty भी।

हमारे पड़ोसी मिठाईलाल जी डिजिटल क्रांति के परम भक्त हैं। बोले, 'भाई साहब, मैं तो अब कैश छूता ही नहीं।' मैंने पूछा, 'क्यों?' बोले, 'क्योंकि कैश है ही नहीं।' यह Digital Minimalism का नया स्वरूप है। मिठाईलाल जी ने अपनी पत्नी को भी UPI सिखाया। पहले दिन पत्नी ने बाज़ार से सब्ज़ी का हिसाब दिया-'दो सौ की सब्ज़ी, पाँच रुपये Convenience Fee, और एक बार गलत QR scan हुआ तो पचास रुपये अलग।' मिठाईलाल जी बोले, 'यह तो कैश से भी महँगा पड़ा।' पत्नी ने कहा, 'पर Receipt मिली- Digital है।' मिठाईलाल जी चुप हो गए। Digital Receipt का वज़न तर्क से भारी होता है।

UPI फ्रॉड की बात करें तो आँकड़े रोमाँचक हैं-2024 में साइबर ठगी के 15 लाख से अधिक मामले। ठगों ने भी Digital India को दिल से अपनाया है। वे भी Work From Home करते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई Office नहीं – बस एक मोबाइल और आपकी 'ज़रा-सी असावधानी।' एक ठग ने फोन किया- 'सर, आपका KYC E&pire हो गया, अभी Update करें।' हमारे मित्र ने पूछा, 'कब?' ठग बोला, 'अभी-वरना Account Block।' मित्र ने OTP दे दिया। Account Block तो नहीं हुआ -पर Balance ज़रूर Block हो गया- ठग के खाते में।

सबसे मज़ेदार है 'Cashback' App कहता है -'इस दुकान पर Pay करो, 2% Cashback पाओ।' आप खुश होकर पाँच हज़ार खर्च करते हैं। सौ रुपये Cashback आता है-Coins में, जो सिर्फउसी App पर चलते हैं, जिसकी Validity तीन महीने है, और जिसे आप भूल जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे-'आपको एक मुफ्त साँस मिलेगी- अगले मंगलवार, हमारी App पर।'

बैंक ने नई सुविधा दी है-'Spend Analysis'। अब App बताता है कि आपने कहाँ-कहाँ पैसे उड़ाए। महीने के अंत में Graph आता है-Food: 40%, Entertainment: 25%, Shopping: 30%, Savings: 5%। यह Graph देखकर आप सोचते हैं - 'इतना खर्च कब हुआ?' App मुस्कुराता है। उसे पता है -जब पैसे दिखते नहीं, तो दर्द भी नहीं होता। और जब दर्द नहीं होता- तो खर्च रुकता भी नहीं।

निष्कर्ष-UPI ने सचमुच देश बदल दिया-लेन-देन आसान, जीवन सरल। पर एक सवाल मन में टीसता रहता है-जब हर पैसे का हिसाब App के पास है, बैंक के पास है, सरकार के पास है-तो क्या आने वाली पीढ़ी यह भी भूल जाएगी कि पैसे की 'खनक' कैसी होती थी? और जब खनक भूल जाए-तो उसकी कीमत कौन याद रखेगा?

पैसा बोलता है-पर किसकी भाषा में?

शेयर बाजार, क्रिप्टो और स्टार्टअप की असली कहानी

राजेश शर्मा

एक 26 वर्षीय युवक-पढ़ा-लिखा, नौकरीपेशा - YouTube पर 'Stock Market Tips' देखकर अपनी पाँच महीने की बचत लगाता है। तीन हफ्ते में आधी पूँजी स्वाहा। उधर एक गृहिणी WhatsApp पर आए 'Crypto Doubling Scheme' के लालच में फँसकर जेवर बेचती है। और एक स्टार्टअप संस्थापक-जिसके पास लाजवाब आइडिया है-फंडिंग के इंतजार में महीनों भटकता है। यही है आज के भारत के वित्तीय परिदृश्य की त्रासदी- अवसर भरपूर, जानकारी अधूरी, और जोखिम असीमित।

शेयर बाजार-उत्साह और भ्रम का महासमुद्र

भारतीय शेयर बाजार ने 2024-25 में ऐतिहासिक ऊँचाइयाँ छुईं- Sensex 85,000 और Nifty 26,000 के पार गया। SEBI के आँकड़े बताते हैं कि देश में Demat खातों की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई – जिनमें से 40 प्रतिशत खाते पिछले तीन साल में खुले हैं। यानी करोड़ों नए और अनुभवहीन निवेशक बाजार में उतरे हैं।

इनमें सर्वाधिक संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है जो Zerodha, Groww और Upstox जैसे ऐप्स से पहली बार निवेशक बने। Futures & Options (F&O) ट्रेडिंग में विस्फोटक वृद्धि हुई – पर SEBI की रिपोर्ट चौंकाती है: स्न×ह्न ट्रेड करने वाले 93 प्रतिशत व्यक्तिगत निवेशकों को नुकसान होता है। 2022-24 के दो

वर्षों में इन निवेशकों ने मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये गँवाए।

''बाजार ऊपर जाए तो खबर होती है - नीचे आए तो सिर्फ आम निवेशक का दर्द होता है, खबर नहीं।''

क्रिप्टो करेंसी-डिजिटल सपना या डिजिटल जाल?

Bitcoin ने 2024 में 1 लाख डॉलर का ऐतिहासिक स्तर छुआ। Ethereum, Solana और अन्य Alt-Coins ने भी जबरदस्त रिटर्न दिए। भारत में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या 10 करोड़ के पार बताई जाती है – जो अमेरिका से भी अधिक है।

लेकिन भारत में क्रिप्टो पर 30 प्रतिशत टैक्स और 1 प्रतिशत TDS ने इस बाजार को हतोत्साहित किया है। हजारों करोड़ का व्यापार विदेशी एक्सचेंजों पर शिफ्ट हो गया। इससे भी बड़ी समस्या है – Crypto Fraud। गृहिणियाँ और बुजुर्ग इसके सबसे आसान शिकार हैं। ED और CBI ने 2024 में 50,000 करोड़ से अधिक के क्रिप्टो फ्रॉड मामले दर्ज किए।

भारत सरकार अभी भी क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियामक ढाँचा तय नहीं कर पाई है। RBI और SEBI दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र का विवाद जारी है। जब तक नीति स्पष्ट नहीं होगी, तब तक आम निवेशक अंधेरे में ही चलेगा।

स्टार्टअप-'Unicorn' की दौड़ में 'Survival' की लड़ाई

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है-1.4 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और 115 से अधिक Unicorn (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्यांकन)। DPIIT और Startup India जैसी योजनाओं ने माहौल बनाया है।

लेकिन 2023-24 में 'Funding Winter' ने हकीकत उजागर की। कुल Venture Capital निवेश 2021 के 42 बिलियन डॉलर से घटकर 2023 में मात्र 8.5 बिलियन डॉलर रह गया। Byju's का पतन, Ola Electric की चुनौतियाँ, Paytm की नियामकीय परेशानियाँ – ये सब बताते हैं कि Valuation और Viability में फर्क होता है।

Tier-2 और Tier-3 शहरों के स्टार्टअप-जैसे बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर जैसे शहरों के उद्यमी- अभी भी Mentor Network, Angel Investment और Incubator तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करते हैं। असली स्टार्टअप क्रांति तब होगी जब यह महानगरों की सीमा से बाहर निकलेगी।

आम निवेशक के लिए सुरक्षित राह

SEBI ने 2024 में Investor Education के लिए कई नए कदम उठाए हैं-SIP (Systematic Investment Plan) की सरलीकृत प्रक्रिया, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान, और Index Fund को बढ़ावा। SIP के माध्यम से मासिक निवेश अब 23,000 करोड़ रुपये प्रतिमाह के पार पहुँच गया है- यह एक स्वस्थ संकेत है।

वित्तीय साक्षरता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। गृहिणियाँ यदि Recurring Deposit, PPF और SIP को समझ लें तो वे परिवार की वित्तीय रक्षक बन सकती हैं। युवा यदि F&O की जगह Inde& Fund में निवेश करें तो दीर्घकालिक सम्पदा बन सकती है।

सोचिए- जब शेयर बाजार में सट्टेबाजी को 'निवेश' कहा जाए, क्रिप्टो की चमक में बचत डूबे, और स्टार्टअप की परिभाषा सिर्फ महानगरों तक सिमटी हो-तो वित्तीय स्वतंत्रता किसकी? पैसे की भाषा समझना आज की सबसे जरूरी शिक्षा है-और जब तक यह शिक्षा हर घर, हर गाँव, हर गृहिणी और हर युवा तक नहीं पहुँचती, 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना आधा-अधूरा ही रहेगा।

जीवन बीमा निगम,बिलासपुर, छत्तीसगढ़
(कामरेड राजेश शर्मा सामाजिक-आर्थिक जीवन और गतिविधियों की गहरी समझ रखते हैं और आम जनता और मध्यम वर्ग पर विभिन्न मुद्दों के प्रभावों का बारीकी से वास्तविक आकलन करते हैं)

सुख, स्वास्थ्य और शिक्षा

इन्द्रसेन अग्रवाल

मनुष्य आदिकाल से ही सुख की खोज में लगा हुआ है। किसी ने धन-संपत्ति में सुख तलाशा, किसी ने सत्ता और वैभव में, तो किसी ने ईश्वर की उपासना और आत्मिक साधना में। हमारे मनीषियों ने भी जीवन के सात प्रमुख सुख बताए हैं, जिनमें सबसे पहला सुख है– ÷निरोगी काया।÷ यह कोई संयोग नहीं है। वस्तुतः स्वास्थ्य ही वह आधार है, जिस पर जीवन के अन्य सभी सुख टिके होते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो धन, पद, प्रतिष्ठा और सुविधाएँ भी उसे आनंद नहीं दे सकतीं।

स्वस्थ रहने की मानव की खोज उतनी ही पुरानी है जितनी उसकी सभ्यता। प्राचीन काल में रोग अपेक्षाकृत कम थे और उनके उपचार भी प्रकृति के निकट उपलब्ध थे। गाँवों में वैद्य और हकीम सेवा-भाव से चिकित्सा करते थे। चिकित्सा व्यवसाय नहीं, लोककल्याण का माध्यम थी। किंतु जैसे-जैसे मनुष्य प्रकृति से दूर और कृत्रिम जीवनशैली के निकट आता गया, वैसे-वैसे रोगों की संख्या और जटिलता दोनों बढ़ती गईं। मिट्टी के घरों की जगह कंक्रीट ने, प्राकृतिक जल की जगह शुद्धिकरण यंत्रों ने और खुली हवा की जगह वातानुकूलित कमरों ने ले ली। इसका प्रभाव केवल जीवनशैली पर नहीं, स्वास्थ्य पर भी पड़ा।

बढ़ती बीमारियों के साथ चिकित्सा का स्वरूप भी बदल गया। चिकित्सा शिक्षा महँगी हुई, विशेषज्ञता बढ़ी और धीरे-धीरे सेवा का स्थान व्यवसाय ने ले लिया। आज अनेक चिकित्सक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, किंतु चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त व्यवसायीकरण ने गंभीर प्रश्न भी खड़े किए हैं। कई बार अनावश्यक परीक्षण, महँगे उपचार और आर्थिक लाभ की प्रवृत्ति मरीजों तथा उनके परिजनों को मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक संकट में डाल देती है। जब स्वास्थ्य सेवा का केंद्र रोगी के स्थान पर लाभ कमाना बन जाए, तब समाज का विश्वास डगमगाने लगता है।

सुख की राह में दूसरा महत्वपूर्ण आधार है– शिक्षा। हमारे शास्त्रों ने विद्या को सर्वोच्च धन माना है -

''न चौरहार्यं न च राजहार्यं,
न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी।
व्यये कृते वर्धते एव नित्यं,
विद्याधनं सर्वधनप्रधान॥''

प्राचीन भारत में शिक्षा को धर्म और समाज सेवा का कार्य माना जाता था। गुरुकुलों में राजा और निर्धन, दोनों के पुत्र समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और समाज निर्माण था। गुरु और शिष्य के बीच विश्वास, अनुशासन और समर्पण का संबंध होता था।

समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला। बढ़ती जनसंख्या, प्रतिस्पर्धा और रोजगार की अनिश्चितता ने शिक्षा को बाजार से जोड़ दिया। आज शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का साधन कम और आर्थिक सफलता का माध्यम अधिक बनती जा रही है। छोटे-छोटे बच्चों पर भारी बस्तों का बोझ, अत्यधिक फीस, कोचिंग संस्कृति और अंकों की अंधी दौड़ ने बचपन की सहजता को प्रभावित किया है। अभिभावक अपनी आय का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने को विवश हैं। कई परिवार इसके लिए आर्थिक और मानसिक दबाव झेलते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बढ़ते व्यावसायीकरण का एक व्यापक सामाजिक प्रभाव भी दिखाई देता है। जब शिक्षा निवेश बन जाती है और चिकित्सा लाभ का साधन, तब नैतिक मूल्यों का क्षरण आरंभ होता है। व्यक्ति का ध्यान सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व से हटकर केवल आर्थिक लाभ पर केंद्रित हो जाता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और राष्ट्र की नैतिक संरचना को भी प्रभावित करता है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अनेक स्थानों पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण आम नागरिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उपचार से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ निजी संस्थानों को विस्तार का अवसर देती हैं, किंतु साथ ही लागत और शुल्क में असंतुलन भी पैदा करती हैं।

वास्तव में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनका आधार परोपकार, सेवा और मानवीय संवेदना होना चाहिए। समाज ने सदैव गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान सम्मान दिया है तथा चिकित्सक को जीवनदाता माना है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में विश्वास कमजोर होता है, तो उसका दुष्प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।

अतः समय की मांग है कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और संतुलन सुनिश्चित करे। निजी विद्यालयों की फीस तथा अन्य शुल्कों की नियमित समीक्षा हो, वहीं चिकित्सा संस्थानों में उपचार और जांच की प्रक्रियाओं का भी समय-समय पर परीक्षण किया जाए। सेवा और व्यवसाय के बीच आवश्यक संतुलन स्थापित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा केवल सुविधाएँ नहीं, बल्कि सभ्य समाज की आधारशिला हैं। यदि इन दोनों क्षेत्रों में सेवा, संवेदना और नैतिकता को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सके, तभी 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का आदर्श वास्तविकता के निकट पहुँच सकेगा। सुखी समाज का मार्ग न केवल धन और विकास से, बल्कि स्वस्थ शरीर, सुशिक्षित मन और सुदृढ़ नैतिक मूल्यों से होकर जाता है।

सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर,
नेहरूनगर बिलासपुर

कोचिंग संस्कृति का मनोविज्ञान: दबाव, उम्मीद और 'एसथेटिक' सपनों का गहरा खेल

बिलासपुर-जांजगीर-चांपा की गलियों से लेकर रायपुर तक, चंडीगढ़ से त्रिवेन्द्रम तक और जयपुर से गौहाटी तक कोटा से पुणे तक्आजकल हर घर में 10वीं-12वीं के बच्चे कोचिंग संस्कृति के चक्रव्यूह में फंसे नजर आते हैं। यह संस्कृति अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि पूरे परिवार के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा 'गेम चेंजर' बन चुकी है।

संजय कुमार मिश्रा

कोचिंग संस्कृति का मनोविज्ञान गहरा, जटिल और दोधारी तलवार है। एक तरफ यह महत्वाकांक्षा जगाती है, दूसरी तरफ चिंता, डिप्रेशन और 'फेलियर फियर' का बीज बोती है। आइए, विभिन्न संदर्भों के साथ, इसकी गहराई में उतरते हैं।

'पेरेंटल एंग्जायटी' और ''प्रॉक्सी अचीवमेंट'' की साइकोलॉजी : माता-पिता के मन में सबसे बड़ा डर 'हमारा बच्चा पीछे न रह जाए'। यह 'प्रॉक्सी अचीवमेंट' कहलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, पेरेंट्स अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। बिलासपुर के मोहल्लों में देखिए-पिता जो खुद सरकारी नौकरी में फंस गए, बेटी को डॉक्टर-इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। कोचिंग जॉइन करते ही परिवार में 'सामूहिक तनाव' शुरू। सुबह का अलार्म युद्ध, रात का जोमैटो ऑर्डर, फीस की EMI सब कुछ 'बच्चे के भविष्य' के नाम पर। लेकिन मनोविज्ञान कहता है- यह ओवर-इन्वॉल्वमेंट बच्चे में 'लर्नेड हेल्पलेसनेस' पैदा कर सकता है। बच्चा सोचने लगता है 'मेरा जीवन मम्मी-पापा के कंट्रोल में है'। परिणाम? किशोरावस्था में विद्रोह या चुपके से डिप्रेशन।

बच्चों में 'परफेक्शनिज्म' और 'फोमो' (फियर ऑफ मिसिंग आउट) : नई जनरेशन को 'एसथेटिक' दुनिया आकर्षित करती है। इंस्टाग्राम पर टॉपर्स की चमकदार फोटो, कोचिंग के मोटिवेशनल रील्स। बच्चा सोचता है 'अगर मैं 95% नहीं लाया तो मैं फेल'। मनोवैज्ञानिक रूप से यह 'सोशल कंपेरिजन थ्योरी' है। कोचिंग टेस्ट सीरीज हर रविवार बच्चे को स्कोर के आधार पर रैंक देती है, जो आत्म-सम्मान को स्कोर से जोड़ देती है। परिणाम-हाई अचीवर्स में भी बर्नआउट, लो स्कोरर्स में चिंता। बिलासपुर-रायपुर कोटा के काउंसलर्स बताते हैं कि बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी क्लिनिक में 12वीं के छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है।

कोचिंग वाले का 'मोटिवेटर' रोल और कमर्शियल साइकोलॉजी : कोचिंग संस्थान अब सिर्फ टीचिंग नहीं, 'होप सेलिंग' का बिजनेस कर रहे हैं। मोटिवेशनल लेक्चर, 'आईआईटी टॉपर' की स्टोरी, दीवार पर सक्सेस चार्ट-सब कुछ 'ग्रोथ माइंडसेट' का पर्दा है, असल में 'फियर माइंडसेट' बेचा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से, बार-बार 'तुम्हें मेहनत करनी होगी' कहकर वे 'स्कैपगोट' तैयार करते हैं-अगर रिजल्ट खराब तो बच्चे की मेहनत कम, अगर अच्छा तो कोचिंग का कमाल। यह 'कॉग्निटिव डिसोनेंस' पैदा करता है। बच्चा खुद को दोषी मानने लगता है।

नई जनरेशन का 'एसथेटिक रिबेलियन' : आज के बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं, बैलेंस चाहते हैं। एसथेटिक स्लीप, फेस वॉश, जोमैटो-ये उनके 'सेल्फकेयर' के रूप हैं। कोचिंग उन्हें रट्टू बनाने की कोशिश करती है, वे 'होलिस्टिक डेवलपमेंट' की मांग करते हैं। यह 'जनरेशनल गैप' है, जो मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ाता है।

अंतिम रूप से इसमें संतुलन की जरूरत : कोचिंग संस्कृति का मनोविज्ञान हमें बताता है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन 'अंधी दौड़' खतरनाक। छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में जहां संसाधन सीमित, कोचिंग ने अवसर दिए, पर मेंटल हेल्थ की कीमत पर।

समाधान:

- स्कूलों को मजबूत करें। • कोचिंग में काउंसलिंग अनिवार्य।
- पेरेंट्स 'प्रेशर' कम करें, 'सपोर्ट' बढ़ाएं। • बच्चे को स्किल्स + खुशी दोनों दें।

भाई, पापड़ बेलना जरूरी है, लेकिन कमर टूटने तक नहीं। कोचिंग अच्छी सहायक है, मालिक नहीं। हमारे बच्चे की 85% सफलता हमें सिखाती है - अंक महत्वपूर्ण, लेकिन मानसिक शांति और परिवार का प्यार सबसे बड़ा 'सम्मान' है।

रुपये की उड़ान, घर की थकान - डिजिटल अर्थव्यवस्था में खोते आम लोग

सुबह छह बजे रमा देवी उठती हैं। चाय के लिए दूध महँगा है, सब्जी का भाव कल से दस रुपये बढ़ा है और गैस सिलेंडर फिर से बुकिंग के इंतजार में है। उनके पति सरकारी नौकरी में हैं, तनख्वाह आती है -पर महीने के अंत तक खाता खाली हो जाता है। टेलीविजन पर बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। रमा देवी चाय की चुस्की लेती हैं और सोचती हैं-'यह विकास हमारे घर कब पहुँचेगा?'

गृहिणी-अर्थव्यवस्था कीअनदेखी मुख्य धुरी

भारत में 19 करोड़ से अधिक गृहिणियाँ हैं जो बिना वेतन के देश की 'Care Economy' चलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार यदि घरेलू कार्य को आर्थिक मूल्य दिया जाए तो यह भारत की GDP में 15 से 17 प्रतिशत तक का योगदान होगा। पर यह कहीं नहीं गिना जाता। खाद्य मुद्रास्फीति की मार सबसे पहले गृहिणी झेलती है। 2024-25 में दालों की कीमत 30 प्रतिशत, खाद्य तेल 22 प्रतिशत और टमाटर-प्याज 40-60 प्रतिशत तक महँगे हुए। गृहिणी वही जादूगर है जो घटते बजट में बढ़ते परिवार का पेट भरती है-बिना किसी सरकारी मान्यता के। PM उज्ज्वला योजना और जन धन खाते अच्छी पहल हैं, पर डिजिटल साक्षरता के अभाव में लाखों गृहिणियाँ अब भी इनका पूरा लाभ नहीं उठा पातीं। *''रसोई में रोज बजट बनता है और रोज टूटता है-यही है असली अर्थशास्त्र जो किताबों में नहीं मिलता।''*

युवा पीढ़ी-सबसे बड़ा Asset या सबसे बड़ी चुनौती?

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है-65 करोड़ से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह 'Demographic Dividend' है-पर इसे भुनाने के लिए हर साल 2 करोड़ नए रोजगार चाहिए। वास्तविकता यह है कि हम मुश्किल से 70-80 लाख रोजगार सृजित कर पाते हैं। AI और ऑटोमेशन ने स्थिति और जटिल कर दी है। Nasscom की रिपोर्ट के अनुसार IT क्षेत्र में जूनियर-स्तर की 40 प्रतिशत भर्तियाँ अगले तीन वर्षों में AI द्वारा प्रतिस्थापित हो सकती हैं। BPO, डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग-जिन नौकरियों को पाने के लिए लाखों युवाओं ने इंजीनियरिंग की-वे तेजी से खत्म हो रही हैं। दूसरी ओर Gig Economy का विस्तार हो रहा है। Swiggy, Zomato, Ola, Uber – इन प्लेटफॉर्म्स पर 80 लाख से अधिक गिग वर्कर हैं। इन्हें न EPF मिलता है, न ESI, न नौकरी की सुरक्षा। 'आजाद रोजगार' के नाम पर यह असल में अनिश्चितता की जंजीर है।

मध्यम वर्ग-निचोड़ी जाती जीवनशैली

भारत का मध्यम वर्ग वह वर्ग है जो सरकारी सब्सिडी के लिए 'बहुत अमीर' और निजी सुविधाओं के लिए 'बहुत गरीब' है। Pew Research के अनुसार भारत में लगभग 9.9 करोड़ लोग 'Upper Middle Class' में हैं, जबकि कोविड के बाद 3.2 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से नीचे खिसक गए।

स्वास्थ्य खर्च, बच्चों की शिक्षा और गृह ऋण – यह तिकड़ी मध्यमवर्गीय परिवार को दोनों तरफ से दबाती है। NSSO के ताजा आँकड़े बताते हैं कि भारत में Out-of-Pocket स्वास्थ्य व्यय एशिया में सर्वाधिक है-परिवार की आय का 17 प्रतिशत तक। एक बीमारी पूरे परिवार को वित्तीय संकट में डाल देती है।

सोचिए-जब गृहिणी का श्रम अदृश्य हो, युवा की प्रतिभा बेरोजगार हो और मध्यम वर्ग का सपना EMI में कैद हो – तो 'विकसित भारत 2047' किसके लिए है? अर्थव्यवस्था तब तक अधूरी है जब तक उसकी धड़कन हर घर की रसोई तक न पहुँचे, हर युवा की आँखों में उम्मीद न जगाए और हर गृहिणी के परिश्रम को सम्मान न मिले।

-प्रभात दत्त झा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

शाला प्रवेश उत्सव के मंच पर कौन रहेगा केंद्र में-बच्चे या नेता!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ शाला प्रवेश उत्सव को लेकर सरकार ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से स्कूलों तक पहुंचकर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुका है कि नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत और विभिन्न हितग्राही योजनाओं का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए। इन निर्देशों के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि यह पहल शिक्षा को जनआंदोलन बनाने की कोशिश है या फिर स्कूलों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की रणनीति।

16 जून से 27 जून तक चलने वाले शाला प्रवेश उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत आधार है और यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि शाला प्रवेश उत्सव केवल नए विद्यार्थियों का स्कूल में नामांकन कराने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य यह भी है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं, पढ़ाई जारी रखें और बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थिति न बने। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग मांगा गया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों का स्वागत जनप्रतिनिधियों के हाथों कराया जाए। साथ ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण जैसे कार्यक्रमों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। विभाग का मानना है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से अभियान को व्यापक सामाजिक समर्थन मिलेगा और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

सरकार इस अभियान को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं से भी जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री विद्यालय योजना, प्रस्तावित विवेकानंद विद्यालयों और नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्कूलों के आधुनिकीकरण का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, मध्यान्ह भोजन और बालिकाओं को सरस्वती साइकिल जैसी सुविधाएं भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, लगातार जारी हो रहे निर्देशों के बीच राजनीतिक चर्चा भी कम नहीं है। कई लोगों का मानना है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से अभियान को मजबूती मिलेगी और समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं कुछ लोगों का सवाल है कि क्या स्कूलों में बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी शिक्षा के मूल उद्देश्य पर हावी तो नहीं हो जाएगी।

फिलहाल सरकार इसे जनभागीदारी का अभियान बता रही है और उम्मीद जता रही है कि इससे नामांकन बढ़ेगा तथा ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूलों तक लाने में सफलता मिलेगी। अब सबकी नजर 16 जून से शुरू होने वाले शाला प्रवेश उत्सव पर है, जहां यह स्पष्ट होगा कि अभियान की पहचान शिक्षा के महोत्सव के रूप में बनती है या फिर स्कूलों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी इसकी सबसे प्रमुख तस्वीर बनकर उभरती है।

अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे ने प्राचार्य पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, महिला आयोग में शिकायत

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे के साथ राजकुमार कॉलेज में कथित दुर्व्यवहार का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस घटना को करीब दो से ढाई वर्ष बीत चुके हैं, जबकि यह मामला 22 नवंबर 2023 से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में लंबित है और इसकी सुनवाई जारी है।

जानकारी के अनुसार, राजकुमार कॉलेज में आयोजित एक हॉकी प्रतियोगिता के दौरान नीता डुमरे को 'कमेटी सुपरविजन' की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैच के दौरान अंपायर के फैसले को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद खेल को रोकना पड़ा। आरोप है कि इसी दौरान कॉलेज प्रशासन की ओर से उन्हें बुलाया गया और और राकुमार कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया।

घटना के बाद नीता डुमरे ने कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि उनके साथ की गई अभद्रता से न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उनका अपमान भी हुआ।

गौरतलब है कि नीता डुमरे छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। खेल क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए यह मामला प्रदेश के खेल जगत में भी चर्चा का विषय बना रहा है। मामला 22 नवंबर 2023 से महिला आयोग में विचाराधीन है। आयोग द्वारा समय-समय पर दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है, लेकिन प्रिंसिपल उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

झाड़फूंक के बहाने ब्रेनवॉश कर युवती से रेप

सरगुजा। अंबिकापुर में झाड़फूंक के नाम पर लोगों को झांसा देने वाले ढोंगी बाबा ने 24 साल की युवती के साथ रेप किया है। आरोपी ने युवती को अच्छा रिश्ता आने और नौकरी लगने का लालच दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 जून की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच अमित गोस्वामी नाम का व्यक्ति उनकी कॉलोनी में पहुंचा। उसने खुद को प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला बताया। लोगों की समस्याएं दूर करने और झाड़फूंक करने का दावा कर रहा था।

महिलाएं बोलीं- नहीं चाहिए महतारी वंदन

घर बर्बाद हो रहे, शराब दुकान बंद करो

- आबकारी मंत्री ने कहा था- इसी आय से चल रही योजनाएं

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के दरिमा में खोले गए अंग्रेजी शराब दुकान के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने कहा कि, शराब दुकान की आय से महतारी वंदन का पैसा दिया जा रहा है, तो हमें महतारी वंदन नहीं चाहिए। उन्होंने सोमवार को सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में शराब दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया है, वर्ना महिलाएं आंदोलन करेंगी।

इससे पहले आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा था कि, आबकारी विभाग से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल महतारी वंदन योजना, एमएससी और आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाने में किया जा रहा है। जिसके बाद महिलाओं ने कहा कि, ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, जिससे किसी का घर बर्बाद हो। दरअसल, सरगुजा में आबकारी विभाग ने दरिमा में एयरपोर्ट के बाहर गांव में अंग्रेजी शराब दुकान खोल दिया है। जिसके विरोध में दूसरी बार महिलाएं अंबिकापुर पहुंचीं। एक सप्ताह पहले महिलाओं ने कलेक्टर को जनदर्शन में शराब दुकान हटाने का आवेदन दिया था। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाओं ने सोमवार को फिर से अंबिकापुर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 3 दिन में शराब दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया है। नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

महिलाएं बोलीं- ऐसे पैसों से हमें योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए

आशा दास ने कहा कि, आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने बयान में कहा है कि शराब बेचने से जो आय होती है, उससे महतारी वंदन और बाकी योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है। आशा दास ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि शराब के पैसे से महतारी वंदन का पैसा दिया जा रहा है, तो हमें महतारी वंदन का पैसा नहीं चाहिए। हम शराब दुकान नहीं हटाने तक प्रदर्शन करेंगे। सरकार यदि गरीब स्थिति में है, तो वो शराब न बेचे। योजना भी न चलाए। क्योंकि किसी के हाय के पैसे से किसी का भविष्य उज्जवल नहीं होता। किसी का घर उजाड़कर किसी का घर नहीं बसता है। मंत्री जी शराब से मिलने वाले आया का आंकड़ा लगा लिए, लेकिन मंत्री जी यह आंकड़ा भी लगाए कि, उस शराब को पीने से कितने बहनों का घर उजड़ा। कितनी माताएं अपने बेटे के लिए तरसीं। कितने युवाओं का एक्सीडेंट हुआ। कितने लोगों का लीवर और किडनी खराब हो गए। कितनी महिलाओं को टेंशन में अटैक आया, कितनों ने फांसी लगा ली।

किसी भी शर्त पर शराब दुकान नहीं चलने देंगे

महिलाओं ने कहा कि, पहले इस इलाके के युवा सरकारी भर्तियों में चयनित हो रहे थे। शराब बिकने से आसानी से युवाओं को शराब मिलने लगा है। जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। महिलाओं ने कहा कि, किसी भी शर्त पर वे दरिमा में शराब दुकान नहीं चलने देंगे।

शराब दुकान हटाने तक देंगे धरना

महिलाओं ने कहा कि, शराब दुकान को 3 दिन में नहीं हटाया जाता है, तो वे आंदोलन करेंगी। शराब दुकान हटाने तक आंदोलन चलेगा। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर करीब 30 महिलाएं सरगुजा कलेक्टर के पास पहुंची थीं।

नकली मंगलसूत्र पर मंत्री की सफाई: 7 हजार में असली गहना कैसे दें?

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नवविवाहित दुल्हनों को दिए गए मंगलसूत्र के नकली निकलने के मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पहली बार खुलकर सफाई दी है। मंत्री ने स्वीकार किया है कि दुल्हनों को दी गई चेन आर्टिफिशियल थी। उनका तर्क है कि योजना में उपहार सामग्री के लिए निर्धारित बजट इतना कम है कि उसमें चांदी की असली चेन उपलब्ध कराना संभव नहीं था।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कपड़े, श्रृंगार सामग्री और उपहार के लिए प्रति जोड़ा केवल 7 हजार रुपए का प्रावधान है। इसी राशि में पायल, बिछिया, श्रृंगार सामग्री समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं भी खरीदनी होती हैं। ऐसे में असली चांदी की चेन देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था, इसलिए उपहार सामग्री में आर्टिफिशियल चेन शामिल की गई।

यह बयान ऐसे समय आया है जब एमसीबी जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल कई दुल्हनों ने उन्हें दिए गए मंगलसूत्र के नकली होने की शिकायत की है। मामला तब सामने आया जब विवाह के कुछ महीनों बाद कई महिलाओं के मंगलसूत्र काले पड़ने लगे। संदेह होने पर उन्होंने स्थानीय ज्वेलर्स से इसकी जांच कराई, जहां पता चला कि गहना न तो सोने का था और न ही चांदी का, बल्कि गिलट धातु से तैयार किया गया था।

पूरा मामला 10 फरवरी को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह से जुड़ा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड के चनवारीडांड में 184 जोड़ों का विवाह कराया गया था। विवाह समारोह के दौरान दुल्हनों को मंगलसूत्र सहित अन्य उपहार सामग्री प्रदान की गई थी। कुछ महीनों बाद उपहार में दिए गए गहनों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे और मामला सार्वजनिक हो गया।

इस बीच कुछ दुल्हनों ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि विवाह सामग्री और मंगलसूत्र के नाम पर उनसे 15-15 हजार रुपए तक वसूले गए। इन आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया। हालांकि प्रशासनिक जांच में संबंधित अधिकारियों को फिलहाल दोषमुक्त बताया गया है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना में पहले अनियमितताओं और कमीशनखोरी की शिकायतें मिलती थीं। इसी वजह से सरकार ने अधिकांश राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू की। वर्तमान में योजना के तहत प्रति जोड़ा 50 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं। इसमें लगभग 8 हजार रुपए विवाह आयोजन, भोजन और टेंट व्यवस्था पर खर्च होते हैं, जबकि 36 हजार रुपए सीधे दुल्हन के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किए जाते हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार गहने और अन्य जरूरी सामग्री खरीद सकते हैं। हालांकि मंत्री की सफाई के बावजूद कई सवाल अब भी कायम हैं। यदि उपहार में दी जाने वाली चेन आर्टिफिशियल थी तो इसकी जानकारी लाभार्थियों को पहले क्यों नहीं दी गई? क्या उपहार सामग्री की गुणवत्ता और प्रकृति को लेकर कोई स्पष्ट मानक तय नहीं थे? और यदि योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह सहायता देना है, तो क्या प्रतीकात्मक गहनों को असली बताकर वितरित करना उस उद्देश्य की भावना के अनुरूप माना जा सकता है?

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का व्हाट्सएप हैक

मदद के नाम पर ऐंठे 12 लाख

रायपुर। साइबर अपराधियों ने इस बार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को निशाना बनाकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। उनके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर अपराधियों ने परिचितों और शुभचिंतकों से आर्थिक मदद मांगी और कुछ ही घंटों में करीब 12 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।

जानकारी के अनुसार रविवार को डॉ. सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट अचानक हैक हो गया। अकाउंट पर कब्जा करने के बाद साइबर ठगों ने उनकी प्रोफाइल फोटो और पहचान का इस्तेमाल करते हुए उनके संपर्क सूची में मौजूद लोगों को संदेश भेजना शुरू कर दिया। संदेश में लिखा गया था कि उनका यूपीआई काम नहीं कर रहा है और किसी जरूरी काम के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता है।

राज्य के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर होने के कारण अधिकांश लोगों ने संदेश की सत्यता पर संदेह नहीं किया। रविवार होने और मामला आपात स्थिति का समझकर कई परिचितों ने बिना फोन पर पुष्टि किए ही मैसेज में दिए गए बैंक खातों और यूपीआई आईडी पर रकम भेज दी। अलग-अलग लोगों से भेजी गई राशि मिलाकर ठगों ने करीब 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली।

मामले का खुलासा तब हुआ जब पैसे ट्रांसफर करने वाले कुछ लोगों ने बाद में डॉ. सलीम राज से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। फोन आने पर उन्हें पता चला कि उनके नाम से फर्जी संदेश भेजकर लोगों से रकम मांगी जा रही है। इसके बाद उन्होंने तत्काल अपने स्तर पर लोगों को सतर्क किया और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही डॉ. सलीम राज ने रायपुर पुलिस और साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर साइबर विशेषज्ञों ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस हैक किए गए अकाउंट की तकनीकी पड़ताल कर रही है, वहीं जिन बैंक खातों और यूपीआई आईडी में रकम ट्रांसफर की गई है, उन्हें फ्रीज कराने के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क किया गया है।

प्रारंभिक जांच में यह मामला सोशल इंजीनियरिंग और पहचान का दुरुपयोग कर की गई साइबर ठगी का माना जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप अकाउंट किस तरीके से हैक किया गया और इसके पीछे सक्रिय गिरोह का नेटवर्क कहां से संचालित हो रहा है।

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी अब आम लोगों के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।

प्रकाशक एवं मुद्रक सुभाष मिश्रा द्वारा स्वामी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि. के लिए मिशन मीडिया प्रा.लि., रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं एचआईजी 27 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित।
प्रधान संपादक- सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक-भालचंद्र जोशी, स्थानीय संपादक-विवेक मिश्रा, आरएनआई रजि. नं.-52143/91, * पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।